● **मिथिलेश कुमार**

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नियुक्तियों को लेकर एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि सत्यापन के लिए भेजे गए 41 कर्मचारियों में से 40 के डिप्लोमा प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए हैं। केवल एक कर्मचारी का प्रमाणपत्र ही संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा वैध और वास्तविक बताया गया है। इस खुलासे के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और पूरे मामले ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं दस्तावेज सत्यापन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

☞ **मामला :-** Pacific Academy of Higher Education and Research University, उदयपुर के नाम पर प्रस्तुत डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाणपत्रों से जुड़ा है। भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने नियुक्त कर्मचारियों द्वारा जमा किए गए प्रमाणपत्रों की सत्यता की पुष्टि के लिए विश्वविद्यालय से आधिकारिक सत्यापन कराया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो तथ्य सामने आए, वे विभागीय अधिकारियों के लिए भी अप्रत्याशित थे।

☞ **विश्वविद्यालय ने खोली पोल :-** विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय से 27 फरवरी 2026 को जारी पत्र संख्या 4676 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सत्यापन के लिए भेजे गए 41 अभ्यर्थियों में केवल क्रम संख्या-13 पर अंकित दिलीप पासवान (Enrollment No.- PU12-5788) का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री और अंकपत्र विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत जारी किया गया है। विश्वविद्यालय ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि शेष 40 अभ्यर्थियों के नाम से न तो कोई डिग्री जारी की गई और न ही कोई अंकपत्र। अर्थात जिन प्रमाणपत्रों के आधार पर इन लोगों ने सरकारी नौकरी प्राप्त की, वे विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं हैं। विश्वविद्यालय ने उन्हें फर्जी और जाली दस्तावेज बताया है।

☞ **अब विभाग ने शुरू की कार्रवाई :-** विश्वविद्यालय की रिपोर्ट मिलते ही भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय हरकत में आ गया। विशेष कार्य पदाधिकारी (भू-अभिलेख एवं परिमाप) ने पत्रांक-2243 जारी कर सभी 40 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित कर्मचारियों ने फर्जी अथवा कूटरचित डिप्लोमा प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी सेवा प्राप्त की है। सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-मेल के माध्यम से अपना पक्ष रखें तथा यदि उनके पास कोई वैध दस्तावेज या साक्ष्य हो तो उसे भी प्रस्तुत करें। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि नियुक्ति फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर हासिल की गई थी। ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मियों की सेवा समाप्त करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध भारतीय कानून के अनुसार आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

☞ **कौन-कौन हैं नोटिस पाने वाले कर्मचारी :-** नोटिस पाने वालों में भूषण भारती, अमित कुमार, ललन कुमार, राकेश कुमार कापरी, चंचला कुमारी, मनीष कुमार, राजीव कुमार, नरेश कुमार, दीपक कुमार, चंद्रकांत कुमार राय, सुधांशु शेखर, अमर कुमार, अमरेंद्र कुमार, प्रिया कुमारी, सुभद्रा सुमन, नितीश कुमार, अभिषेक कुमार, मंटू कुमार, रूपा कुमारी, प्रियंका कुमारी, दीपक कुमार, अनुज कुमार, रामप्रवेश कुमार, मंटू कुमार, पंकज स्वराज, निशिकांत कुमार, ओमप्रकाश चौधरी, मुंचुन कुमार, ऋषु राकेश, आशुतोष कुमार, अभिषेक कुमार, नितीश कुमार, रोहित कुमार, मुकेश कुमार, एमडी सरफराज रिजवान, दिव्या राव भारती, रविंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, सुबोध कुमार तथा नितीश कुमार शामिल हैं।

☞ **भर्ती प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल :-** यह मामला केवल 40 कर्मचारियों तक सीमित नहीं माना जा रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया में शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन अनिवार्य माना जाता है, तब इतने बड़े पैमाने पर कथित फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्ति कैसे हो गई? क्या नियुक्ति के समय प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं कराया गया? यदि कराया गया था तो फर्जी प्रमाणपत्र कैसे मान्य हो गए? यदि सत्यापन नहीं हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों का जवाब अब विभागीय जांच और आगे की कार्रवाई से ही सामने आएगा।

☞ **क्या होगी आगे की कार्रवाई? :-** विभागीय सूत्रों के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों के जवाब मिलने के बाद उनका परीक्षण किया जाएगा। यदि उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया और विश्वविद्यालय की रिपोर्ट सही साबित होती है, तो सबसे पहले उनकी सरकारी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद फर्जी दस्तावेज तैयार करने, उनका उपयोग कर सरकारी नौकरी प्राप्त करने तथा सरकारी रिकॉर्ड में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आरोप में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर जाली शैक्षणिक प्रमाणपत्र का उपयोग कर सरकारी नौकरी प्राप्त की है और यह आरोप जांच में सिद्ध हो जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड कानून के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी और कूटरचना से संबंधित धाराओं में कार्रवाई संभव है। हालांकि अंतिम कार्रवाई जांच और विधिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

☞ **अन्य विभागों में भी हो सकती है जांच :-** इस प्रकरण के सामने आने के बाद यह चर्चा भी तेज हो गई है कि राज्य सरकार अन्य विभागों में नियुक्त कर्मचारियों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का भी व्यापक सत्यापन करा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो कई और मामलों के सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक हलकों में यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे सरकारी भर्ती प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नियुक्ति से पहले डिजिटल सत्यापन, विश्वविद्यालयों से सीधे ऑनलाइन प्रमाणीकरण तथा दस्तावेजों की बहुस्तरीय जांच की व्यवस्था को और मजबूत करना होगा।

☞ **पूरे मामले पर सबकी निगाहें :-** फिलहाल सभी 40 कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि संबंधित कर्मचारी क्या जवाब देते हैं और विभाग उनकी सफाई को किस आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करता है। यदि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट और विभागीय जांच में आरोप पुष्ट होते हैं, तो यह बिहार में फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नियुक्ति से जुड़े सबसे बड़े मामलों में से एक साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में इस मामले की जांच और विभागीय कार्रवाई कई महत्वपूर्ण तथ्यों से पर्दा उठा सकती है।●

पिपरा पुल की बदहाली

टूटा पुल, अधूरा विकास और, टूटता जनविश्वास

तीन साल से इंतजार, आखिर कौन जिम्मेंदार?

● मुकेश कुमार

विकास के बड़े-बड़े दावे, चुनावी मंचों से किए गए वादे और जनता की सेवा की कसमें, क्या इन सबका कोई अर्थ बचता है जब एक टूटा हुआ पुल वर्षों तक अपनी बदहाली की कहानी सुनाता रहे? पटना जिले के फतुहा विधानसभा क्षेत्र के अंचल संपतचक अंतर्गत पिपरा, डोमनचक, खैराटाली, सेदानीचक और शेखपुरा गांवों को रामकृष्ण नगर बाईपास से जोड़ने वाला पिपरा पुल आज क्षेत्र की बदहाल व्यवस्था और अधूरे विकास का प्रतीक बन चुका है। वर्ष 2023 में पुल टूटने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही नया पुल बन जाएगा, लेकिन तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह उम्मीद अधूरी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पुल निर्माण के लिए कई बार टेंडर जारी हुए, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उन्हें रद्द कर दिया गया। फिर दोबारा टेंडर निकाला गया, लेकिन परिणाम वही रहा। इस बीच नाला निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जो आज तक अधूरा पड़ा है। सड़क निर्माण का भी कोई स्पष्ट अता-पता नहीं है। लोकतंत्र में जनता केवल वोट देने वाली भीड़ नहीं होती; वही लोकतंत्र की असली मालिक होती है। यदि वर्षों तक एक पुल नहीं बन पाता, सड़कें जर्जर रहती हैं और नालियां

सड़क पर बहती रहती हैं, तो जनता यह सवाल पूछने के लिए विवश होगी कि आखिर विकास के दावे किसके लिए किए जाते हैं? ग्रामीण बताते हैं कि एक समय पुल निर्माण का कार्य शुरू भी हुआ था। कुछ शुरुआती गतिविधियों के बाद काम अचानक बंद हो गया। अब स्थिति यह है कि नया पुल बनाने के बजाय टूटे हुए पुल के हिस्से को मिट्टी, ईंट और पत्थर डालकर भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसे देखकर ग्रामीणों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर सरकार, संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि करना क्या चाहते हैं? क्या यह स्थायी समाधान है या केवल अस्थायी दिखावा?

पिपरा से रामकृष्ण नगर बाईपास तक जाने वाली सड़क की हालत बेहद खराब है। जगह-जगह गहरे गड्ढे, सड़क पर बहती नालियां और बरसात में कीचड़ से भरे रास्ते लोगों की मजबूरी बन चुके हैं। रोज इसी रास्ते से स्कूली बच्चे, किसान, मजदूर, मरीज, महिलाएं और नौकरीपेशा लोग जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन हालात जस के तस हैं।

ग्रामीणों में अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर गहरी नाराजगी दिखाई देती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फतुहा विधानसभा क्षेत्र

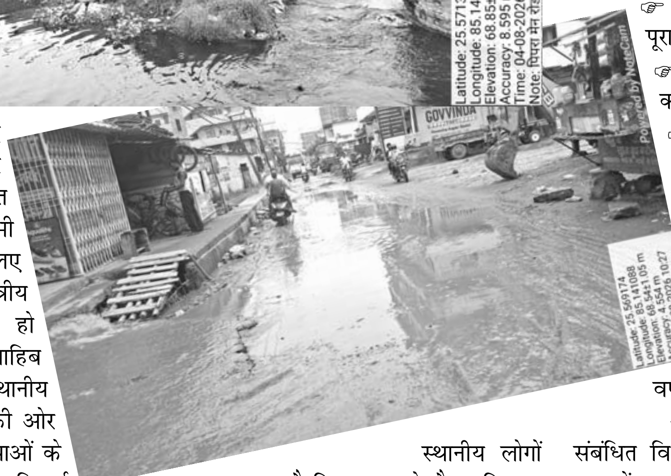

से लगातार चार बार निर्वाचित राजद विधायक ने क्षेत्र की इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए अपेक्षित पहल नहीं की। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आम नागरिकों के लिए उनसे संपर्क करना कठिन है और क्षेत्रीय समस्याओं पर पर्याप्त संवाद नहीं हो पाता। इसी प्रकार यह क्षेत्र पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि सांसद की ओर से भी इस इलाके की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए अपेक्षित सक्रियता दिखाई नहीं दी। उनका कहना है कि चुनाव के समय नेताओं के लंबे काफिले गांव तक पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्षेत्र की समस्याएं फिर उपेक्षित रह जाती हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान विकास के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। उनका मानना है कि यदि एक पुल और मुख्य सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी वर्षों तक इंतजार करना पड़े, तो लोकतंत्र में जनता का विश्वास कमजोर होना स्वाभाविक है। पिपरा का टूटा पुल आज केवल कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि टूटते जनविश्वास का प्रतीक बन चुका है। यह पुल केवल एक टूटा हुआ ढांचा नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुस्ती, योजनाओं की धीमी गति और जनता की बढ़ती निराशा का प्रतीक बन चुका अब यह सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर निर्भर है कि वे इस भरोसे को फिर से जोड़ते हैं या इसे और टूटने देते हैं।

❖ **जनता पूछ रही है :-**

☞ आखिर पिपरा पुल का निर्माण कब पूरा होगा?

☞ बार-बार टेंडर रद्द होने के पीछे क्या कारण हैं?

☞ शुरू हुआ निर्माण कार्य बीच में क्यों रोक दिया गया?

☞ क्या मिट्टी, ईट और पत्थर से पुल भर देना ही समाधान है?

☞ सड़क और जलनिकासी की समस्या कब दूर होगी?

☞ आखिर जनता अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए और कितने वर्षों तक इंतजार करेगी?

अब समय आ गया है कि सरकार, संबंधित विभाग, जनप्रतिनिधि और प्रशासन इन सवालों का स्पष्ट उत्तर दें। क्योंकि लोकतंत्र में जनता केवल वोट देने के लिए नहीं होती, बल्कि उसके जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधाजनक बनाना ही जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।●

जब अपराध रुक नहीं रहा तो पुलिस पर खर्च क्यों?

● **डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह**

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि राज्य में अपराध की आग लगातार भड़क रही है। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार और गोलीबारी की घटनाएँ रोज अखबारों की सुर्खियाँ बन रही हैं। ऐसा लगता है जैसे अपराधियों के मन से कानून का डर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। सड़कों पर खून बह रहा है, घरों में मातम पसरा है और सरकार केवल बैठकों, घोषणाओं और दावों में व्यस्त है। जब अपराध नहीं रुक रहा, निर्दोष लोगों की लाशें लगातार गिर रही हैं, तब जनता के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर सरकार और पुलिस पर करोड़ों रुपये खर्च क्यों किए जा रहे हैं? यदि सुरक्षा देने वाली व्यवस्था ही असफल है, तो यह खर्च जनता के टैक्स की बर्बादी नहीं तो और क्या है? हर दिन किसी जिले से हत्या, कहीं व्यापारी से लूट, कहीं महिला से दुष्कर्म, कहीं युवक की गोली मारकर हत्या, कहीं अपहरण, ऐसी खबरें आम हो चुकी हैं। अपराध अब घटना नहीं, व्यवस्था की पहचान बनता जा रहा है। सरकार को अब जवाब देना होगा कि आखिर कब तक जनता भय के साये में जीती रहेगी? कब तक माताओं की गोद सूनी होगी? कब तक बच्चों के सिर से पिता का साया उठता रहेगा? यदि अपराध पर लगाम नहीं लगती, तो जनता का आक्रोश सड़कों पर उतरना तय है। मुजफ्फरपुर में माँ और दो मासूम की हत्या हुई। हलवाई संतोष की पत्नी रीता देवी 25 साल, तीन साल की बेटी वैष्णवी और सात माह का दुधमुँहा रुद्र। तीनों के गले में एक ही लाल फीते का फंदा लिपटा था। भागलपुर में नगर परिषद कार्यालय में कृष्ण कुमार की हत्या कर दी गई। धनरूआ में छत पर सोई बच्ची के पेट में गोली लगी। वह माँ के साथ शादी में आई थी। पुत्री की पहचान सौम्या कुमारी के रूप में हुई। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने बिहार के मुख्यमंत्री से कहा कि यदि आपको अपराध रोकना है तो प्रधानमंत्री मोदी से हरेक जिले के लिए पटना के पूर्व एसपी किशोर कुणाल की तरह तथा हरेक थाना के लिए फतुहा के पूर्व थाना प्रभारी केके साहू, रघुनाथ सिंह की तरह अधिकारी माँगें। या दोनों की तरह पुलिस अधिकारी बनाने के लिए गुरुकुल स्कूल में शिक्षा देनी होगी।●

मसौढ़ी एसडीपीओ ने थानाध्यक्षों को दिये कई निर्देश

● अमित कुमार/श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा मसौढ़ी का पुलिस अनुमंडल की कमान फिलहाल राघव दयाल के हांथों में है। जनता के प्रति विनम्र स्वभाव तथा अपराधियों के लिए सख्त रूख अपनाने वाले एसडीपीओ-1 राघव दयाल कर बिहार पुलिस में सेवा के 30 वर्षो से अधिक हो चुका है और वह एक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ पुलिस के तौरपर वर्षों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। मसौढ़ी अनुमंडल में कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा लंबित कांडो के त्वरित निष्पादन को लेकर बीते दिनों अनुमंडल पुलिस कार्यालय में समीक्षा बैठक की गयी। इसकी अध्यक्षता एसडीपीओ-1 राघव दयाल ने की, जिसमें सभी थानाध्यक्ष और पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में एसडीपीओ ने गंभीर मामलों के अनुसंधान में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का अधिकतम उपयोग कर अनुसंधान को मजबूत बनाया जाये। एसडीपीओ ने थानाध्यक्षों से कहा कि थानों में आने वाले लोगों की शिकायतों का त्वरित और संवेदनशील तरीके से समाधान करें।

गौरतलब है कि मसौढ़ी एसडीपीओ-1 राघव दयाल इससे पूर्व भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे बिहार के जयनगर में एसडीपीओ के पद पर पदस्थापित थे। राघव राजधानी पटना में कई वर्षों तक अपनी सेवा दे चुके हैं और बीते 19 जुलाई को पुलिस मुख्यालय पटना से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर मसौढ़ी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1 के तौरपर कार्यभार संभाला है। राघव दयाल का मानना है कि पुलिस पब्लिक संवाद से इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाया जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को पब्लिक फ्रेंडली रहने को कहा ताकि अपराधियों पर नकेल कसा जा सके। उन्होंने वाहन चेकिंग, रात्रि गस्ती, फरार एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध हथियार, शराब एवं मादक पदार्थों की बरामदगी पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। ●

तय समय में करायें काम : एसडीएम

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

मसौढ़ी अनुमंडल पदाधिकारी धनराज कुमार पुरानी बाइपास रोड पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य की प्रगति और उसमें आ रही बाधाओं का जायजा लेने अधिकारियों की टीम के साथ निर्माण स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कर्पूरी चौक से रेलवे पुल मालिकाना रोड तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, सीओ ऋषिकेश कुमार, एसडीओ धनराज कुमार, अमीन रामाधार समेत अन्य अधिकारी और सरकारी कर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सड़क के दोनो किनारो पर चल रहे नाली निर्माण कार्य में आ रही तकनीकी व स्थानीय समस्याओं का भी जायजा लिया।

एसडीएम ने बताया कि कर्पूरी चौक के पास कुछ स्थानीय विवाद और अन्य कारणों से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस मौके पर वर्तमान स्थिति का अवलोकन कर समस्याओं पर चर्चा की गई ताकि निर्माण कार्य बिना किसी अनावश्यक बाधा के आगे बढ़ सके। निरीक्षण के दौरान कर्पूरी चौक स्थित शिव मंदिर सहित मार्ग में पड़ने वाले अन्य मंदिरों की स्थिति का भी अवलोकन किया गया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा सम्मान करते हुए ऐसा समाधान निकाला जाएगा, जिससे निर्माण कार्य भी प्रभावित न हो और धार्मिक स्थलों को लेकन किसी तरह की परेशानी भी न हो। ●

अपराधमुक्त मसौढ़ी के लिए दो नये ओपी का उद्घाटन

● **अमित कुमार/श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव**

बिहार अपनी पहचान के दो चेहरे रखती है-एक तो धर्मस्थली, ज्ञानस्थली, महापुरूषों की जन्मभूमि, शिक्षा का विश्वप्रख्यात केन्द्र तो वही इसकी दूसरी पहचान अपराध, दुष्कर्म, अपहरण, जातिवादी नरसंहार और नक्सलवाद। इन सबमें बिहार ने नक्सलवाद में देश के अन्य राज्य झारखण्ड, छत्तीसगढ़, तेलांगना (जो बाद में बना) के साथ ही अपना नाम ऐसे बनाया, जो इस प्रदेश के लिए कोढ़ से कम ना था। नक्सली गतिविधियों में हमेशा रेड एलर्ट पर बिहार का जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, कैमूर के साथ ही राजधानी पटना से सटा मसौढ़ी भी रहा। हालांकि बिहार को अब नक्समुक्त कहा जा सकता है! 2011 के जहानाबाद जेल ब्रेक काण्ड को छोड़ दें तो उसके बाद नक्सली घटनाएं ना के बराबर ही रही। कड़ी मशक्कत और सुशासन का असर इस पर पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए वो सबकुछ किया, जिससे वह सफल हो पाये। किंतु क्षेत्र में नक्सली घटना ना होना अपनी जगह है पर क्षेत्र आज भी इस भय में जी रहा है। बहरहाल, नक्सलवाद अब अपराध का रूप ले रखा है और यहां छोटी-बड़ी अपराधिक घटनाएं घटती देखी जा सकती है। ये कहना भी सही है कि बिहार पुलिस अब अत्याधुनिक हथियारों से लैश है और पुलिस पेट्रोलिंग इसे कम करने में कारगर साबित हो रहे हैं। ज्ञात हो कि मसौढ़ी, जिसे तारेगना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि महान खगोलविद् आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद् और गणितज्ञ थे, इनका और तारेगना गांव का खगोलीय और अंतरिक्ष भौतिकी से गहरा संबंध है। तारेगना खगोल शास्त्र के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट की कर्मस्थली है। आर्यभट्ट ने तारेगना डीह यानी टीले पर अपनी प्रयोगशाला बनाकर खगोलीय अध्ययन किया था। आज इस मसौढ़ी या यूं कहे तारेगना की जनता के लिए आपराधिक गतिविधि कम करने की दिशा में 10 अगस्त को दो नये आउटपोस्ट खोला गया।

गौरतलब कि राजधानी में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में पटना पुलिस ने ये अहम पहल की है। 10 अगस्त 2026 को नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, पटना सुश्री शैलजा ने मसौढ़ी थाना क्षेत्र में नदौल ओपी और छाता ओपी का विधिवत उद्घाटन किया। पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो नए पुलिस आउटपोस्ट-नदौल ओपी और छाता ओपी का विधिवत उद्घाटन कर उन्हें जनता की सेवा में समर्पित कर दिया गया। दोनों नए पुलिस आउटपोस्ट का विधिवत उद्घाटन नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), पटना सुश्री शैलजा द्वारा किया गया। इस अवसर पर मसौढ़ी एसडीपीओ-1 राघव दयाल के साथ ही पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। फीता काटकर नए ओपी का शुभारंभ करने के बाद एसपी पूर्वी ने परिसर का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए एसपी पूर्वी सुश्री शैलजा ने नए ओपी की उपयोगिता और पुलिस की प्राथमिकताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन नए पुलिस आउटपोस्ट के शुरू होने से इलाके में पुलिस बल की सक्रियता, गश्त और निगरानी व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। अब असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर सीधी नजर रखी जा सकेगी। नए ओपी के संचालन से स्थानीय नागरिकों को सुरक्षा का बेहतर माहौल मिलेगा। अब किसी भी आपात स्थिति या घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच सकेगी, जिससे आम लोगों को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध हो सकेगी। इससे दूरस्थ थानों तक जाने की मजबूरी से भी स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वही एसडीपीओ-1 राघव दयाल ने भेंटवार्ता के दौरान इस संदर्भ में कहा कि नदौल और छाता क्षेत्र में लंबे समय से पुलिस चौकी की मांग की जा रही थी। पटना पुलिस की इस सराहनीय पहल से नदौल, छाता और आसपास के ग्रामीण इलाकों में विधि-व्यवस्था को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए पुलिस आउटपोस्ट के जरिए क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी और निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को बेहतर सुरक्षा और त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध करायी जा सकेगी और इससे नदौल और छाता क्षेत्र में विधि-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। वही नये पुलिस आउटपोस्ट खुलने से स्थानीय ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर काफी उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला।●

ओल्ड फ्रेंड्स क्लब फुटबॉल मसौढ़ी को मिला नया अध्यक्ष

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

मसौढ़ी फुटबॉल क्लब के पुराने दोस्तों की बैठक हुई। इस बैठक में सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने सरोज भारती के रूप में नए अध्यक्ष का चुनाव किया। क्लब के सचिव मुकुल कुमार, संयुक्त सचिव इम्तियाज अहमद और नये सदस्यों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत किया. मसौरही स्थित फ्रेंड्स क्लब फुटबॉल के नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना होगी और वह युवाओं को फुटबॉल की ओर प्रोत्साहित करेंगी। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभ्यास से ही व्यक्ति परिपूर्ण बनता है। इसलिए, अभ्यास पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने सदस्यों से कहा कि क्लब को और अधिक मजबूत और सक्रिय होना चाहिए, तभी खेल गतिविधियां बेहतर होंगी। स्थानीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रहे। इस मौके पर सचिव मुकुल कुमार, संयुक्त सचिव इम्तियाज अहमद, महिला सचिव ज्योति कुमारी, शशि सिंह, सुएब अहमद, तनवीर अहमद, पूर्व सरपंच राजकुमार, धनंजय कुमार, चंदन कुमार मौजूद थे. ●

बिहार का वृंदावन है विजयपुरा

● मनोज कुमार गोस्वामी

जब भी सनातन की बात होगी, वहां बिहार का स्थान सर्वोपरी होगा। चाहे प्रभु श्रीराम का शिक्षा दीक्षा स्थान की बात हो या माता सीता का जन्मस्थान का। गौतम बुद्ध को ज्ञान भी इसी बिहार में प्राप्त हुआ और महावीर ने यहां जन्म लिया। शक्तिपीठ से लेकर बाबा भोलेनाथ का देवघर (झारखण्ड) में चढ़ता गंगाजल भी इसी बिहार से उठता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो धर्म सनातन को बिहार ने खुद में समाया हुआ है। धार्मिक मूल्यों के साथ ही रोजगार और पर्यटन में यह काफी मददगार भी हैं। वैसे में राजधानी पटना के निकट एक ऐसा तीर्थस्थान है, जिसकी मान्यता है कि यहां पर भगवान श्रीकृष्ण आज भी बांसुरी बजाते हैं और राधा-रानी के साथ रास रचाते हैं। इसलिए यहां के ग्रामीण इसे दूसरा वृंदावन भी कहते हैं। यह स्थान पटना जिला के धनरूआ थाना अंतर्गत विजयपुरा ग्राम में स्थित है। बता दें कि यहां तीन महीनों तक वृंदावन के कलाकारों द्वारा रासलीला का आयोजन होता है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्य पर्यटन को बढ़ावा देते हुए पर्यटनीय स्थल के विकास में अपनी पहल दिखाते हैं, जिससें उन्हे करोड़ों रूपयों का राजस्व मिलता है और वह राजस्व अन्य महत्वपूर्ण विभागों के विकास में मदद करता है। किंतु बड़े ही गंभीरता भरा प्रश्न है कि बिहार के कई ऐसे पर्यटन व तीर्थ स्थान हैं जिनपर सरकार की नजर नहीं है या फिर उसे नजरअंदाज कर रही है। उनमें एक नाम विजयपुरा के ठाकुर स्थान भी शामिल है। इसके विकास और पर्यटन की दृष्टि से मान्यता न मिलने से

स्थानीय विकास तो अवरूद्ध है ही, सरकार को भी यहां से कोई राजस्व नहीं आ रहा। यदि पर्यटन विभाग और धार्मिक न्यास इस दिशा में पहल करते हुए विजयपुरा ठाकुर स्थान की जांच-पड़ताल कराकर इसे पर्यटन व तीर्थस्थान बनाती है तो राजस्व भी आयेगा और इस धार्मिक स्थल, जिसकी मान्यता है कि श्रीकृष्ण यहां पर आज भी बांसुरी बजाते हैं को पहचान मिलेगी। पर्यटक यहां पहुंचेंगे। यहा के ग्रामीणों की मांग है कि विजयपुरा ठाकुर स्थान को राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र का दर्जा दिलाया जाये एवं इस तीर्थ स्थल का समुचित विकास किया जाये। इस दिशा में पर्यटन विभाग, बिहार सरकार को गंभीरता से लेना होगा। वही इस मंदिर के कर्ताधर्ता संतोष बाबा, भुतन सिंह और विजय सिंह का कहना है कि विजयपुरा ठाकुर स्थान में आज भी बांसुरी बजता है।

बहरहाल, बिहार के अन्य जिलों के पर्यटन स्थल एवं धार्मिक महत्वों पर जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं, उस स्थान को नाम व पहचान दिलाने में लगे हैं, उनसे स्थानीय जनता की मांग है कि विजयपुरा ठाकुर स्थान को महत्व देते हुए यथाशीघ्र नाम और पहचान दिलायी जाये, जिससे इस जगह से अंजान पर्यटक इसकी मान्यता और महत्व को देख समझ पाये। ●

क्या सरकार अन्न पैदा करने वाला मशीन अविष्कार करेगी

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा नेत्री ममता पटेल ने कहा कि भारत कभी कृषि प्रधान देश कहलाता था। गांव की मिट्टी में अन्न की खुशबू बसती थी। किसान के पसीने से देश की थाली भरती थी। खेत देश की ताकत थे, किसान देश की रीढ़ था। परंतु आज स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि कृषि प्रधान देश धीरे-धीरे जनसंख्या वृद्धि, अपराध और भ्रष्टाचार वृद्धि के बोझ तले दबता जा रहा है। जिस किसान के भरोसे देश जिंदा है, उसी किसान को सबसे अधिक अपमान, कर्ज और लाचारी झेलनी पड़ रही है। आज किसान की हालत ऐसी हो गई है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्ज उसका पीछा नहीं छोड़ता। खेती करने के लिए बीज कर्ज से, खाद कर्ज से, पानी कर्ज से, ट्रैक्टर कर्ज से, बच्चों की पढ़ाई कर्ज से, बीमारी की दवाई कर्ज से और अंत में कफन तक कर्ज से खरीदना पड़ता है। जिस देश का अन्नदाता अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा हो, उस देश के विकास के दावे कितने खोखले हैं, यह समझना कठिन नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने की गंभीर इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती। जनसंख्या लगातार विस्फोट की तरह बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी के लिए शौचालय, महलनुमा मकान, सड़क, स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री और सरकारी योजनाओं की लंबी कतार सजती जा रही है। लेकिन इन सबके लिए सबसे आसान निशाना किसान की उपजाऊ जमीन बन गई है। सरकारें और बड़े पूंजीपति विकास के नाम पर किसानों की अन्न उत्पादन वाली जमीन छीनने में लगे हैं। जिस मिट्टी से देश का भोजन पैदा होता

है, उसी मिट्टी पर कंक्रीट का जंगल उगाया जा रहा है।

विडंबना देखिए, एक ओर सरकारें किसानों को अन्नदाता कहकर मंचों पर सम्मान देती हैं, दूसरी ओर उसी किसान को उसकी जमीन से बेदखल करने की योजनाएं बनती हैं। किसान विरोध करे तो उसे विकास विरोधी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यदि खेत खत्म हो जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को भोजन कौन देगा? क्या सीमेंट और लोहे की फैक्ट्रियां रोटी पैदा करेंगी? क्या चमचमाती सड़कें भूख मिटाएंगी? आज गांव का किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ मौसम की बेरहमी, दूसरी तरफ सरकारी नीतियों की मार। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि तो कभी फसल का उचित मूल्य नहीं। ऊपर से बिचौलियों और भ्रष्ट व्यवस्था का शिकंजा। किसान अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर है, जबकि बाजार में वही सामान कई गुना महंगा बिकता है। मेहनत किसान करे और मुनाफा कोई दूसरा खा जाए, यही आज की व्यवस्था बन चुकी है। स्थिति इतनी दर्दनाक हो चुकी है कि देश के कई किसान कर्ज और बेबसी से टूटकर आत्महत्या तक कर चुके हैं। यह केवल आत्महत्या नहीं, बल्कि व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रश्नचिह्न है। जिस देश में अन्नदाता जहर पीने को मजबूर हो जाए, वहां लोकतंत्र और विकास के दावे शर्मसार हो जाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि देश में खेती और किसान की चर्चा कम होती जा रही है, जबकि अपराध, भ्रष्टाचार और सत्ता की राजनीति का शोर बढ़ता जा रहा है। रोजगार के अभाव में युवा अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार व्यवस्था की नसों में जहर की तरह फैल चुका है। योजनाएं गरीबों के नाम पर बनती हैं, लेकिन मलाई भ्रष्ट तंत्र खा जाता है। किसान और मजदूर केवल भाषण सुनते रह जाते हैं। आज आवश्यकता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून बने। किसानों की उपजाऊ जमीन की सुरक्षा के लिए सख्त नीति लागू हो। खेती को उद्योग से अधिक महत्व दिया जाए। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, सिंचाई और खाद की सस्ती व्यवस्था हो तथा कृषि को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ईमानदार पहल हो। क्योंकि जिस दिन खेत खत्म हो जाएंगे, उस दिन देश की आजादी और विकास दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। यदि सरकारें और समाज अब भी नहीं चेते, तो आने वाला समय भयावह होगा। तब देश में इमारतें तो बहुत होंगी, लेकिन थाली में अन्न नहीं होगा। इसलिए देश को बचाना है तो किसान को बचाना होगा, खेत को बचाना होगा और अन्न उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।●

रेल विकास की रफ्तार से बदलेगा बिहार का भविष्य

दानापुर-फतुहा तीसरी-चौथी रेललाइन की मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार, कहा यह विकसित बिहार की मजबूत नींव फतुहा। भाजपा नेत्री शोभा पटेल ने दानापुर से फतुहा तक तीसरी और चौथी रेललाइन बिछाने की 976 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे बिहार के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल रेललाइन विस्तार की योजना नहीं, बल्कि बिहार की आर्थिक प्रगति, उद्योग, व्यापार और रोजगार को नई गति देने वाला बड़ा कदम है। लंबे समय से व्यस्त दानापुर-पटना-फतुहा रेलखंड पर ट्रेनों का दबाव कम होगा, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और मालगाड़ियों के संचालन में भी तेजी आएगी। इसका सीधा लाभ किसानों, व्यापारियों, छात्रों और लाखों दैनिक यात्रियों को मिलेगा। शोभा पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले ले रही है। सड़क, रेल, पुल और अन्य विकास परियोजनाओं के माध्यम से बिहार को आधुनिक परिवहन व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। यह निर्णय आने वाले वर्षों में राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई ऊंचाई देगा। उन्होंने कहा कि विकास की राजनीति ही देश और समाज को आगे ले जाती है। दानापुर-फतुहा रेललाइन विस्तार की मंजूरी इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार बिहार की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री और केंद्र सरकार को बधाई देते हुए कहा कि यह परियोजना बिहार के विकास की नई पहचान बनेगी। **रिपोर्ट :- डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह**

भाजपा प्रदेश महामंत्री का अधिकार और कर्तव्य

नारा, माला और फोटो खिंचवाना नहीं

● **डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह**

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि भाजपा प्रदेश महामंत्री का कार्य सिर्फ कार्यक्रताओ से नारा लगवाना, माला पहनना और फोटो खिंचवाना नहीं है बल्कि अधिकार और कर्तव्य का पालन करना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने प्रथम बार शपथ ग्रहण समारोह में कहा था कि भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा है, सबों को आगे आना होगा। भ्रष्टाचार केवल सरकारी धन की चोरी नहीं है, बल्कि यह गरीब के अधिकार, किसान की मेहनत, छात्र के भविष्य और आम नागरिक के विश्वास पर डाका है। जब कोई अधिकारी जनता से रिश्वत मांगता है, जब विकास योजनाओं का पैसा बिचौलियों और भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ जाता है, जब सड़क, पुल, अस्पताल और विद्यालय के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जनता को गुणवत्तापूर्ण सुविधा नहीं मिलती, तब लोकतंत्र की आत्मा घायल होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना, प्रदर्शन, जनआंदोलन और जनजागरण ऐसे संवैधानिक माध्यम हैं, जिनके जरिए जनता अपनी आवाज सत्ता और प्रशासन तक पहुंचाती है। जब शिकायतों, आवेदनों और ज्ञापनों के बावजूद भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होती, तब शांतिपूर्ण और कानून सम्मत धरना-प्रदर्शन जनता के अधिकारों की रक्षा का सशक्त माध्यम बन जाता है।

प्रदेश महामंत्री की भूमिका यहां अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि किसी जिले में मनरेगा, आवास योजना, राशन वितरण, भूमि मापी, दाखिल-खारिज, शिक्षा, स्वास्थ्य या निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें मिल रही हों, तो सबसे पहले तथ्यों और प्रमाणों को एकत्र करना चाहिए। बिना प्रमाण के आरोप लगाने से आंदोलन कमजोर होता है, जबकि तथ्य आधारित संघर्ष व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर देता है। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर समयबद्ध कार्रवाई की मांग की जानी चाहिए। यदि फिर भी कार्रवाई नहीं होती, तो प्रखंड, अनुमंडल, जिला मुख्यालय और संबंधित कार्यालयों के समक्ष शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन आयोजित किए जा सकते हैं। ऐसे आंदोलनों का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को अपमानित करना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं और भ्रष्टाचार के मामलों को सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाना होना चाहिए। आज सबसे बड़ा संकट यह है कि कई बार जनता भ्रष्टाचार को अपनी नियति मानकर चुप हो जाती है। यही चुप्पी भ्रष्ट तंत्र की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब जनता संगठित होकर सवाल पूछती है, तब बड़े-बड़े अधिकारी और तंत्र जवाब देने को मजबूर हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि अनेक जनहित के मुद्दों पर जनदबाव ने प्रशासन को निर्णय बदलने और कार्रवाई करने के लिए विवश किया है।

प्रदेश महामंत्री को चाहिए कि वे गांव-गांव, पंचायत-पंचायत और वार्ड-वार्ड में भ्रष्टाचार विरोधी जनजागरण अभियान चलाएं। लोगों को यह बताया जाए कि रिश्वत देना और लेना दोनों गलत हैं तथा सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी अवैध भुगतान के मिलना उनका अधिकार है। साथ ही, सूचना के अधिकार (RTI), जनसुनवाई और शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग कर तथ्यों को सामने लाने की पहल की जाए। यह भी आवश्यक है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, अनुशासित और कानून सम्मत हो। लोकतंत्र में संघर्ष का उद्देश्य अराजकता फैलाना नहीं, बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जब हजारों नागरिक किसी कार्यालय के सामने खड़े होकर पूछते हैं कि जनता का पैसा कहां गया, विकास कार्य अधूरे क्यों हैं, पुल और सड़कें समय से पहले क्यों टूट रही हैं, तब यह सवाल केवल प्रशासन से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से होता है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई किसी एक दल, व्यक्ति या संगठन की नहीं, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। यदि जनता जागेगी, संगठन आवाज उठाएगा और प्रशासन जवाबदेह बनेगा, तभी सुशासन का सपना साकार होगा। लोकतंत्र में धरना और प्रदर्शन केवल विरोध के साधन नहीं हैं, बल्कि वे सत्ता को यह याद दिलाने का माध्यम हैं कि असली मालिक जनता है और जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग है। आज आवश्यकता डरने की नहीं, बल्कि सच बोलने की है; चुप रहने की नहीं, बल्कि व्यवस्था से जवाब मांगने की है। जब जनता संगठित होकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ी होगी, तभी विकास की नींव मजबूत होगी और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा सुरक्षित रह सकेगी। महामंत्री महोदय भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को मुंद्रा योजनाओं का ऋण दिलवा दें जिससे अपना रोजगार कर सके औरों को दे सकें।●

सरदार पटेल जैसा साहस दिखाएं सीएम सम्राट

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भारत के लौह पुरुष और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने प्रशासन और कानून व्यवस्था को लेकर जो आदर्श स्थापित किया था, वह आज भी प्रासंगिक है। उनका स्पष्ट मानना था कि अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। यदि शासन और प्रशासन की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो अपराध और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण असंभव नहीं है। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ. लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह करते हुए कहा कि आज राज्य में आम लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। हत्या, लूट, रंगदारी, भूमि विवाद, महिला उत्पीड़न और साइबर अपराध जैसी घटनाओं ने जनता को परेशान कर रखा है। ऐसे समय में सरकार को सरदार पटेल की कार्यशैली से प्रेरणा लेकर कठोर और त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रथम गृह मंत्री सरदार बल्भ भाई पटेल ने शपथग्रहण के समय घोषणा कर दिया कि कल से एक घंटा नित्य दिन जनता के लिए समय देगे।

सयोंग से पहले ही दिन कानपुर से बुजुर्ग महिला आई थी, पुछने पर महिला ने कहा कि मेरा बेटा एक महिना से जेल में है, अपने चल कर देख लें। उनहे महिला के बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया और तुंरत कानपुर के एस को फोन लगाये और कहा कि निम्न थाना में एक निर्दोष लड़का एक महिना से जेल मे है। एक घंटे के अंदर दारोगा को जेल भेजो अन्याय अगला दिन तुम जेल में रहोगे। ऐसे थे पटेल। सम्राट चौधरी जी जांच करवा ले अधिकांश निर्दोष ही जेल में मिलेगा। आप भी निर्दोष को

जेल भेजने वाले को जेल भेजना शुरू कर दे। यदि किसी अपराध का प्रथम दृष्टया प्रमाण मिल जाता है, तो राजनीतिक दबाव, जातीय समीकरण अथवा प्रभावशाली लोगों की पैरवी से ऊपर उठकर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का भय समाप्त होने पर अपराधी बेलगाम हो जाते हैं और निर्दोष नागरिक भय के वातावरण में जीने को मजबूर हो जाते हैं। लोकतंत्र में जनता की पहली अपेक्षा सुरक्षा और न्याय होती है। डॉ. पटेल ने कहा कि पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखते हुए उनकी जवाबदेही तय करनी होगी। जिस प्रकार सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत आधार दिया था, उसी प्रकार आज भी दृढ़ इच्छाशक्ति और निष्पक्ष कार्रवाई की आवश्यकता है। अपराधी का कोई धर्म, जाति या दल नहीं होता; उसका केवल एक परिचय होता है-वह कानून तोड़ने वाला व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कदम उठाती है तो जनता का विश्वास स्वत: बढ़ेगा। बिहार की जनता विकास के साथ-साथ सुरक्षित वातावरण भी चाहती है। सरकार की सफलता केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था में दिखाई देने वाले सुधार से मापी जाएगी। अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि राज्य में अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि बिहार कानून के राज, सुशासन और जनविश्वास का उदाहरण बन सके। जनता को यह महसूस होना चाहिए कि अपराध करने वाला चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, कानून के सामने सभी समान हैं और दोषी को शीघ्र दंड मिलेगा।●

दिलीप जयसवाल अहंकार के परिचायक?

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

डॉ. लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि जनप्रतिनिधि और मंत्री जनता के सेवक हैं, जनता उनके दरबार की प्रतीक्षा करने के लिए विवश नहीं होनी चाहिए। पटना। भाजपा मीडिया प्रभारी किसान एवं डॉ. लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि यदि कोई मंत्री आम नागरिक या किसान को घंटों प्रतीक्षा कराए और इस दौरान अपने परिचितों से बातचीत में व्यस्त रहे, तो यह जनप्रतिनिधि के आचरण पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व जनता की बात सुनना और उनकी समस्याओं का सम्मानपूर्वक समाधान करना है। उन्होंने कहा कि यदि जनता को सम्मान नहीं मिलेगा और उसकी समस्याओं को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तो इसका राजनीतिक नुकसान किसी भी दल को उठाना पड़ सकता है। लोकतंत्र

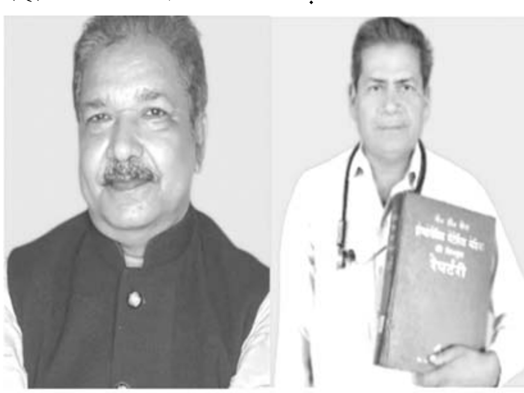

जनता को अपने गेट पर छ घंटे खड़ा करवाने वाले मंत्री दिलीप जयसवाल

में जनता सर्वोपरि है और मंत्री जनता के सेवक होते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों के व्यवहार में विनम्रता, जवाबदेही और समय का सम्मान दिखाई देना चाहिए। डॉ. पटेल ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर कठोर कार्रवाई की अपेक्षा है। जनता चाहती है कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई हो, ताकि सुशासन पर लोगों का विश्वास मजबूत हो। उन्होंने आग्रह किया कि जनप्रतिनिधियों को जनता से संवाद बढ़ाना चाहिए, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए और ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे जनता का विश्वास और सम्मान बना रहे। लोकतंत्र की असली ताकत जनता है, और उसकी उपेक्षा किसी भी राजनीतिक दल के लिए दीर्घकाल में नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है।●

गोलियों की तड़तड़ाहट से कांपी चैती पीपर की धरती

लेडी सिंघम DY. S.P. कृति कमल ने तोड़ी बालू माफियाओं की कमर

● अमित कुमार सिंह/रजनीश कान्त झा

जिले के बालू माफिया ने 4 जूलाई को घोसी थाना क्षेत्र के चौती पीपर की धरती पर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहली धरती छः लोगों को लगी गोली बालू माफिया को नदी किनारे बालू उठाव को महिला लोगो ने विरोध किया और कहा कि इधर प्रदा (झलास) में हमलोग शौच को जाते है। बस इतनी सी विवाद पर अपराधियों ने तील को ताड़ बनाकर तावातोड़ फायरिंग कर छः लोगों को गोली गली। जिसमें एक अपराधी को चन्द्रवंशियों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुख्य अभियुक्त विशणु शर्मा को पकड़ कर पुरी तरह पिटाई की। फिर सूचना पाकर पहुँची पुलिस के हवाले किया। इस काण्ड में महिला एवं पुरूश दोनो को गोली लगी। पहले सदर अस्पताल जहानाबाद में भर्ती कराया गया फिर जिनका पेट में गोली लगी थी जो गंभीर अवस्था में थे सभी को पटना रेफर किया गया बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। इधर DYSp लेडी सिंघम कृति कमल SIT गठन कर एक सप्ताह के भीतर मुख्य आरोपी समेत सभी की गिरफ्तारी एवं कुर्ती जप्ती कर केश का निष्पादन किया गया। एवं अपराधियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

घटना स्थल पर मंत्री प्रमोद चन्द्रवंशी, रामबली चन्द्रवंशी, पूर्व डस्ब्ए भीम सिंह राज्यसभा सदस्य, चन्देश्वर चन्द्रवंशी पूर्व लोक सभा सदस्य पूर्व सदस्य अतिपिछड़ा आयोग प्रमोद सिंह चन्द्रवंशी ने जिला के SP, DM को कडे निर्देश देकर शीध्र गिरफ्तारी करने को कहा फिर ये सभी नेताओं ने घायल से पटना में जाकर मुलाकात किये और इंसाफ का भरोसा दिलाया। एक युवा नेता लवकुश कुमार हम पार्टी के नेता है। उन्होनें भी शिष्टाचार मुलाकात की। घोषी थाना क्षेत्र के चौती पीपर गाँव में गोली काण्ड में पीड़ित परिवार से राजद का एक प्रतिनिधि मंडल मिला और कहा कि गाँव में दहशद का माहौल है। कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करनी गिंजी गाँव नहीं जा रहे है।

कृति कमल
DY.S.P.

उन्होने बताया शौचालय निर्माण के लिए बोरी से बालू लाने गये की उसी दौरान, बालू माफियाओं द्वारा रंगदारी माँगा गया। यह घटना आपसी गुटीय सधसे नहीं है। बल्कि बालू तस्कर द्वारा किया गया सुनियोजित हमला था। निर्दोश लोगों को झुठे मुकदमें के मामले में फसाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान सरकार में अपराधी वेलागम हो चुके है। सरकार से मामले की निष्पक्ष जाँच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इलाज कराने तथा बालू तस्कर और स्थानीय पुलिस संबंधों की जाँच कर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की माँग की गई है। कितने प्रतिशत शौचालय का निर्माण हुआ है। इसका काला चिट्ठा का पोल जातीय जनगणना में खुल चुका है।

इधर घोषी थाना क्षेत्र के चौती पीपर गाँव में 4 जूलाई की हुई हिंसक घटना के विरोध में सोमवार को घोसी खेल के मैदान में माकपा माले की ओर से प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया सभा में बड़ी संख्या में लोग, ग्रामीण, महिला और पीड़ित परिवार ने भाग लिया। वक्ताओं ने राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर अवैध बालू खनन को संरक्षण देने तथा पीड़ितों के साथ न्याय नहीं होने का आरोप लगाया। धीरेन्द्र झा ने आरोप लगाया फल्गु नदी में प्रतिबंध के बावजूद स्थानीय स्तर पर अवैध बालू खनन जारी है। इसमें प्रशासन की मिली भगत है। उन्होने दावा किया कि चैती पीपर में गरीब, दलित, अतिपिछड़ा परिवार के लोगों पर बालू माफिया ने जानलेवा हमला किया। लोग गाँव में

अब भी दहशद के महौल में जी रहे है। पीड़िता को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। पूर्व विधायक महानंद सिंह ने आरोप लगाया कि पीड़िता को सुरक्षा के बजाय झुठे मुकदमे में निर्दोश लोगों को फसाने की साजिश रची जा रही है। उन्होनें कहा कि स्थानीय महिला ने साहस का परिचय देते हुए हमलावरों को धुल चटाया और मुहतोड़ जवाब दिया और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होनें आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार से दूरी बनाए रखी पूर्व विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा यह संघर्ष केवल बालू के अवैध खनन का नहीं बल्कि गरीबों के अधिकार सम्मान और प्राकृतिक संसाधनों पर भी उसका हक है। जबतक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तबतक सड़क से सदन तक आन्दोलन जारी रहेगा। सभा में पीड़ित

महिलाओं रेणु देवी और रेशमी देवी ने अपनी बात रखते हुए आरोप लगाया की उन्हे लगातार फोन पर धमकिया मिल रही है और गाँव में असुरक्षा का माहौल है। सभा के दौरान सरकार और प्रशासन के समक्ष कई माँग रखी इनमें अजय राम और विजय राम पर दर्ज मामले को वापस लेने अवैध खनन को सरक्षंण देने वाली आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई मुख्य आरोपी स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी सजा दिलाने पीड़ित परिवार को मुआवजा मुफ्त इलाज और सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा चौतीपुर पीपर महादलित अतिपिछड़ा टोले में शौचालय पेयजल, एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने की माँग की। साथ ही उन्होने कहा कि अपराधियों को मिल रहा सत्ता एवं प्रशासन का संरक्षण गरीबों पर जुर्म ढ़ाह रही है सरकार सभा के अन्त में पार्टी के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी माँग पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन एंव घेराव की जायेगी तथा जरूरत पड़ी तो सरकार की विधानसभा का घेराव किया जायेगा।●

ई.ओ. हत्याकाण्ड में सीबीआई जांच की मांग

कैंडल मार्च निकाल लोगों ने जताया आक्रोश

● मो० सईद

डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) एवं शेरघाटी निवासी डॉ. विमल कुमार की हत्या के विरोध में मंगलवार 4 अगस्त की शाम शेरघाटी में कैंडल मार्च निकाला गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यवसायियों और स्थानीय नागरिकों ने हाथों में मोमबत्तियां व तख्तियां लेकर शहर के प्रमुख मार्गों पर मार्च किया। इस दौरान लोगों ने हत्याकांड की निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। कैंडल मार्च गोलाबाजार से शुरू होकर राम मंदिर, शहर के प्रमुख मार्गो से गुजरते हुए पुलिस चौक पहुंचा। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने "ईओ विमल कुमार के हत्यारों को फांसी दो", "विमल कुमार हत्याकांड की सीबीआई जांच हो" और "हाथों में मशाल है, न्याय का सवाल है" जैसे नारे लगाए। लोगों ने कहा कि एक सरकारी अधिकारी की इस तरह हत्या होना गंभीर चिंता का विषय है। घटना की पूरी सच्चाई सामने लाकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है।

मार्च के बाद अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हत्याकांड की उच्चस्तरीय और पारदर्शी जांच कराने, हत्या के पीछे छिपी पूरी साजिश का पर्दाफाश करने, घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान कर उन्हें कानून के कठघरे में लाने तथा दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मामले की जांच किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए और घटना के हर पहलू की जांच होनी चाहिए।

❖ **डेहरी से पटना लौटने के दौरान हुई थी हत्या :-** गौरतलब है कि डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या 1 जुलाई की रात डेहरी से पटना लौटने के दौरान की गई थी। वह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने वाहन से पटना जा रहे थे। इसी दौरान बारुण थाना क्षेत्र में धनौती पुल के समीप पटना नहर रोड पर उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। हमलावरों ने वाहन को रोककर विमल कुमार पर रॉड व धारदार हथियार से हमला करने के साथ गोली भी मारी थी। गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमुहार ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। विमल कुमार मूल रूप से शेरघाटी के गोलाबाजार क्षेत्र के निवासी थे। उनकी हत्या की खबर के बाद से ही शेरघाटी में लोगों में आक्रोश और शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विमल कुमार एक सरकारी अधिकारी होने के साथ शेरघाटी के रहने वाले थे, इसलिए इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। मामले में उनके चालक मिथलेश कुमार पर हत्या में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है और

नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हालांकि, हत्या के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र या अन्य लोगों की भूमिका को लेकर अभी जांच जारी है। आईजी विकास वैभव के निर्देश पर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के वास्तविक कारण, षड्यंत्र और अन्य संभावित आरोपितों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। कैंडल मार्च में महेंद्र अग्रवाल, पवन किशोर, प्रमोद वर्मा, रिंकू उर्फ नजीर, राजीव पाठक, सुनील अग्रवाल, दीनानाथ पांडे, प्रवेश वर्मा, डॉ. पंकज अग्रवाल, दिनेश यादव, शकील खान सहित बड़ी संख्या में नागरिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।●

दिव्या हत्याकाण्ड में बड़ी सफलता

आरोपित राहुल यादव गिरफ्तार

● मो० सईद

बहुचर्चित दिव्या कुमारी पासवान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डोभी प्रखंड निवासी एलएलबी छात्रा दिव्या कुमारी पासवान की हत्या के मुख्य आरोपित राहुल कुमार यादव को शेरघाटी और झारखंड के हंटरगंज थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ से मिलने वाले तथ्यों के आधार पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शेरघाटी डीएसपी संदीप कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों और पूछताछ के आधार पर मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी। गिरफ्तार किए जाने के बाद राहुल कुमार यादव को शेरघाटी पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर झारखंड के हंटरगंज थाना पुलिस के हवाले कर दिया। हंटरगंज थानाध्यक्ष प्रभात कुमार ने बताया कि आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। दिव्या कुमारी पासवान बीते 24 जून से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता थी। परिजनों की शिकायत के बाद उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन काफी खोजबीन के बाद उसका शव झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र स्थित पानी से भरी एक खदान से बरामद हुआ था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था। परिजनों ने शुरू से ही आरोप लगाया था कि पुराने दुष्कर्म मामले में गवाही रोकने के उद्देश्य से राहुल कुमार यादव ने इस वारदात को अंजाम दिया। परिजनों के अनुसार, उस मामले में दिव्या की गवाही एक जुलाई को होनी थी और इसी वजह से उसकी हत्या की साजिश रची गई।

दिव्या कुमारी पासवान

राहुल कुमार यादव

निलंबित थानेदार मोहन कुमार

सुशील कुमार एसएसपी, गयाजी

घटना के बाद पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर भी लगातार सवाल उठते रहे। न्याय की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शेरघाटी में कैंडल मार्च निकाला और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी स्वयं पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए गया के वरीय पुलिस अधीक्षक से आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की थी। इधर, मामले की जांच में लापरवाही सामने आने के बाद गया के वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने शेरघाटी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष मोहन कुमार और चौकीदार देवेंद्र कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसएसपी कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जांच में पाया गया कि पीड़िता के अनुसूचित जाति से संबंधित होने के बावजूद प्राथमिकी में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं नहीं जोड़ी गईं। इसके अलावा चौकीदार पर शिकायत मिलने के बावजूद संतोषजनक कार्रवाई नहीं करने, पीड़ित पक्ष से दुर्व्यवहार करने तथा अन्य प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप भी सही पाए गए। दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।

मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी और पुलिस अधिकारियों पर हुई कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि परिजनों का कहना है कि वे मामले में शामिल सभी दोषियों की गिरफ्तारी और त्वरित न्यायिक कार्रवाई होने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों को कानून के अनुसार सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।●

क्या रेलवे, दारोगा दंपत्ति को दे पायेगी इंसाफ!

● अमित कुमार सिंह/रजनीश कान्त झा

बिहार के चर्चित नवादा के वारिसलीगंज एवं काशीचक के बीच दारोगा दम्पति के साथ गया हावड़ा एक्सप्रेस में सीट पर बैठने को लेकर बड़ा ववाल खड़ा हो गया। नवादा से एक यात्री जो बिना टिकट Ac बोगी में घुस जाता है और दोनो दारोगा दम्पति जो अपनी दोनो डियूटी ज्वाइन करने जा रहे दारोगा दम्पति के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। आये दिन इस तरह की घटना गया क्यूल रेलवे में सीट को लेकर अक्सर विवाद खड़ा होता रहता है। क्या रेलवे बिना टिकट यात्री को Ac बोगी में बैठने की इजाजत देती है। अगर इस तरह की व्यवस्था है तो क्या लोग Ac में इतना महँगा सफर बिना सुरक्षा के करेगा। दोनो से 139 पर फोन कर सुरक्षा की गुहार लगाई। एवं T.T.E.ने उनका साथ नहीं दिया और T.T.E. पहुँचा पर बातचीत का मामला वही छोड़कर हँसता हुआ चल दिया। बाद में T.T.E. को सस्पेंड कर दिया गया। दारोगा दम्पति ने बताया कि नवादा में बैठा आदमी अपने साथियों लगभग 10 अज्ञात लोगो को बुलाकर ट्रेन में मारपीट किया एवं चलती ट्रेन में तीनो को जान मारने के नियत से ट्रेन से फेकने का प्रयास किया।

अगर कोई यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है तो उस पर अर्थ दण्ड एवं सजा का प्रावधान भारत के संविधान एवं रेलवे के संविधान में वर्णित है। विस्फोटक समान, ज्वलनशील पदार्थ आदि पकड़े जाने पर दोषी व्यक्ति को तीन वर्ष तक कैद और एक हजार रूपया का जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद एवं 10 अज्ञात अपराधी को बुलाकर ट्रेन में मारपीट करता है एवं दारोगा दम्पति एवं 4 साल के बच्चे को चलती ट्रेन से फेकना चाहता है एवं अभद्र व्यवहार करता है। दम्पति ने बताया कि हमलोगों को लोगो ने धमकी दी कि अगले स्टेशन पर इनलोगों को पिटेगें अपराधी एवं दोनो ने चलती ट्रेन में हाथापाई की एवं दो बार चौन पुलिंग कर ट्रेन को रोका। तो रेलवे ने इस तरह की जघन्य अपराध के लिए कितने साल एवं कितने रूपये सजा का प्रावधान है। रेलवे प्रशासन एवं विभाग बताए।

इस घटना के विरोध में दारोगा दम्पति एवं 4 साल का बच्चा के साथ की घटना के विरोध में महिला दारोगा ने ट्रेन पर विरोध किया तो यात्री एवं ग्रामीण सामने खड़ी होकर लगभग 1 घंटे तक विरोध की जिससे ट्रेन संचालन बाधित रही जानकारी के अनुसार दारोगा झारखण्ड के साहिबगंज जिले के बड़हरवा थाने में तैनात महिला पूजा कुमारी पति हरिओम और बच्चे के साथ गया से पाकुड़ जा रहे थे। हरिओम गया जिले के डेलहा निवासी स्पेशल ब्राँच में दारोगा पद पर तैनात है। दारोगा दम्पति अपने परिवार के साथ गया हावड़ा एक्सप्रेस के Ac कोच B-2 में यात्रा कर रहा था। पूजा को 6 जूलाई को डयूटी ज्वाइन करनी थी। उन्होने बताया कि नवादा स्टेशन से ही कुछ युवक जबरदस्ती मना करने के बावजूद बैठ गया पूजा की सीट को खाली करने को कहा इस पर उनलोगों ने उग्र रूप लेकर गलत ढ़ंग से सीट पर कब्जा जमाया और फिर युवक ने अपने लगभग 10 साथियों को बुलाकर काशीचक स्टेशन पर मारपीट किया। दारोगा दम्पति ने बातया। ट्रेन काशीचक स्टेशन पहुची तो पहले से घात लगाये मौजूद अपराधियों ने उनके पति पर लाठी और डंडो से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई पत्नी पूजा कुमारी को भी गंभीर चोट आई। पूजा ट्रेन से उतरकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की माँग करने लगी। आर.पी.एफ., जी.आर.पी. और स्थानीय पुलिस काशीचक थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने दारोगा दम्पति से घटना की जानकारी ली। कठोर कारबद्ध का भरोसा दिया। इसके बाद ट्रेन रवाना हुई।

इस घटना के बाद बदमाशों ने पूजा के घर जाकर समझौता का दबाब देकर बातचीत नहीं समझौता की तो पूजा को अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। जबाब में दारोगा दम्पति ने समझौता से साफ इनकार कर दिया।

आर पी0 एफ0 थानाध्यक्ष महेन्द्र कुमार ने बताया कि सुरक्षा नियंत्रण कक्ष दानापुर द्वारा जानकारी मिली की काशीचक रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 13024 को कुछ यात्रियों द्वारा इंजन के पास खड़ा होकर उसके साथ मारपीट होने के कारण गाड़ी रोक दिया गया था। इस घटना के बाद खानापूर्ति के लिए दो चार दिन टिकट चेकिंग चलाया यगा फिर वही ढ़ाक के तीन पात फिर वैसा ही व्यवस्था बहाल हो जायेगी। आखिर रेलवे ऐसे अपराधियों पर कब नकेल कसेगी। आखिर कब तक जबरन सीट पर बैठने का विरोध करने पर युवको से यात्री मारपीट खाते रहेगी। दारोगा दम्पति ने बताया कि उस अपराध ी का नाम विलमेश कुमार पिता परशुराम सिंह दादा दुखो सिंह, मुनिरका सिंह थे पूर्व पैक्स अध्यक्ष सकलदेव सिंह क गोतिया से आते है। आखिर कबतक पुलिस ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर सजा देती है। या दारोगा दम्पति न्याय के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी।●

RIMC देहरादून में शिखा राय का चयन

● मिथिलेश कुमार/मनीष कमलिया

नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की बेटी शिखा राय ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर देश के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य शिक्षण संस्थानों में से एक राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC), देहरादून में चयनित होकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। शिखा की इस शानदार सफलता से परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ग्रामीण, शिक्षक एवं शुभचिंतक उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं और उनकी उपलब्धि को क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणादायक बता रहे हैं।

शिखा राय, सुल्तानपुर निवासी शिक्षक प्रवीण कुमार एवं गृहिणी सिंपी कुमारी की पुत्री हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वारिसलीगंज के विवेकानंद पब्लिक स्कूल से हुई। बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रही शिखा ने आगे की तैयारी

के लिए दिल्ली के एक निजी संस्थान में रहकर आरआईएमसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। कठिन परिश्रम, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने माता-पिता एवं अपने गुरुजनो का सपना साकार कर दिया। शिखा ने बताया कि उनका सपना भारतीय सेना में आर्मी ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना है। उनका कहना है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कोई भी मंजिल कठिन नहीं होती। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और सभी शुभचिंतकों को देती हैं, जिन्होंने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया।

थाना प्रभारी ने NEET UG 2026 के ऑल इंडिया रैंक-4 आयुष भालोटिया को किया सम्मानित

वारिसलीगंज थाना प्रभारी पंकज कुमार सैनी ने मंगलवार को नगर के कमलिया मिल निवासी एवं NEET UG 2026 में ऑल इंडिया रैंक-4 प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र आयुष भालोटिया के आवास पर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर आयुष को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। थाना प्रभारी ने कहा कि आयुष भालोटिया की यह शानदार उपलब्धि पूरे वारिसलीगंज, नवादा और बिहार के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। आयुष की उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है। बताते चलें कि आयुष भालोटिया, वारिसलीगंज के कमलिया मिल निवासी व्यवसायी सुनील भालोटिया के छोटे पुत्र हैं। उन्होंने NEET UG 2026 में ऑल इंडिया रैंक-4 हासिल कर चिकित्सा शिक्षा की देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनकी इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मौके पर उपस्थित शिक्षक व समाजसेवी प्रत्यूष आनंद ने आयुष को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। वहीं परिवार के सदस्यों ने थाना प्रभारी के इस सम्मान एवं उत्साहवर्धन के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

जब केवल सच के पत्रकार नें शिखा की मां सिंपी कुमारी से सवाल पूछा तो अपनी बेटी की सफलता पर वो भावुक हो गई। उन्होंने कहा, 'हमारी दो बेटियां हैं, बेटा नहीं है। गांव के कई लोग ताना मारते थे कि बेटा नहीं है, फिर भी बेटी को बाहर पढ़ा रही हो। लेकिन मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा था। आज लगता है कि मेरी बेटी ही मेरा बेटा बनकर परिवार और गांव का नाम रोशन कर रही है।' उनकी यह बात सुनकर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। शिखा के पिता प्रवीण कुमार, जो गांव के एक विद्यालय में शिक्षक हैं, ने कहा कि बेटा और बेटी में कभी कोई अंतर नहीं करना चाहिए। यदि बेटियों को भी समान अवसर और बेहतर शिक्षा मिले तो वे हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं। उन्होंने सभी अभिभावकों से बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC), देहरादून भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित देश का एक प्रतिष्ठित सैन्य शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1922 में हुई थी। यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र आगे चलकर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) तथा भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना में अधिकारी बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आरआईएमसी में प्रवेश के लिए वर्ष में दो बार-जून और दिसंबर सत्र के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। पूरे देश से लाखों छात्र-छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन केवल 36 सीटों पर ही चयन होता है, जिनमें 28 सीटें लड़कों और 8 सीटें लड़कियों के लिए निर्धारित हैं। ऐसे कठिन मुकाबले में शिखा राय का चयन होना नवादा जिले के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

शिखा की इस सफलता पर परिवार, विद्यालय,वारिसलीगंज के SHO श्री पंकज सैनी सर, ग्रामीणों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों एवं पत्रकारों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। उनकी उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। सही मार्गदर्शन, अवसर और मेहनत के बल पर वे देश का नाम रोशन कर सकती हैं। शिखा राय की यह सफलता निश्चित रूप से नवादा जिले की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। ●

राज्य स्तरीय योगासन चैंपियनशिप-2026 का हुआ भव्य आयोजन

● **मिथिलेश कुमार**

राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्टस काम्पलेक्स में आयोजित सातवें राज्य स्तरीय योगासन चौंपियनशिप, 2026 में नवादा के खिलाड़ियों ने योगासन खेलों में धूम मचा दी है। पहली बार एक बड़ी टीम के साथ प्रदर्शन करने पहुंची नवादा की टीम ने प्रदेशभर के खिलाड़ियों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश की और एक स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य पदक जीतकर पदल तालिका में पांचवें स्थान पर रहें। जिले के काशीचक प्रखंड की नेहा कुमारी ने परंपरागत योगासन खेल में स्वर्ण जीता। नवादा नगर की आंचल मेहता और नारदीगंज के फल्गु की ज्योति कुमारी ने तालात्मक योगासन युगल में रजत और कलात्मक योगासन युगल खेल में कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं नवादा नगर के केशव पांडेय और काशीचक प्रखंड के शिवम कुमार और काशीचक प्रखंड की नेहा कुमारी और चांद मुनि की जोड़ी ने कलात्मक योगासन युगल में अलग-अलग ग्रुप में कांस्य पदक जीता। पटना, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी के बाद नवादा इस प्रतियोगिता में पांचवे स्थान पर रही।

❖ **महानिदेशक ने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिस्पर्द्धा के लिए खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित :-** बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरण ने योगासन खेल के खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। इस बार योगासन खेल भी होंगे। इस खेल में नवादा के खिलाडी भी देश के लिए पदक जीतें। महानिदेशक ने सभी खिलाड़ियों को संकल्प दिलाया। इधर, बिहार योगासन स्पोर्टस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रशेखर प्रसाद, सचिव डा. रानी कुमारी, कंपीटिशन मैनेजर अवनीश कुमार मिश्रा, टेक्निकल डायरेक्टर अभिजीत कुमार, कंपीटिशन डायरेक्टर डा. संध्यावासिनी कुमारी ने नवादा के खिलाड़ियों को प्रतिभावान बताते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने को प्रेरित किया। बता दें कि नवादा जिला योगासन खेल समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार और सचिव मनमोहन कृष्ण महीनेभर से प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे थे। राज्य स्तर पर प्रतियोगिता के लिए 29 खिलाड़ियों का चयन किया गया था, जिसमें 25 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ●

गांवों को पूर्ण विकसित करना मेरा दृढ़ संकल्प : श्रवण कुमार

● प्रो० रामजीवन साहु

भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है. इसी चिंतन के कारण बिहार सरकार के मंत्री माननीय श्री श्रवण कुमार ने कहा कि गाँवों को पूर्ण विकसित करना मेरा दृढ़ संकल्प है. सर्वप्रथम यह बताना चाहूंगा कि श्रवण कुमार नाम एक ऐतिहासिक नाम है. श्रवण शब्द में कुल चार अक्षर हैं. एक संयोग है कि इस नाम में कोई मात्राएं नहीं हैं. यह त्रेतायुगीन प्रेरणादाई और आदर्शवादी नाम है. भारत के लगभग-लगभग सभी नागरिक यह जानते हैं कि त्रेतायुगकालीन श्रवण अपनी आर्थिक विपन्नता के कारण अपने मात-पिता की तीर्थाटन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कांवर में बिठाकर यात्रा प्रारम्भ किए थे.

वर्तमान समय में बिहार प्रांत के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री माननीय श्री श्रवण कुमार भी उसी मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हैं. इनका संकल्प उस श्रवण कुमार से भी बेहतर है. इनका चिंतन है कि बिहार के प्रत्येक नागरिकों को इतना आर्थिक और साधन सम्पन्न बना दें कि प्रत्येक पुत्र की इच्छा इतनी प्रवल हो जाए कि अपने मात-पिता को आधुनिक संसाधनों के द्वारा तीर्थाटन कराने के लिए व्याकुल हो जाए.

केवल सच के विशेष प्रतिनिधि प्रो० रामजीवन साहु द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के वृहत कार्य हैं, परन्तु उनमें से कुछ कार्य अग्रवत है :-

☞ 2026-27 में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, आवास योजना और रोजगार के लिए केन्द्र सरकार ने 23,701.28 करोड़ रूपये स्वीकृत की है.

☞ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम एक जुलाई 2026 से VBG, RAM G हो गया है यानि 'विकसित भारत गारंटी' अब 'रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' हो गया है. इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रांत में अतिप्रभावि तरीके से लागू करने के 6,715.83 करोड़ रूपये का अंतरिम बजट में आबंटित किया गया है. इस माध्यम् से प्रतिवर्ष 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार दिया जायेगा. इसके साथ ही संक्रमण कालखंड में केन्द्र सरकार 745.59 करोड़ रूपये एवं बिहार सरकार 244.52 करोड़ रूपये दी है.

☞ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण-बिहार राज्य में तीस लाख व्यक्तियों को पक्के मकान के लिए आनलाइन आवेदन किये गए हैं.

☞ बिहार में 1,19,800 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो चुका है एवं 2834 पुलों के भी निर्माण हो चुके हैं. वर्तमान में 7133 किलोमीटर सड़कों का निर्माण तेजी से चल रहा है.

☞ जमुई जिला अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए 914 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं. 312 करोड़ रूपये से 189 नयी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है. इसके अतिरिक्त 602 करोड़ रूपये में 181 का लोकार्पण भी हुआ है. ●

आधुनिक हिलसा के निर्माता

● सोनू यादव

सभी धर्मों की प्रवर्तक की कर्मभूमि, दुनिया को शिक्षा का संदेश देने वाले ज्ञान की धरती नालंदा। हलधर की धरा हिलसा के लोकप्रिय अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार पटेल को केवल सच मासिक पत्रिका के ब्यूरो इन चीफ सोनू कुमार ने अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देखकर उनके कार्यालय में सम्मानित किया। कुछ दिनों पहले केवल सच मासिक पत्रिका का 21वां स्थापना वर्ष पटना के अधिवेशन भवन में मनाया गया था। उस समारोह में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय सरकारी काम में व्यस्तता के चलते शिरकत नहीं कर पाये थे। लोकप्रिय अनुमंडलाधिकारी महोदय सभ्य, सौम्य, शालीन, लोक व्यवहार पदाधिकारी है। प्रशासनिक पदाधिकारी अच्छी नीति, सच्ची नियत से अपने कार्यो

को अंजाम दे रहे हैं। इनके कार्यकाल में सबको न्याय, सबको अधिकार मिलता रहेगा।

सरकार की नीतियों को जमीनी क्रियान्वयन में सबसे अहम और महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। सिविल सेवा में काम करने वाले को लोक सेवक के रूप में जाना जाता है। लोक सेवक सरकार का सबसे प्रत्यक्ष चेहरा है लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी के चलते योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सफलता मिली है। इनके नुमाइंदगी मैं शिक्षा में संपूर्ण सुधार लक्ष्य है हमारा, व्यवस्था में संपूर्ण पारदर्शिता ध्येय है हमारा। वे सदा उपेक्षितों और तिरस्कृतों की आवाज बनकर खड़े रहते हैं कार्य क्षेत्र में। निर्भीक और सूझबूझ वाले पदाधिकारी है। वे एक ग्रेसफुल इंसान भी हैं। लोकप्रिय पदाधिकारी महोदय लोगों की उम्मीद, आकांक्षाओं व अपेक्षाओं पर खरा उतरने में लगातार कोशिश करते रहते हैं। वे लोगों से निरंतर संवाद कायम रखते हैं।●

आर्थिक इकाई पटना ने किया गुड्डू यादव को गिरफ्तार

● संजय शर्मा

आर्थिक अपराध संख्या थानाकांड संख्या 14/26 दिनांक 27/7/2026 अंतर्गत धारा 111 (3) (4) (5)(6)(7) / 336 (2) (3) / 336 (2)(3)/ 340(2)/61[2] BNS 2023 में प्राथमिकी अभियुक्त गुड्डू यादव, पिता बिसुनदेव यादव उर्फ मच्छर यादव, साकिन बोदर, (मिट्टी कुआं) थाना सिकंदरा जिला जमुई। वर्तमान पता 101 एकलव्य कॉलेज बोधवन तालाब जमुई एवं उसके उनके आपराधिक सहयोगियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई का विश्वसनीय सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त अपराध कर्मी अपने सहयोगियों के साथ राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर की है। फर्जी विक्रेता खड़ा कर उसे अपने अथवा अपने किसी परिजनों के नाम पर फर्जी निबंधन दस्तावेज तैयार कराया गया है। यह गिरोह फर्जी दस्तावेज तैयार कर आपराधिक बल प्रयोग से भूमि पर अवैध कब्जा करने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से रंगदारी कर धन उगाही, लूट, अपहरण, हत्या का प्रयास एवं आर्म्स एक्ट सहित कई दर्जनों घटनाओं में संलिप्तता रही है। गुड्डू यादव के द्वारा एक संगठित अपराधिक गिरोह बनाकर विगत 15-16 वर्षों में उसके एवं उसके गिरोह के सदस्यों के द्वारा बड़े पैमाने पर परिसंपत्तियां अर्जित की गई है। यह भी सूचना मिली है कि अपने अपराधिक पृष्ठभूमि एवं आतंक का सहारा लेकर इसके गुड्डू यादव द्वारा राजनीति में भी स्थान बनाने का प्रयास किया गया। गुड्डू यादव की पत्नी श्री मति दुलारी देवी जमुई जिला परिषद की अध्यक्ष है। सूचना सत्यापन में यह पाया गया कि कुख्यात अपराध कर्मी गुड्डू यादव वर्ष 2000 में अपराध जगत में आया एवं इसके विरुद्ध जमुई, लखीसराय नवादा जिले के सिकंदरा, हलसी, कौआकोल ,पकरी बरामा,एवं चंद्रदीप आदि थानों में बर्ष 2000 से अब तक 39 कांड अंकित है। ये कांड हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट, रंगदारी, अपहरण, लूट, लूट की योजना, लोकसेवकों पर हमला, शस्त्र अधिनियम, जमीन पर कब्जा आदि से संबंधित है। इस संगठन गिरोह में शामिल भूषण यादव, ललन यादव, बिपिन यादव, छोटू यादव, बाबूलाल यादव, सहनवाज अली, नेरू खान, प्रवीन मिश्रा, मनोज यादव, राकेश उर्फ सोनू यादव एवं रघुनंदन यादव के विरुद्ध भी जमुई जिलाके आस-पास जिलों में कई कांडों में अंकित पाए गए हैं। इनमें अधिकांश मामलों में न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अपराधकर्मी गुड्डू यादव सहित

इसके गिरोह में शामिल कुल 17 अपराधकर्मियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। गुड्डू यादव के द्वारा स्वयं एवं अपनी पत्नी दुलारी देवी के नाम पर कुल 29 परिसंपत्तियां, जमुई एवं सिकंदरा में जमुई स्थित निबंधन कार्यालय में निबंधित कराया है। इन परिसंपत्तियों का निबंधन मूल्य 2,57,50000 रू० मात्र है, जबकि इस परिसंपत्तियों को सरकारी सर्किल रेट 7,5967000 निर्धारित की गई है। गुड्डू यादव के आपराधिक सहयोगियों के द्वारा अपने तथा अपने परिजनों के नाम पर कुल 61 दस्तावेजों के माध्यम से जमुई स्थित निबंधन कार्यालय में परिसंपत्तियां निबंधित कराई गई। जिसके लिए उन सभी के द्वारा 3,37,78000 सरकारी सर्किल रेट सन्निहित है। इसके अतिरिक्त सत्यापन में गुड्डू यादव एवं उसकी पत्नी दुलारी के पास 10 विभिन्न बैंकों में 10 खाते होने की सूचना है। गुड्डू यादव तथा उसके सहयोगियों ने अमित कुमार भगत, रामविलास यादव, रंजीत केसरी, संजीव कुमार, विशाल कुमार, आफताब खान, अनीश कुमार, छोटन यादव एवं बालेसर महतो। एवं कई अन्य लोगों के नाम पर परिसंपत्तियां निबंधित कराई गई। उपरोक्त प्राथमिकी के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना ने माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पटना से तलाशी अधिपत्र प्राप्त करते हुए आज दिनांक 28/ 7 /26 को सुबह 8:30 बजे प्राथमिकी अभियुक्त गुड्डू यादव एवं कांड में संलिप्त कुल 17 अभियुक्तों तथा (1)बाबूलाल यादव, ललन यादव, पिता बिसुदेव यादव, बोदर ।[2]भूषण यादव, पिता रामस्वरूप यादव दरसंडा, (3)छोटू यादव, पिता नागो यादव, शाकिन खेवसर, (4)बिपिन यादव, पिता सियाराम यादव, शाकिन खेवसर, (5)प्रमोद यादव, पिता लखन यादव, शाकिन सिकंदरा (6)नय्यर खान, पिता नसरूल खान, सिकंदरा, (7)शहनाज खान उर्फ मुनचुन मियां, पिता शाहजहां अली सिकंदरा (8)प्रवीण मिश्रा, पिता कुलदीप मिश्रा, सिकंदरा, (9)राजेश कुमार, सोनू यादव, पिता संजय यादव, शाकिन सिकंदरा, (10)आलोक मिश्रा, पिता प्रमोद चंद्र मिश्रा, सिकंदरा (11)मनोज यादव, प्रकाश यादव, रामडीह, (12)रघुनंदन यादव, पिता रायंदर यादव, पचमहुआ सभी थाना सिकंदरा (13)शंभू यादव, पिता राम खिलावन यादव। बिट्ठलपुर जमुई। (14)मनोज यादव, पिता मुरारी यादव, डूंगरपुर कोला (15)अनुज यादव, टहल यादव, शाकिब इकम्मा थाना चेवाड़ा जिला शेखपुरा के कुल 25 ठिकानों पर विशेष कार्यबल एसटीएफ जमुई एवं शेखपुरा जिला पुलिस के सहयोग से घेराबंदी करते हुए एक साथ तलाशी का कार्य संपन्न किया गया। संगठित अपराधिक गिरोह का आर्थिक हितों पर चोट करती हुई आर्थिक अपराध इकाई विशेष कार्यबल। जमुई एवं सिकंदरा जिला पुलिस की यह एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई है। तलाशी के दौरान प्राथमिक अभियुक्त गुड्डू यादव के सिकंदरा चौक स्थित आवास से 813000 रूपये नकद भूखंड क्रय किए जाने से संबंधित कुल 25 दस्तावेज एग्रीमेंट बरामद हुए हैं। साथ ही एक ट्रैक्टर खरीद किए जाने से संबंधित कागजात बरामद हुए। इनके प्रत्येक मकान से भूखंड क्रय किए जाने से संबंधित कुल 12 कागज विभिन्न बैंकों में कुल 10 पासबुक, एसयूवी, बेलोरो एवं स्कूटी क्रय किए जाने से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। गुडू यादव के सिकंदर थाना मोड़ अवस्थित पेट्रोल पंप के कार्यालय से कुल 14 भूखंड से संबंधित दस्तावेज, 4 बैंक पासबुक एवं कुल 79 राउंड राइफल की गोलियां भी बरामद हुई है। बरामद गोलियों के संबंध में स्थानीय सिकंदर थाना में कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त बाबूलाल यादव के घर की तलाशी में कुल 36 भूखंडों से संबंधित दस्तावेज एग्रीमेंट बरामद हुए हैं। इनके मुख्य आवास से भूखंड क्रय किए जाने से संबंधित कुल 16 कागजात एवं एक स्कार्पियो, वाहन से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। प्राथमिक अभियुक्त बाबूलाल यादव को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक अभियुक्त गुड्डू यादव, बाबूलाल यादव, ललन यादव द्वारा सिकंदर एवं जमुई में आलीशान मकान बनवाए गए हैं जिसका मूल्यांकन आगे कराया जाएगा। जैसे कि जानकारी आर्थिक अपराध इकाई के शाखा के द्वारा दी गई प्राथमिक अभियुक्त भूषण यादव, घर की तलाशी व भूखंड से संबंधित दस्तावेज, बैंक पासबुक आदि बरामद हुए हैं। भूषण यादव को गिरफ्तार

किया गया है। छोटू यादव भी घर की तलाशी में कुल 7 भूखंड से संबंधित दस्तावेज। 5 बैंक पासबुक कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली कमबाइन मशीन क्रय की जाने संबंधी कागजात एवं एक देसी कट्टा एवं दो गोली दो गोली बरामद हुई है। बरामद हथियार के संबंध में स्थानीय थाना द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बीपीन यादव के घर से तलाशी के दौरान 1506500 रू० नगद, भूखंड से संबंधित कागजात एवं बैंक खाता तथा 3 ट्रक जिनके नंबर बीआर 46 1702 बीआर जीरो, 1 जीएफ 9900 एवं बीआर 46 जी 5936 संबंधित कागजात बरामद हुए हैं प्राथमिक अभियुक्त। बिपिन यादव को गिरफ्तार किया गया है। अनुज यादव के घर की तलाशी में दोपहिया वाहन क्रय किए जाने संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इनके नाम पर ही एक फॉर्चूनर वाहन संख्या बीआर 46 एल 0006 खरीदी गई। इसका उपयोग गुड्डू यादव करते हैं। प्रमोद यादव के घर तलाशी में भूखंड से संबंधित कागजात कुल 11 एवं एक स्कार्पियो वाहन जिसका नंबर बीआर 40, बीआर 46 एल 6562 से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। प्राथमिक अभियुक्त प्रमोद यादव को गिरफ्तार किया गया है।

नैयर खान उर्फ नेरू खान के घर में कुल 27 मूल एवं 12 छाया प्रति लिपि भूखंड क्रय करने से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। नैरू खान एवं पत्नी के नाम पर 17 दस्तावेज पाए गए हैं। शहनाज अलीके घर के तलाशी में कुल 950000 रूपये नगद, बैंक से संबंधित दस्तावेज, पासपोर्ट आदि बरामद हुए हैं। प्रवीण कुमार मिश्रा के घर की तलाशी में अंचल कार्यालय, सिकंदरा से संबंधित सरकारी रजिस्टर 2 के कुल 5 वॉल्यूम न्यायालय से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों को प्रेषित किए जाने वाले शील बंद लिफाफे भूखंड से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित कुल 30 दस्तावेज बरामद हुए हैं। बरामद सरकारी अभिलेखों के संबंध में जांच के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। राकेश कुमार उर्फ सोनू यादव के गृह तलाशी में 4 बैंक पासबुक सहित निवेश के कागजात बरामद हुए हैं। प्राथमिक अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सोनू यादव को गिरफ्तार किया गया है। शंभू यादव, बोधवन तलाब, जमुई में अवस्थित घर पर तलाशी में कुल 150000 रू० नगद। निवेश संबंधित कागजात 11 बैंक पासबुक, एक स्कार्पियो, एक ट्रैक्टर खरीद से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। आलोक मिश्रा के घर की तलाशी में भूखंड क्रय किए जाने से संबंधित कागजात निवेश से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। स्थित घर से दो शराब की सील बंद बोतल बरामद हुई, जिनके संबंध में स्थानीय द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की इस कार्रवाई में इकाई के पुलिस अधीक्षक सहित 3 अपर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक कोटि के 18 पदाधिकारी, बड़ी संख्या में निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक एवं अन्य कर्मी शामिल थे। इस कार्रवाई में विशेष कार्यबल एवं जमुई,/ शेखपूरा जिला पुलिस का सहयोग लिया गया। कार्रवाई में उपरोक्त वर्णित 5 प्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी 34,19,500 रू० नगद बरामदगी सहित भारी संख्या में भूखंडों के क्रय किए जाने संबंधी दास्तावेज, वाहनों से संबंधित कागजात एवं निवेश कागजात बरामद हुए हैं। तलाशी की कार्रवाई कुछ स्थान पर जारी है। संगठित आर्थिक अपराध एवं इसमें संलिप्त अपराधियों एवं उनके सहयोगियों, संरक्षणकर्ताओं के विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई, राज्य सरकार के नीति के अनुरूप कार्रवाई कृत संकल्पित है।●

बिहार इलेक्ट्रिक वाहन योजना

● **संजय शर्मा**

बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिए जोर दिया जा रहा है। परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने इस संबंध में जानकारी दी कि खासकर महिला वर्ग को विशेष छूट दी जाएगी। लगभग 12000 रू० प्रति स्कूटी पर एवं बड़ी गाड़ियों का भी प्रावधान है। जिला परिवहन पदाधिकारी सुनील कुमार ने जानकारी दी कि यह सूचना; 06/ योजना-14-14/2025/3747 पटना, दिनांक 15/5/26 के निर्देशानुसार जीवाश्म ईंधन को जारी क्षरण, कीमत में वृद्धि परिवेशीय वायु प्रदूषण, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक कुल नए वाहनों में कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करते हुए वैश्विक अभियान म्ट 30/30 को सहयोग प्रदान करने का लक्ष्य नागरिकों में इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्साहपूर्ण स्वीकारता, ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराने जाने तथा रोजगार सृजन के समग्र दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना लागू की जाती है।

☞ **इस योजना के तहत प्रस्तावित बिहार :-** इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 के अंतर्गत बिहार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय हेतु विनिर्दिष्ट दिशा निर्देश के अनुरूप इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय एवं निबंधन हेतु निम्न रूपेन प्रोत्साहन की राशि दे होगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई सुनील कुमार ने जानकारी दी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रकार में सामान्य वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए इस प्रकार से छूट दी जाएगी। तिपहिया वाहनों पर सामान्य वर्ग 50000 रू० प्रति वाहन और अनुसूचित जाति के लिए 60000 रू० प्रति वाहन की छूट रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहन के प्रकार पर परिवहन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन पर महिलाओं को 12000 रू० प्रतिमाह छूट रहेगी। सामान्य वर्ग के

लिए और पुरुषों को 10000 रू० प्रति वाह न छूट मिलेगी, वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 12000 रू० प्रति वाहन छूट रहेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई ने जानकारी दी कि लगभग मेरे द्वारा 300 चालकों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें 50 से ज्यादा सरकारी वाहनों के चालकों को प्रशिक्षण दिया गया एवं निजी वाहनों के चालक को यह प्रशिक्षण को दिया गया और यह कार्यक्रम दिनांक 26/7/2026 तक लगातार चलाया। जाएगा, जिसमें उनके खाता संख्या लिया जाएगा और साथ ही, अल्पाहार है और 200 रू० प्रोत्साहन राशि भी दिए जाने का प्रावधान है।●

शिक्षा कार्यालय में हो रही मनमानी

● संजय शर्मा

विगत माह जुलाई 2026 के अधिवेशन भवन सचिवालय, पटना में प्रथम महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे केवल सच सम्मान समारोह आयोजित हुआ था। जिसमें केवल सच के संपादक श्री ब्रजेश मिश्र उरवार ने कई ज्वलंत मुद्दे उठाए थे। जिसमें शिक्षा विभाग के मंत्री मिथिलेश तिवारी के साथ कई अन्य मंत्रीगण उपस्थित हुए। अपने कार्यक्रम के क्रम में श्री ब्रजेश मिश्र ने शिक्षा मंत्री के समक्ष कई प्रकार की जानकारियां दी कि आपके स्कूल में कई कार्यक्रम होते हैं इसकी जानकारी पत्रकारों के माध्यम से ही जनता को मिलती है और आप लोगों के आदेश के अनुसार पत्रकार स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, जबकि आप शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई जानकारी कि स्कूल में कई अच्छी-अच्छी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है इसका सत्यापन तो पत्रकारों के माध्यम से ही जनता और आपको दी जाएगी। कई ऐसे मामले हैं जिसमें स्थानीय शिक्षक और प्रभारी अपनी शिकायत लेकर के जिला पदाधिकारी के पास जाते हैं और जो प्रखंड स्तर के पदाधिकारी होते हैं वहीं जांच करते हैं और वही रिपोर्ट अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को देते हैं। मामला वहीं का वहीं रहता है और उनकी जो परेशानियां हैं वह दबी ही रह जाती है मन में। प्रभारी या शिक्षक/शिक्षिका को अपनी परेशानी अवगत कराने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय जाने के पूर्व उन्हें आवेदन देकर छुट्टी लेनी अनिवार्य है नहीं तो उनका मानदेय कट जाएगा या और भी कई तरह के उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर स्कूल समय में शिक्षक और प्रभारी नहीं जा सकते तो रविवार के दिन कम से कम 2 घंटे का समय जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा दिया जाए, ताकि शिक्षक और शिक्षिकाएं/प्रभारी अपनी परेशानी रविवार के दिन अमुक समय में आकर दे सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है पत्रकारों को स्कूल में उन योजनाओं /परेशानियां की जानकारी के लिए सप्ताह या माह में एक-दो दिन के लिए मिलने का अवसर मिले ताकि पत्रकार भी मजबूती से खबर को प्रमुखता से प्रकाशित कर जनता और बिहार सरकार शिक्षा विभाग तक पहुंच सके। प्रधानाध्यापक या प्रभारी शिक्षकों द्वारा आरोप लगाया गया है कि विद्यालय रंग रोगन के जो पैसे आते हैं। उस राशि में से 15% काट लिया जाता है या उन्हें देना पड़ता है। इस संबंध में जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सोनो एवं झाझा से जानकारी लेनी चाहिए तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ने हुए कहा मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप जिला शिक्षा कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। जब पत्रकार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई से जानकारी लेनी चाहिए तो जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई ने भी अपना पल्ला झाड़ने हुए स्पष्ट रूप से कहा कि बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता या बयान नहीं देंगे। अपने मातहत को मौखिक आदेश दिया कि साक्षी देने वाले प्रधानाध्यापक/प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जब पत्रकार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई से पुन: जानकारी लेनी चाहिए कि इसमें प्रधानाध्यापक/प्रभारी का क्या दोष जिसकी जांच के लिए आपके द्वारा कहा जा रहा है? लेकिन वही 15% लेने वाले प्रखंड शिक्षा कार्यालय/वेंडर के द्वारा उगाई पर मौन धारण यह दोहरा रवैया क्यों? यह एक ज्वलंत और सवालिया निशान है शिक्षा तंत्र पर। वही एक मामला वर्ष 2016 का है जिसमें शिक्षिका संगीता कुमारी नवीन प्राथमिक विद्यालय, सबैजोर झाझा का 4 महीने का भुगतान रुका हुआ है। लगभग 10 साल बीत चुके हैं बकाया वेतन के लिए। जबकि शिक्षिका ने लोक शिकायत पदाधिकारी और कई जगह जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी के अलावा भी आवेदन दिया है। लेकिन मामला वहीं का वही है। 10 साल बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी झाझा के द्वारा अपने पत्रांक 450 दिनांक-25/6/26 को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, जमुई को पत्र लिखा की संगीता कुमारी 4 महीने से अनुपस्थित थीं। जबकि उसे वर्ष का विद्यालय से रजिस्टर गायब है। यह अबूझ पहेली है कि एक और संगीता कुमारी अनुपस्थित थी। दूसरी और चिकित्सा अवकाश के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी झाझा पंचायत सचिव, सबैजोर को फोन करना पड़ा की संगीता कुमारी शिक्षिका, सबैजोर को चिकित्सा अवकाश दिया जाए। इसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अहम भूमिका क्यों है चिकित्सा अवकाश के लिए। आवेदन मेरे पास उपलब्ध है जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी झाझा द्वारा फोन से कहा गया कि इन्हें अवकाश देने की कृपा की जाए इसकी जानकारी पंचायत सचिव सबैजोर ने मुझे फोन के माध्यम से दी। मामला 2016 का है और 10 साल बाद जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में चिकित्सा अवकाश के लिए फोन किया जा रहा है। जबकि आवेदन की तिथि 2017 में बहुत ही सूक्ष्म रूप से लिखी गई है। यह कहां तक न्याय संगत है। जब मैंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी झाझा से जानकारी लेनी चाहिए कि आप अवकाश क्यों दिलाना चाहते संगीता कुमारी को उन्होंने फोन काट दिया। शायद यही कारण रहा होगा कि पत्रकारों को स्कूल में जाने से मना किया जाए ताकि वह इस तरह के मामले को उजागर न कर सके। पूर्व में भी सोनो प्रखंड का एक मामला मौखिक आया था जिसमें प्रभारी और शिक्षकों का कहना था की प्रखंड शिक्षा कार्यालय के पदाधिकारी औचक निरीक्षण के नाम पर स्कूल में बराबर आते हैं। जब कोई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी किसी औचक निरीक्षण में जाते हैं तो क्या वह रजिस्टर मेंटेन करके जाते हैं कि मैं आम का स्थान जा रहा हूं। और औचक निरीक्षण में क्या पाया। क्यों आते हैं इसमें स्पष्टता नहीं होती है। इस संबंध में जब मैं पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई दयाशंकर सिंह से बात की तो उन्होंने भी टालमटोल की नीति अपनाई थी। इसी बीच बिहार सरकार शिक्षा विभाग के दिनेश कुमार सचिव/निदेशक ने सभी जिला शिक्षक पदाधिकारी को जानकारी दी की अपने पत्रक 11 बिहार 32 2025 18 11 जिसमें राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को नियमित मासिक वेतन एवं बकाया वेतन का भुगतान करने के संबंध में भी कहा है। भविष्य में शिक्षकों के वेतन का भुगतान अनावश्यक रूप से रोकने की शिकायत प्राप्त होने पर आपको जवाब दे मानते हुए आपके विरुद्ध यथोचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।●

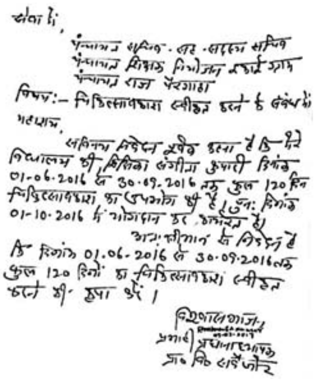

सेवा में,
पंचायत सचिव-सह-सदस्य सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई ग्राम
पंचायत राज पैरगाहा
विषय:- चिकित्सावकाश स्वीकृत करने के संबंध में
महाशय,
सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरे विद्यालय की शिक्षिका संगीता कुमारी दिनांक 01-06-2016 से 30-09-2016 तक कुल 120 दिन चिकित्सावकाश का उपभोग की है। पुनः दिनांक 01-10-2016 में योगदान कर चुकी है।
अतः श्रीमान से निवेदन है कि दिनांक 01.06.2016 से 30.09.2016 तक कुल 120 दिनों का चिकित्सावकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।
विश्वासभाजन
प्रभारी प्रधानाध्यापक
प्रा० वि० सबैजोर

पत्रांक–11/वि0–32/2025 1811
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।
प्रेषक,
दिनेश कुमार, भा0प्र0से0
सचिव–सह–निदेशक, (मा0 शि0)
सेवा में,
राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।
पटना, दिनांक 14/07/2025
विषय– राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के नियमित मासिक वेतन एवं बकाया वेतन का भुगतान करने के संबंध में।
महाशय/महाशया,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग को शिकायत प्राप्त हो रही है कि शिक्षकों के नियमित वेतन एवं बकाया वेतन के भुगतान हेतु विभाग द्वारा राशि आवंटित किए जाने के बावजूद, समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब आपके स्तर से ऐसे लंबित मामलों का सतत अनुश्रवण नहीं किया जाता। शिक्षकों को समय पर वेतन न मिलने से उनमें असंतोष की भावना बढ़ती है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। यह स्थिति राज्य के स्वच्छ प्रशासन के लिए कदापि उचित नहीं है।
अतः निदेशित किया जाता है कि शिक्षकों का नियमित मासिक वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक तथा बकाया वेतन 15 तारीख तक करना सुनिश्चित करें। साथ ही, ऐसे लंबित मामलों का साप्ताहिक अनुश्रवण करें और अधिक समय से लंबित मामलों के कारणों की समीक्षा कर, इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध यथोचित अनुशासनिक कार्रवाई करें।
भविष्य में शिक्षकों के वेतन भुगतान को अनावश्यक रूप से रोकने की शिकायत प्राप्त होने पर, आपको जवाबदेह मानते हुए आपके विरुद्ध यथोचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
विश्वासभाजन
(दिनेश कुमार)
सचिव–सह–निदेशक, (मा0 शि0)

100 दिनों की सेवा का संकल्प बना विकास की पहचान

● अब्दुल कैय्यूम

सेवा, संकल्प एवं समर्पण के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर बिहार सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समाहरणालय स्थित परमान सभागार, अररिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी अररिया विनोद दूहन, माननीय विधायक जोकीहाट मोहम्मद मुर्शीद आलम, माननीय जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष आशीष कुमार पटेल, श्री नारायण कुमार झा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं तथा आगामी कार्य योजनाओं पर आधारित संबोधन का सीधा प्रसारण देखा गया। साथ ही जिला स्तर पर तैयार "जांच एवं उपचार – चिकित्सा आपके द्वार" अभियान एवं भूमि के डिजिटाइजेशन कार्य का डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम के समापन उपरांत जिला पदाधिकारी विनोद दूहन ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नई सरकार द्वारा आमजनों के हित में संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अररिया जिला पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 100 दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार, खेल, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। जिला पदाधिकारी ने विशेष रूप से जिले में चल रही नवाचारी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि "जांच एवं उपचार – चिकित्सा आपके द्वार" अभियान अररिया में एक नवाचारी पहल के रूप में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर 30 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोगों की रक्तचाप (बीपी), मधुमेह (शुगर), कैंसर, मोतियाबिंद एवं एनीमिया की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 5 लाख 47 हजार लोंगो का स्क्रीनिंग उपरांत अब तक 5,190 हाईपरटेंशन, 4,203 मधुमेह, 616 एनीमिया, 369 मोतियाबिंद, 10 मुंह के कैंसर, 10 स्तन कैंसर तथा 6 गर्भाशय कैंसर के मरीजों की पहचान कर उनका उपचार स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रारंभ कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले 100 दिनों इसके साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10,237 आयुष्मान भारत (PM JAY एवं CM JAY) कार्ड तथा 528 आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल 10,765 लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया है। उन्होंने जिले में सरकारी भूमि के डिजिटाइजेशन कार्य को भी प्रशासन की एक महत्वपूर्ण नवाचारी पहल बताया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नरपतगंज, फारबिसगंज, कर्सुाकांटा एवं सिकटी प्रखंडों में सरकारी भूमि के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इसे अन्य प्रखंडों में भी सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान में रानीगंज प्रखंड में यह कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल से भविष्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एवं अन्य विवादों की रोकथाम तथा विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा विगत 100 दिनों की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए बताया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिले में 12 सरस्वती विद्यालय निकेतन (आदर्श विद्यालय) संचालित हैं, जिनमें 2,886 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। वहीं जिले के जोकीहाट, पलासी, भरगामा, सिकटी एवं नरपतगंज में नवस्थापित 5 राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र भी प्रारंभ हो चुका है, जहां 512 छात्र-छात्राओं का नामांकन हुआ है। इससे जिले के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा आगामी 30 दिनों में चिन्हित स्कूलों में एक-एक पदाधिकारियों के द्वारा अवलोकन कराए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, ताकि स्कूली शिक्षा को ओर बेहतर बनाया जा सका है। विगत 100 दिनों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से 5,580, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से 4, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 262, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा

पेंशन योजना से 207, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना से 700 तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना से 2 नए लाभुकों को आच्छादित किया गया है। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक 60 पंचायतों एवं नगर निकायों के 44 वार्डों में शिविर लगाए गए। सहयोग शिविर पोर्टल के माध्यम से अबतक 8,315 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 7,356 शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन किया जा चुका है। पंचायत विकास दिवस के अंतर्गत जिले की सभी 211 पंचायतों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिससे पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं जनभागीदारी सुनिश्चित हो रही है। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी ने बताया कि खेल विभाग के अंतर्गत जिले की सभी 211 पंचायतों में पंचायत स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में अंडर-14, अंडर-16 एवं अंडर-19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने खो-खो, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद एवं रस्साकशी सहित विभिन्न खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा आगे खेल को लेकर आगे दो-दो पंचायत, फिर दो-दो प्रखंडों का एक साथ प्रतियोगिता आयोजित कराने की योजना है। उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा एवं समृद्धि यात्रा के अंतर्गत जिले में 620 व्यक्तियों की क्षमता वाले अटल कला भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो भविष्य में सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 06 प्रखंड कार्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सैफगंज से सुकेला पथ और बैरगाछी से कुआड़ी सिकटी पथ का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। पर्यटन विभाग की ओर से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सुंदरनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने बताया कि कृषि विभाग के अंतर्गत 1,83,504 किसानों का किसान रजिस्ट्री कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिससें किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जा सकेगा। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत पिछले 100 दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 14,275 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। वहीं आईएचएचएल (IHHL) योजना के अंतर्गत 1,637 शौचालयों का निर्माण भी पूर्ण कराया गया है। उद्योग, निवेश एवं रोजगार के क्षेत्र में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 264, बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 6, पीएमईजीपी (PMEGP) के तहत 3, पीएमएफएमई (PMFME) के तहत 10, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 6 लाभुकों का चयन किया गया है। इस प्रकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुल 294 लाभार्थियों को स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने का कार्य किया गया है। इस क्रम में पूर्व में जिला गंगा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बताया गया कि जिले की प्रमुख नदियों के संरक्षण, स्वच्छता की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नदियों के किनारों पर डॉल्फिन व्यू प्वाइंट एवं टूरिज्म स्पॉट जैसे स्थल विकसित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में टूरिज्म स्पॉट को बढ़ावा देने के लिए मीरगंज एवं त्रिशूलिया घाट पर टूरिज्म स्पॉट निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक उनका लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। इसी सोच के साथ आप सभी के सहयोग से नवाचार, तकनीक एवं सुशासन के माध्यम से जिले के समग्र विकास की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर जिला एवं प्रखंड स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी एवं उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा 14 लाभुकों के बीच बासगीत पर्चा का वितरण किया गया। साथ ही “जांच एवं उपचार - चिकित्सा आपके द्वार” अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर जिलाधिकारी द्वारा श्री रविकांत कुमार, सीएचओ एवं श्रीमती रानी कुमारी, ए0एन0एन0 को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। मौके पर माननीय जनप्रतिनिध गण के साथ अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता जि0लो0शि0नि0 पदाधिकारी, अपर समाहर्ता अपादा प्रबंधन, उप विकास आयुक्त सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी गण उपस्थित थे।●

पलासी बीडीओ को दी गयी भावभीनी विदाई

● **अब्दुल कैय्यूम**

अररिया जिला के पलासी प्रखंड में गत 28 जुलाई को बीडीओ आदित्य प्रकाश के स्थान्तरण के बाद प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार मे विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें स्थानांतरित बीडीओ आदित्य प्रकाश को भावभीनी विदाई दी गयी। समारोह की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सदानंद यादव ने की। समारोह में मुख्य रूप से वक्ताओं में प्रखंड प्रमुख सदानंद यादव, थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार, एमओ कुमुद सिंह,मुखिया कृपानंद सिंह सरदार, समद अली, मुखिया प्रतिनिधि मगफुर आलम, जितेंद्र मल्लिक पंकज कुमार, चंदन कुमार, मुकेश कुमार, इनतखाब, निधि कुमारी, राहिल आलम आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में बीडीओ सहित 36 कर्मियों को स्थान्तरण के बाद विदाई दी गयी। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने स्थानांतरित बीडीओ के कार्यकाल की प्रशंसा

करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तत्पश्चात सभो ने स्थानांतरित बीडीओ को अंगवस्त्रादि भेंट कर भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम के दौरान बीडीओ ने नम आंखों से अपने कार्यकाल के अनुभव व्यक्त किये। इस क्रम में उन्होंने निर्वाचन में पदस्थापित शिक्षकों को भी प्रसंशा की। वही प्रमुख प्रतिनिधि सदानंद यादव ने बीडीओ के कार्यकाल की भूरी भूरी प्रसंशा की। इस अवसर पर प्रेम प्रकाश दास, मोहम्मद वसीम, राहिल परवाज आदि मौजूद थे।●

नए डिग्री कॉलेजों में पठन-पाठन का शुभारंभ

● अब्दुल कैय्यूम

राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा भागलपुर जिले के गोराडीह स्थित नवस्थापित डिग्री कॉलेज, कासिल परिसर से राज्यभर के 211 नए डिग्री कॉलेजों में पठन-पाठन कार्य का शुभारंभ किया। इसी क्रम में अररिया जिले के 05 प्रखंडों में नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में भी शैक्षणिक सत्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिले में जिन महाविद्यालयों में पठन-पाठन शुरू हुआ, उनमें राजकीय डिग्री महाविद्यालय जोकीहाट, राजकीय डिग्री महाविद्यालय पलासी, राजकीय डिग्री महाविद्यालय भरगामा, राजकीय डिग्री महाविद्यालय सिकटी तथा राजकीय डिग्री महाविद्यालय नरपतगंज शामिल हैं। इन महाविद्यालयों के प्रारंभ होने से जिले के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री के राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोकीहाट प्रखंड स्थित प्लस टू उमानाथ उच्च विद्यालय, उदाहाट में लाइव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर माननीय सांसद अररिया प्रदीप कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी अररिया विनोद दूहन, जोकीहाट के माननीय विधायक मोहम्मद मुर्शीद आलम, नामांकित छात्र-छात्राएं, उनके अभिभावक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया और नए महाविद्यालयों के शुभारंभ का स्वागत किया।

वहीं, जिले के अन्य संबंधित प्रखंडों में आयोजित कार्यक्रमों में जिला पदाधिकारी द्वारा

नामित पदाधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लेकर नव नामांकित विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि नए राजकीय डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना से ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह पहल राज्य सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने तथा युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा से जोड़ने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी वही पलासी प्रखंड अंतर्गत प्लस टू हाई स्कूल डाला परिसर में बुधवार को राजकीय डिग्री महाविद्यालय सत्ररम्भ सह उनमुखीकरण कार्यक्रम का का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा विधिवत तरीके से फीता काट कर किया गया। जिस का वर्चुअल देखा गया। इस अवसर पर एडीएम नवनील कुमार, बीडीओ आदित्य प्रकाश, बीपीआरओ अखिलेश कुमार, प्राचार्य मनोज कुमार सिंह,विधायक प्रतिनिधि इरफान सलीम,अजहर मुर्शीद,प्रोफेसर अवनीश सुमन, नोमान हैदर, शमीम अख्तर, शाद आलम, रामानंद सदानंद मंडल आदि मोजूद थे। मौके पर डिग्री कॉलेज के प्राचार्य मनोज कुमार सिंह ने कहा कि राजकीय डिग्री कॉलेज में आज से बच्चो का पठन पाठन शुरू कर दिया गया हैं। उन्होंने बताया कि इस सत्र मैं अब तक 98 छात्रों का नामांकन हुआ हैं। जिस मे 42 छात्र व 56 छात्रओं की संख्याहै। प्राचार्य श्री सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में विभाग द्वारा उन्हें चार कमरा आवंटित हुआ हैं। जिस में एक प्राचार्य कार्यालय, एक ऑफिस कार्यालय तथा दो अन्य कमरों में छात्रों का पठान पठान शुरू होगा। नवपदस्थापित डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल डा मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पलासी प्रखंड 21 पंचायतों में तीन लाख की आवादी में डिग्री कॉलेज खुलने से अब यहां का बच्चों का स्नातक की शिक्षा के अलावे एनसीसी, खेल, कूद के अलावे डिग्री कॉलेज के माध्यम से बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा।●

काली मंदिर परिसर दुकानदार संघ का गठन

● अब्दुल कैय्यूम

अररिया जिला के पलासी प्रखंड मुख्यालय स्थित काली मंदिर परिसर में 07 अगस्त को मंदिर परिसर स्थित दुकानदारों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महेंद्र यादव ने की। बैठक में पुरानी दो कमेटी को भंग करते हुए नई कमेटी के गठन को लेकर वोटिंग प्रक्रिया कराई गई। इस क्रम में दुकानदार संघ के अध्यक्ष पद पर तारिक मोबीन उर्फ चुन्ना तथा अरुण मंडल के बीच मतदान हुआ। जिस में तारिक मोबीन ने अरुण मंडल को तीन मतों से हराकर विजय हुए। तारिक मोबीन उर्फ चुन्ना को 79 मत प्राप्त हुए जबकि अरुण मंडल को 76 मत मीले। सचिव पद पर विनोद साह को 80 जबकि संजय पंजियार को 74 मत मिले। विनोद साह छह मत से विजयी घोषित किये गए। वही कोषाध्यक्ष पद पर रूपेश कुमार को 85 तथा सदानंद मंडल को 71 मत प्राप्त

हुए। इस प्रकार कोषाध्यक्ष पड़ पर रूपेश कुमार विजयी घोषित हुए। मतदान प्रक्रिया में करीब 157 दुकानदारों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रमुख सह काली मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सदानंद यादव, सचिव गणेश भगत, शंकर भगत, गौतम भगत, मिथुन भगत,श्याम लाल साह, श्याम प्रसाद रजक, बिहारी ठाकुर, श्री सदानंद यादव गणेश भगत,शंकर भगत ,गौतम साह ,राजा भगत ,सुनील भगत , दिलीप भगत, जीवन लाल साह, लक्ष्मण ठाकुर, मुन्ना, आदि दुकानदार उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित सभी दुकानदारों ने विजय समिति के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। नव गठित संघ के अध्यक्ष तारिक मोबीन उर्फ चुन्ना ने कहा कि काली मंदिर परिसर के विकास, स्वच्छता, सुरक्षा, दुकानदारों के हितों की रक्षा तथा आपसी सहयोग के साथ कार्य करने उनकी प्राथमिकता होगी। बैठक में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएँ।●

निराशा की हत्या कर शव को बधार में फेंका

● अब्दुल कैय्यूम

अररिया जिला के पलासी थाना क्षेत्र के ब्रह्कुम्बा पंचायत के तरबी और डुमरिया गांव के बीच घर से करीब 500 मीटर दूरी पर 26 जुलाई रविवार को सुबह बधार के धान के खेत के मेड़ पर एक 18 वर्षीया किशोरी का लाश मिली। किशोरी के शव मिलने की खबर फैलते ही गांव के लोगों की भीड़ घटना स्थल पर लगने लगी। शव की पहचान तरबी वार्ड संख्या एक निवासी बालेश्वर यादव उर्फ भूटाई यादव की पुत्री निराशा कुमारी 18 (वर्षीय) के रूप में की गई। शव मिलते ही मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया। शव को देखने के लिये दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतका के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार 18 जुलाई शनिवार की शाम के करीब आठ बजे निराशा कुमारी शौच के लिए घर से पूरब सड़क तरफ निकली। काफी देर बाद तक घर नहीं आई तो परिवार के लोगों द्वारा खोजबीन की जाने लगी। रविवार 19 जुलाई को भी दिन भर खोजबीन की गई परन्तु कही कुछ पता नहीं चल पाया। 20 जुलाई को परिजनों द्वारा स्थानीय थाना में गुमशुदगी की सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस

पीड़ित परिवार के घर पहुंच कर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कहीं प्यार मोहब्बत का तो मामला नहीं है तो परिवार के लोगों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इस बाबत थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि लड़की के परिजनों द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। केवल गायब होने की सूचना दी गई थी। लाश मिलने के बाद तरबी सहित आस पास के गांव में अफरा- तफरी मच गया। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। मृतका की मां सरोजनी देवी ने कहा कि मेरी बेटी का किसी लड़का का कोई चक्कर नहीं था। चार बहन और एक भाई समेत पांच भाई बहनों में निराशा कुमारी सबसे छोटी थी। निराशा उत्क्रमित मध्य विद्यालय तरबी में आठवीं क्लास में पढ़ती थी। लाश मिलने के बाद स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया है। इधर लड़की के गायब होने तथा एक सप्ताह बाद किशोरी के शव मिलने को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस घटना का पर्दाफाश करने व दोषी को सजा दिलाना पुलिस के लिये कड़ी चुनौति साबित होगी। इस मामले को लेकर मृतिका के पिता बालेश्वर यादव ने पलासी थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई हैं।

☞ **पुलिस अभी तक मामले का नहीं कर सका उद्‌भेदन :-** हत्यारा आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। परिजनों ने हत्यारे को अबिलम्ब गिरफ्तार की मांग की हैं। इधर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई हैं। दोषी कोई भी होगा बख्शा नही जायेगा, शीघ्र सलाखो के पीछे भेजा जायेगा।●

सगी माँ और बहन ही निकली जुमनी की कातिल

● अब्दुल कैय्यूम

एक कहावत है कि मां की ममता और बहन का स्नेह दुनिया में सबसे पवित्र होता है, लेकिन अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के हैय्याधार गांव से सामने आई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात ने इस रिश्ते को तार-तार कर दिया है। 24 घंटे पहले हुई बीबी जुमनी की नृशंस हत्या की गुत्थी जब पुलिस ने सुलझाई, तो हकीकत जानकर हर कोई सन्न रह गया। जुमनी की जान किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही कलियुगी मां फितमा और सगी बहन आशियाना ने ली थी। मृतका के पिता मोहसीन द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, इस खौफनाक साजिश की वजहें बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली हैं। प्राथमिकी में खुलासा किया गया हेकि जुमनी मंदबुद्धि और दिखने में सामान्य नहीं थी। उसकी शादी न हो पाने के कारण परिवार को लगातार समाज के तानों का सामना करना पड़ता था, जिससे घर में रोज क्लेश होता था। इसके साथ ही दोनों बहनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर तीखी बहस होती रहती थी। इस बीच 2 अगस्त को पड़ोसी अजीज और उनके

परिवार से बकरी चराने को लेकर विवाद व धक्का-मुक्की हुई थी। मां-बेटी ने एक तीर से दो शिकार करने का मन बनाया। एक तरफ जुमनी को रास्ते से हटाना और दूसरी तरफ इस हत्या का इल्जाम पड़ोसी दुश्मनों पर गढ़कर उनसे बदला लेने की साजिश रची। इसी साजिश के तहत मां और बहन ने किसी बाहरी व्यक्ति की मदद से धारदार हथियार से जुमनी का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही जोकीहाट थानाध्यक्ष राजीव कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और साक्ष्य जुटाए। थानेदार श्री झा ने बताया कि पुलिसिया जांच और तकनीकी साक्ष्यों के सामने जब आरोपियों से पूछताछ शुरू हुई, तो मां-बेटी ज्यादा देर टिक न सकीं और अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने कातिल मां-बेटी की निशानदेही पर घर से ही हत्या में प्रयुक्त धारदार दबिया और कचिया बरामद कर लिया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार दोनो आरोपियों को पुलिस पुछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक तरफ जहां पूरा इलाका इस कलयुगी घटना से सख्ते में है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना हो रही है।●

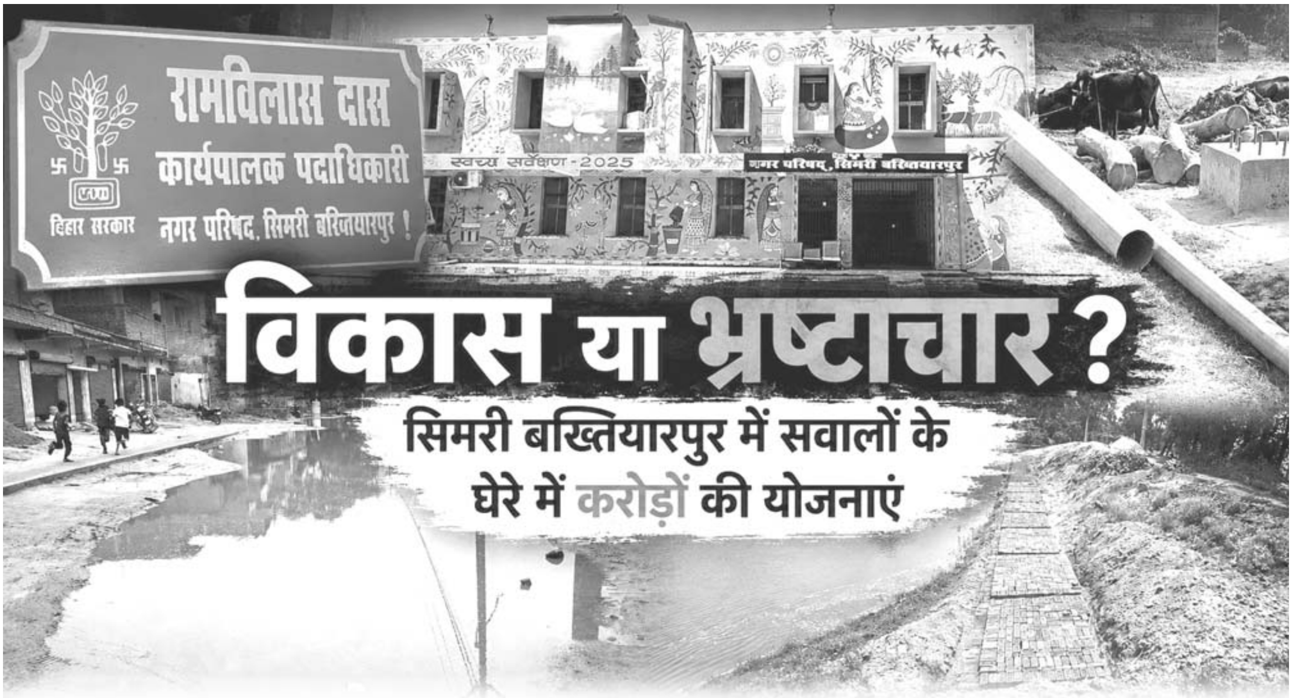

● धर्मेन्द्र सिंह

सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद इन दिनों विकास योजनाओं से अधिक उन योजनाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चर्चा में है। एक ओर बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने हाई मास्ट लाइट योजना में 1.54 करोड़ रुपये के कथित गबन की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों रुपये की लागत से संचालित तालाब जीर्णोद्धार और सड़क निर्माण योजनाओं पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लगातार सामने आ रहे आरोपों ने नगर परिषद की कार्यशैली और विकास कार्यों की पारदर्शिता पर बहस तेज कर दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त सचिव सुनील कुमार द्वारा 21 जुलाई 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि सावन मेला से पूर्व हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए चयनित एजेंसी मेसर्स श्री राम एंटरप्राइजेज, हनुमानगढ़ (राजस्थान) को कार्य पूर्ण किए बिना ही नगर परिषद द्वारा पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया। विभाग ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें अधीक्षण अभियंता हरेंद्र कुमार उपाध्याय, सहायक अभियंता अमित कुमार और प्रशाखा पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार साह को शामिल किया गया है। समिति को 14 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। इस मामले को लंबे समय से उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता एवं युवा नेता पुनपुन यादव ने इसे जनता की जीत बताते हुए कहा कि उन्होंने आरटीआई और दस्तावेजों के आधार पर इस कथित वित्तीय अनियमितता को उजागर किया था। उनका आरोप है कि मामला उठाने के बाद उनके विरुद्ध दो प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

उन्होंने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और सरकारी राशि के गबन के आरोप में कार्रवाई, भुगतान की राशि की ब्याज सहित वसूली तथा उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की है। इधर, नगर परिषद की निविदा संख्या 06/25-26 के तहत लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत से पांच तालाबों के जीर्णोद्धार एवं छठ घाट निर्माण कार्य भी विवादों में है। आरोप है कि कुछ कार्य बिना विधिवत एकरारनामा किए ही शुरू करा दिए गए। वार्ड संख्या-14 स्थित रंगिनिया पोखर में लगभग 78.84 लाख रुपये की योजना के तहत निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने प्राक्कलन के विपरीत और घटिया गुणवत्ता का कार्य किए जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि कार्यस्थल पर सूचना पट्ट तक नहीं लगाया गया है, जिससे योजना की स्वीकृति, लागत और संविदा संबंधी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो सकी। आरोप यह भी है कि प्राक्कलन के अनुसार पहले तालाब का पानी निकालकर पाइलिंग और अन्य तकनीकी प्रक्रिया पूरी की जानी थी, लेकिन बिना पानी निकाले ही ईंट सोलिंग का कार्य शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने पूरे निर्माण की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने की मांग की है। वहीं, नगर परिषद क्षेत्र में बनहा चौक हनुमान मंदिर से कानू टोला, हाई स्कूल पोखर होते हुए स्टेशन चौक तक प्रस्तावित 1.55 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना भी सवालों के घेरे में है। सावन में कांवरियों की सुविधा को देखते हुए अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान जल्द निर्माण शुरू होने और सड़क को यात्रा योग्य बनाने का दावा किया था। लेकिन सावन का पहला सोमवार बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं हो सका। जलजमाव की समस्या जस की तस बनी हुई है

और स्थानीय लोगों को घुटने भर पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इन सभी मामलों में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राम विलास दास का पक्ष जानने के लिए कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। ऐसे में उनका पक्ष उपलब्ध नहीं हो पाया। लगातार उठ रहे सवालों और विभागीय जांच के बीच अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच समिति की रिपोर्ट क्या निष्कर्ष देती है और प्रशासन विकास योजनाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या कदम उठाता है। फिलहाल, सिमरी बख्तियारपुर में विकास कार्यों से अधिक उनकी गुणवत्ता, वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही चर्चा का विषय बने हुए हैं।●

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा देशी गोपालन

● संजीव कुमार झा

पशुपालकों, कृषकों और दुग्ध उत्पादकों के लिए बिहार सरकार स्वरोजगार और आय में वृद्धि के लिए सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। इसकी वजह से प्रदेश में देशी गोपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक प्रमुख जरिया बन रहा है। गव्य विकास निदेशालय द्वारा चलाई जा रही 'देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना' के तहत सरकार साहीवाल, गिर और थारपारकर जैसी देसी नस्ल की 2 या 4 गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने पर पशुपालकों को 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है। मधेपुरा जिला के पशुपालक भी इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं।

दरअसल, गव्य विकास निदेशालय के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए मधेपुरा जिले में कुल 40 पशुपालकों (डेयरी इकाइयों) को 'देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना' का लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया था। दिसंबर 2025 से मधेपुरा के जिलाधिकारी के रूप में पदभार संभाल रहे अभिषेक रंजन कहते हैं कि हालांकि इस लक्ष्य को अलग-अलग श्रेणियों (2 गाय और 4 गाय की इकाई) और सामाजिक वर्गों के आधार पर बांटा गया है। इसके तहत दो (02) देशी गाय की इकाई के लिए कुल 25 पशुपालक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 11 पशुपालक, अनुसूचित जाति के 7 पशुपालक और सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के 7 पशुपालकों को लाभ दिया जाएगा। जबकि, चार देशी गायों के कुल 15, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 5, अनुसूचित जाति के 2 पशुपालक और सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के 8 पशुपालकों को लाभार्थी के रूप में चयन किया गया है। जहां तक बात वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में पशुपालकों को 'देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना' का लाभ देने की बात है, तो अभी तक सरकार की ओर से इसका कोई विधिवत आंकड़ा पेश नहीं किया गया है। जिलाधिकारी बताते हैं कि चूंकि अभी भी जिले में पिछले वित्तीय वर्ष (2025-2026) के तहत स्वीकृत 40 पशुपालकों के लक्ष्य पर ही काम चल रहा है, इसलिए नए वित्तीय वर्ष (2026-2027) के आवेदन और लक्ष्य फिलहाल स्पष्ट नहीं किए गए हैं। हालांकि, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार बजट में पशुपालन और डेयरी आधारित रोजगार योजनाओं को मंजूरी अवश्य दे दी गई है, लेकिन मधेपुरा जिले का सटीक कोटा (लक्ष्य) अभी अस्पष्ट है। इसके बावजूद सूत्रों का मानना है कि पिछले ट्रेंड को देखते हुए मधेपुरा जिले के लिए यह लक्ष्य 40 से 50 डेयरी इकाइयों, यानी पशुपालकों के बीच रहने की उम्मीद है।

जहां तक श्देसी गौपालन प्रोत्साहन योजनाश के तहत पशुपालकों को मिलने वाले अनुदान का सवाल है, तो इसके तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को कुल लागत पर 75 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है, जबकि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है। इस योजना के लिए लाभार्थियों का चयन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है। जिलाधिकारी अभिषेक रंजन कहते हैं कि सरकार अधिक से अधिक किसानों को देसी गायों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत अनुदान की प्रक्रिया भी वर्गानुसार अलग-अलग है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 50% अनुदान का प्रावधान है, वहीं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है। हालांकि, इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं जिसके तहत अनुदान के लिए आवेदन करने वाले किसान के पास गव्य विकास कार्यालय से प्रशिक्षित पशुपालक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं, दूध आपूर्ति करने वाली समिति का सदस्य होने का रसीद भी आवश्यक है। जिलाधिकारी कहते हैं कि महिलाएं भी 'देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना' से जुड़ सकती हैं, लेकिन उनके लिए जीविका समूह से जुड़ा होना अनिवार्य है, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। 'देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना' के तहत पशुपालकों को केवल सरकारी अनुदान ही प्राप्त नहीं होता है, बल्कि सरकार की ओर से पशुओं के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए पशु चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। जिलाधिकारी अभिषेक रंजन कहते हैं कि मधेपुरा जिले में कुल 26 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं, जो टीकाकरण और चिकित्सीय परामर्श देते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के घर-घर तक इलाज पहुंचाने के लिए 13 मोबाइल वेटरनरी यूनिट काम कर रही हैं, जबकि पशुओं के बीमार होने पर किसान टोल-फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके घर पर मुफ्त एम्बुलेंस और डॉक्टर की आपात सहायता भी ले सकते हैं।●

चिकन नेक के मुहाने पर जमीन का खेल

● धर्मेन्द्र सिंह

देश की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ भूभाग ऐसे हैं, जिनका महत्व केवल भौगोलिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी होता है। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम बोलचाल में 'चिकन नेक' कहा जाता है, ऐसा ही एक इलाका है। करीब 20 किलोमीटर चौड़ा यह संकरा गलियारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग है। इसके पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश होने के कारण यह क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। इसी कॉरिडोर के प्रवेश क्षेत्र में बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित भेलागुड़ी मौजा में भारतीय सेना का नया सैन्य स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन प्रस्तावित सैन्य स्टेशन से पहले यहां

उम्रः– 26 वर्ष पति का नामः– मेनुद्दीन (MENUDDIN) जातिः– सुरजापुरी (मुस्लिम) पेशाः– खेती वगैरह, स्थाई पता/ग्राम मुहल्लाः– भेलागुड़ी थानाः– सुखानी (ठाकुरगंज) जिलाः– किशनगंज राज्यः– बिहार राष्ट्रीयताः– भारतीय नागरिक। आधार नं0 8851 2837 9577

क्रेता की विवरणीः–

(i) लेख्यधारी (क्रेता) का नामः– इमरान प्रतापगढी (IMRAN PRATAPGHARHI) उम्रः– 38 वर्ष पिता का नामः– मोहदम्मद इलियास खान (MOHDAMMAD ILIYAS KHAN) जातिः– खान (मुस्लिम) पेशाः– खेती वग़ैरह व पारलियामेंट मेंमबर स्थाई पताः– ग्राम/मुहल्लाः– चमरूपुर शुक्लान, प्रतापगढ, उत्तर प्रदेश– 230144 राष्ट्रीयताः– भारतीय नागरिक। आधार नं0 2159 0722 1279 PAN N0- AUCPK1210A मोबाईल नं0 7827768809

लेख्य का प्रकारः– निर्विवाद बिक्रय–पत्र (Absolute Sale Deed)

बिक्रय मूल्यः– 8,53,000/– (आठ लाख तिरेपन हजार) रूपया मात्र।

बिक्री जमीनः– 14 डी0 643 वर्गकड़ी (चौदह डिसमील छः सौ तैंतालीस वर्गकड़ी) मात्र।

No. : 260500188504 Deed Type : Sale/Conveyance Deed Sub Type : Sale
1418 Serial No. : 1422 Book No. : 1 From Page : 85 To Page : 96

Registering Officer, T

from https://enibandhan.bihar.gov.in on ... 2026 10:11 AM

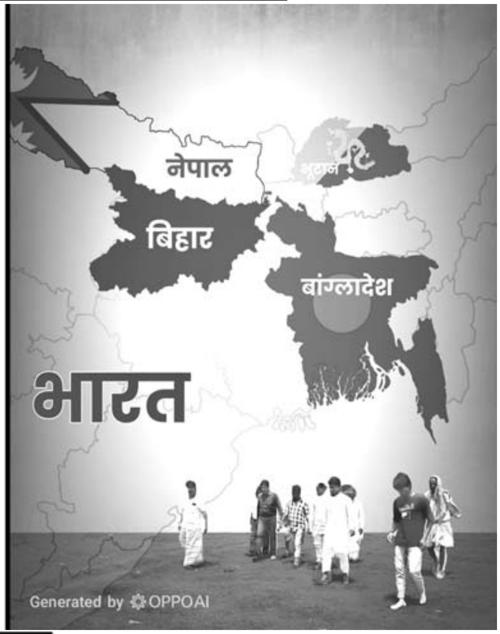

खरीदार का नाम	दर्ज स्थायी पता	खरीदी गई कुल भूमि
इमरान प्रतापगढ़ी	चमरूपुर शुकुलान, जिला- प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)	25.93 एकड़ (दान + खरीदी गई जमीन)
मोहम्मद सलमान खान	24-F, सेक्टर-7, जसोला विहार, दक्षिण दिल्ली	14.09 एकड़
मोहम्मद सुल्तान	चमरूपुर शुकुलान, जिला- प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)	13.93 एकड़
सुलेमान खान	चमरूपुर शुकुलान, जिला- प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)	13.12 एकड़
मोहम्मद शमीम	जसोला, दक्षिण दिल्ली	11.72 एकड़
तश्कील अहमद	चमरूपुर शुकुलान, जिला- प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)	10.18 एकड़
मोहम्मद अनस	मऊ (उत्तर प्रदेश)	9.05 एकड़

हुई बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद-बिक्री ने प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार रक्षा संपदा विभाग ने लगभग 189. 68 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहित कर सेना को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। सितंबर 2025 में सेना मुख्यालय से परियोजना को स्वीकृति मिली। इसके बाद अक्टूबर 2025 से भूमि निरीक्षण शुरू हुआ और जनवरी-फरवरी 2026 तक अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी प्रक्रिया आगे बढ़ने के तुरंत बाद, 11 फरवरी 2026 से प्रस्तावित क्षेत्र में तेजी से जमीन की रजिस्ट्रियां शुरू हो गईं। 28 मार्च 2026 को एक ही दिन कई बड़े सौदों का पंजीकरण हुआ। दस्तावेज बताते हैं कि कुल 98.02 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सात बाहरी खरीदारों के नाम दर्ज हुई। रजिस्ट्री रिकॉर्ड के अनुसार सबसे अधिक भूमि मोहम्मद सलमान खान, मोहम्मद सुल्तान, सुलेमान खान, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद अनस, तश्कील अहमद तथा उत्तर प्रदेश के एक राज्यसभा सांसद के नाम दर्ज हुई। सांसद के नाम पर कुल 25.93 एकड़ भूमि दर्ज है, जिसमें लगभग 20 एकड़ दान पत्र के माध्यम से प्राप्त बताई गई है। हालांकि दस्तावेजों में दर्ज व्यक्ति और संबंधित राज्यसभा सांसद एक ही हैं या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। भेलागुड़ी के ग्रामीणों का दावा है कि जमीन खरीदने वालों ने गांव में कॉलेज और स्पोर्ट्स

अकादमी बनाने का भरोसा दिया था। इसी आश्वासन के आधार पर कई लोगों ने जमीन बेची, जबकि कुछ परिवारों ने दान भी दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें सेना के कैंप से आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि संभव हो तो अधि ग्रहण के लिए वैकल्पिक भूमि चुनी जाए, ताकि उनके पुनर्वास और आजीविका पर असर कम पड़े। दूसरी ओर, ठाकुरगंज के अंचलाधिकारी मृत्युंजय कुमार का कहना है कि सैन्य स्टेशन का मामला अभी प्रक्रियाधीन है और लगभग 200 एकड़ भूमि के सर्वेक्षण का कार्य जारी है। उनके अनुसार अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू इसकी टाइमलाइन है। जिस समय सेना के लिए भूमि चयन और अधिग्रहण की प्रक्रिया सरकारी स्तर पर आगे बढ़ रही थी, उसी दौरान प्रस्तावित क्षेत्र में बाहरी खरीदारों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीद ली गई। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या परियोजना से जुड़ी जानकारी पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच गई थी, या यह केवल संयोग था। यदि संबंधित विभागों को इसकी जानकारी थी तो रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने या विशेष निगरानी क्यों नहीं की गई? मामला केवल जमीन खरीदने तक सीमित नहीं है। यदि खरीदी गई भूमि अधिग्रहण क्षेत्र का हिस्सा बनती है, तो भविष्य में मिलने वाले करोड़ों रुपये के मुआवजे का लाभ मूल भू-स्वामियों को मिलेगा या बाद में जमीन खरीदने वालों को यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी नागरिक को कानूनी रूप से जमीन खरीदने का अधिकार है। लेकिन जब मामला देश के सबसे संवेदनशील सामरिक क्षेत्रों में प्रस्तावित सैन्य स्टेशन का हो, तब हर भूमि लेन-देन स्वाभाविक रूप से जांच और पारदर्शिता की कसौटी पर आ जाता है। फिलहाल भेलागुड़ी की यह कहानी केवल जमीन की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रह गई है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण, प्रशासनिक पारदर्शिता और संभावित मुआवजे से जुड़े कई अनुत्तरित सवालों का केंद्र बन चुकी है। इन सवालों के स्पष्ट जवाब अब केवल आधिकारिक जांच और दस्तावेजी तथ्यों से ही सामने आ सकेंगे।●

सीमा के साये में साजिश!

● धर्मेन्द्र सिंह

बिहार का सीमावर्ती जिला किशनगंज एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। नेपाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमाओं से जुड़े इस संवेदनशील इलाके में दो बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने अवैध घुसपैठ, फर्जी भारतीय दस्तावेजों और सीमा पार सक्रिय नेटवर्क की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया ब्यूरो (आईबी) ने जांच की कमान संभाल ली है और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस समय हुई, जब कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला के निर्देश पर एसडीपीओ-1 खुसरू सिराज के नेतृत्व में प्रेम पुल के समीप संयुक्त वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान मोटरसाइकिल सवार एक संदिग्ध युवक ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे और उसके साथ मौजूद महिला को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों बांग्लादेशी नागरिक निकले और भारत में वैध रूप से रहने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में गिरफ्तार मो. हसन शेख उर्फ असनउल्ला मल ने कई अहम खुलासे किए। उसने बताया कि भारत में अवैध प्रवेश कराने के लिए उसने एक दलाल को 15 हजार रुपये दिए थे। दलाल ने असम के रास्ते सीमा पार कराई, जिसके बाद वह ट्रेन से किशनगंज पहुंचा। जांच में यह भी सामने आया कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र बनवाकर उसके आधार पर आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य भारतीय पहचान पत्र तैयार कराए गए। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल वह अपनी असली पहचान छिपाने के लिए कर रहा था। हसन शेख ने यह भी स्वीकार किया कि वह ओमान से भारत लौटा था और यहां से बांग्लादेश जाने की तैयारी में था। भारत में उसने 'हसन शेख' नाम अपनाया, जबकि बांग्लादेश में उसका वास्तविक नाम असनउल्ला बताया गया। उसके कब्जे से बरामद दस्तावेजों और अन्य सामग्री की फॉरेंसिक तथा तकनीकी जांच कराई जा रही है। गिरफ्तार महिला तय्यबा इस्लाम उर्फ तंजीला अख्तर ने खुद को बांग्लादेश के नारायणगंज जिले की निवासी बताया। उसने दावा किया कि उसका विवाह किशनगंज निवासी जाकिर हुसैन से हुआ था और वह उसी के साथ रह रही थी। अब जांच एजेंसियां इस विवाह की वैधता, भारत में उसके निवास, स्थानीय संपर्कों और जाकिर हुसैन की भूमिका की गहन जांच कर रही हैं। फिलहाल पुलिस और आईबी की संयुक्त जांच का फोकस फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह, सीमा पार घुसपैठ कराने वाले दलालों, स्थानीय सहयोगियों और संभावित अंतरराज्यीय नेटवर्क पर है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस पूरे रैकेट से जुड़े कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। सीमाई सुरक्षा के लिहाज से यह मामला अब सिर्फ दो गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं, बल्कि एक बड़े संगठित नेटवर्क की पड़ताल में बदल चुका है।●

नशे के नेटवर्क पर पुलिस का प्रहार

● धर्मेन्द्र सिंह

सीमावर्ती जिला किशनगंज में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो अलग-अलग अभियानों में हेरोइन (स्मैक) और एमडीएमए की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। डीआईयू, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ), विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चार तस्करों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। पुलिस का मानना है कि इन कार्रवाइयों से पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच सक्रिय ड्रग नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पहली कार्रवाई किशनगंज बस स्टैंड के समीप की गई, जहां गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष अभियान में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से 200 ग्राम स्मैक (हेरोइन) और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार, बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बहादुरगंज थाना क्षेत्र के अफसाना रोड निवासी मुन्ना उर्फ मोहम्मद जमीर तथा रहमदनगर निवासी सोहेब आलम के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने संगठित तरीके से मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री करने की बात स्वीकार की है। दूसरी कार्रवाई पोठिया थाना क्षेत्र के बिरनाबाड़ी के समीप की गई। यहां पुलिस ने पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर से मोटरसाइकिल पर मादक पदार्थ लेकर आ रहे दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। तलाशी में उनके पास से 31.44 ग्राम एमडीएमए, एक मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान उत्तर दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल) निवासी मो. गुफरान और मो. तैरुद्दीन के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने इस्लामपुर से एमडीएमए लाकर ठाकुरगंज क्षेत्र में आपूर्ति करने की बात स्वीकार की है। दोनों मामलों में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने जब्त मोबाइल फोन की तकनीकी जांच शुरू कर दी है और गिरोह के बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को चिह्नित कर जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने कहा कि किशनगंज को नशा मुक्त बनाने के लिए मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि नशा तस्करी से जुड़ी किसी भी सूचना की जानकारी एएनटीएफ हेल्पलाइन 9031816150 पर दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचनादाता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। ●

पश्चिमपाली में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई

● फरीद अहमद

जिले में अवैध खनन एवं खनिज परिवहन पर रोक लगाने के लिए खनन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में शनिवार की सुबह खनन विभाग के खान निरीक्षक सुनील कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए अवैध बालू परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार, 1 अगस्त 2026 को अहले सुबह खनन विभाग की टीम ने पश्चिमपाली के समीप छापेमारी की। अभियान के दौरान अवैध रूप से बालू का परिवहन कर रहे दो डीसीएम (6 चक्का) ट्रकों को पकड़ा गया। जांच में वाहनों द्वारा बिना वैध दस्तावेज के बालू का परिवहन किए जाने की आशंका पर दोनों ट्रकों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए दोनों वाहनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए किशनगंज थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। खनन विभाग द्वारा मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। ●

डॉ. अखलाकुर्रहमान की वापसी पर नजरें

● धर्मेन्द्र सिंह

ठाकुरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अखलाकुर्रहमान को कर्मचारियों की शिकायतों के आधार पर लगे आरोपों से पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त कार्यालय ने आरोपमुक्त कर दिया है। विस्तृत विभागीय जांच के बाद आरोपों को मनगढ़ंत और आधारहीन मानते हुए आयुक्त कार्यालय ने न केवल उन्हें क्लीन चिट दी है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के प्रावधानों के अनुरूप दोबारा ठाकुरगंज पीएचसी का प्रभार सौंपने की भी अनुशंसा की है। इस आदेश के बाद जिले के स्वास्थ्य महकमे में एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर उनकी वापसी कब होगी। आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, डॉ. अखलाकुर्रहमान के विरुद्ध ठाकुरगंज पीएचसी के कुछ कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों की जांच उप निदेशक (कल्याण), पूर्णिया प्रमंडल से कराई गई थी। उप निदेशक ने 12 मई 2026 को अपनी जांच रिपोर्ट आयुक्त कार्यालय को सौंपी, जिसमें सभी आरोपों को निराधार और मनगढ़ंत बताया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डॉ. अखलाकुर्रहमान को पुनः योगदान कराने पर विचार किया जाना चाहिए। जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के बाद आयुक्त कार्यालय ने असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज को निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार के 26 जुलाई 2023 के प्रावधानों के तहत डॉ. अखलाकुर्रहमान को वरीयतम चिकित्सा पदाधिकारी होने के नाते नियमानुसार तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी का प्रभार दिलाना सुनिश्चित किया जाए। आदेश की प्रति संबंधित विभागीय अधिकारियों और जिला प्रशासन को भी भेजी गई है। गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद डॉ. अखलाकुर्रहमान को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए प्रमंडलीय स्तर पर जांच का आदेश दिया गया था। अब जांच में आरोप सिद्ध नहीं होने के बाद उनके पक्ष में निर्णय आने से पूरे प्रकरण पर विराम लग गया है। हालांकि, आयुक्त कार्यालय की स्पष्ट अनुशंसा के बावजूद अब तक (खबर लिखे जाने तक) उन्हें ठाकुरगंज पीएचसी का प्रभार नहीं सौंपा गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अगले निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यदि विभाग आदेश का अनुपालन करता है तो डॉ. अखलाकुर्रहमान की जल्द ही दोबारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में वापसी हो सकती है। फिलहाल यह मामला स्वास्थ्य प्रशासन में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है।●

प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया

आयुक्त के सचिव,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

भूमि-अर्जन विवादों को मिलेगी नई रफ्तार

● धर्मेन्द्र सिंह

बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि-अर्जन से जुड़े विवाद अक्सर वर्षों तक लंबित रहने और मुआवजा भुगतान में देरी की वजह बनते रहे हैं। अब इन समस्याओं के समाधान की दिशा में राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों में संचालित भूमि-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरणों के लिए नए पीठासीन पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न केवल लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा, बल्कि प्रभावित किसानों और भू-स्वामियों को समय पर न्याय और उचित मुआवजा भी मिल सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता भूमि-अर्जन प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि देने वाले लोगों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं और विलंब का सामना न करना पड़े, इसके लिए अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को प्राधिकरणों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार अली अहमद को मुजफ्फरपुर, सम्पूर्णानंद तिवारी को सारण, देवराज त्रिपाठी को दरभंगा, विजय आनंद तिवारी को भागलपुर, विनोद कुमार तिवारी को गया, राकेश मालवीय को मुंगेर, राधे श्याम शुक्ला को पूर्णिया, हसमुद्दीन अंसारी को कोशी (सहरसा) तथा हेमंत कुमार त्रिपाठी को पटना प्रमंडल के भूमि-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण में पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। सरकार ने इन अधिकारियों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक निर्धारित किया है। साथ ही सभी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र मिलने के सात दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। इन प्राधिकरणों को भूमि-अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन और मुआवजा संबंधी विवादों की सुनवाई तथा अधिनियम के तहत संदर्भित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।सरकार को उम्मीद है कि इससे भूमि-अर्जन मामलों का निष्पादन तेज होगा, मुआवजा वितरण में पारदर्शिता आएगी और राज्य की सड़क, रेल, औद्योगिक तथा अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं को भी गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि समयबद्ध न्याय की यह व्यवस्था विकास और जनहित के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।●

पंचायत के बहाने होटल ले जाने का आरोप

● धर्मेन्द्र सिंह

किशनगंज जिले के पौआखाली थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अहमद हुसैन उर्फ लल्लू मुखिया पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप ने जिले की सियासत और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। पीड़िता के आवेदन पर पौआखाली थाना में कांड संख्या 120/2026 दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि 28 जुलाई की रात उसकी बेटी से जुड़े एक विवाद को सुलझाने के नाम पर आरोपी उसे, उसके पति और बेटी को अपने साथ ले गया। शिकायत के अनुसार, रास्ते में उसके पति को कथित रूप से नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया गया। इसके बाद उसे किशनगंज के एक होटल में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि पहले उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, लेकिन असफल रहने पर उसे दूसरे कमरे में भेज दिया गया और फिर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई तथा मामला दबाने के लिए पांच लाख रुपये देने का प्रस्ताव भी रखा गया। उसने पुलिस से आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। प्रभारी पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जाएगी तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इधर, आरोपी और पीड़िता के पति के बीच

बातचीत का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि उसमें समझौते और मुकदमा वापस लेने को लेकर बातचीत है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वायरल ऑडियो की प्रामाणिकता की अभी पुष्टि नहीं हुई है और इसकी जांच भी की जा सकती है। फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है। आरोपों की पुष्टि या खंडन न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। घटना के बाद जिले में मामले को लेकर व्यापक चर्चा है और निष्पक्ष जांच तथा कानून के अनुरूप कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।

लल्लू मुखिया की क्राइम हिस्ट्री

- पौआखाली थाना कांड संख्या-77/09 दि-19.04.09 धारा-188/171(H) IPC
- पौआखाली थाना कांड संख्या-80/13 दि-05.05.13 धारा-420/504/34 IPC
- पौआखाली थाना कांड संख्या-12/15 दि-03.11.15 धारा-147/341/323/379/307/353/504 IPC
- पौआखाली थाना कांड संख्या-89/25 दि-11.10.25 धारा-126(2)/127(2)/115(2)/351(3)/352/3(5) BNS
- सुखानी थाना कांड संख्या-247/14 दि-02.09.14 धारा-147/149/186/189/341/342/290/291/353 IPC
- पौआखाली थाना कांड संख्या-35/23 दि-26.06.23 धारा-341/323/379/504/506/34 IPC

ठाकुरगंज-गलगलिया हाइवे पर ओवरलोड वाहनों की कतार

● धर्मेन्द्र सिंह/फरीद अहमद

किशनगंज प्रखंड क्षेत्र में ठाकुरगंज धर्मकांटा से लेकर गलगलिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग-327ई के विभिन्न हिस्सों में कोयला समेत अन्य भारी मालवाहक ट्रकों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोगों का कहना है कि कई ट्रकों को हाईवे और उसके किनारे लंबे समय तक खड़ा रखा जाता है, जिससे सड़क का एक हिस्सा अवरुद्ध हो जाता है और यातायात प्रभावित होता है। लोगों के अनुसार, हाईवे किनारे अनियोजित ढंग से खड़े ट्रकों के कारण छोटे वाहनों के आवागमन में परेशानी होती है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। लोगों का आरोप है कि कुछ स्थानों पर हाईवे के किनारे अस्थायी रूप से पार्किंग जैसी स्थिति बना दी गई है, जिससे आम राहगीरों को जोखिम उठाकर सफर करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि कथित इंट्री सिंडिकेट के संरक्षण में ओवरलोड वाहनों का परिचालन जारी है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इस संबंध में जिला खान निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि कोयला परिवहन से जुड़े मामलों में कार्रवाई का अधिकार खनन विभाग के दायरे में नहीं आता। उन्होंने कहा कि यदि ओवरलोडिंग का मामला है तो उस पर कार्रवाई परिवहन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है। वहीं, परिवहन विभाग से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। विभाग का जवाब मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। जदयू के वरिष्ठ नेता अहमद हुसैन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि हाईवे पर ओवरलोड वाहनों और अवैध पार्किंग की शिकायतों को गंभीरता से लेकर प्रशासन को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। वहीं, जदयू के वरिष्ठ नेता अहमद हुसैन ने कहा कि पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार जब कुछ दिन किशनगंज में नहीं थे तब कथित इंट्री माफिया का मनोबल बढ़ गया था लेकिन किशनगंज में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के पदभार संभालने के बाद कथित इंट्री माफिया के बीच बेचैनी देखी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में इंट्री माफिया के संरक्षण में ओवरलोड वाहनों का परिचालन होता रहा है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की।●

प्रखण्ड कृषि विभाग बिहिया में लूटेरा कौन?

● बिन्ध्याचल सिंह

'पांच लगाओ पच्चीस पाओ' उद्धत वाक्य प्रखण्ड कृषि विभाग बिहिया में पदस्थापित कृषि समन्वयक कमरियॉव, तियर, चकवथ में जैविक कोरिडोर योजना के अन्तर्गत दी गई प्रशिक्षण से सम्बन्धित कागजातो व उपस्थित किसानो को गहनता से जॉच करेगे, तो आप पायेगें कि ''पॉच लगाओ-पच्चीस पाओ वाला वाक्य कितना सटीक बैठता है। सरकार द्वारा कई योजनाओ का संचालन किया जाता है, जिसमें केवल सच आपको दो योजनओ की धरातल की जानकारी उपलब्ध करा रहे है। पहला- कमरियॉव पंचायत अन्तर्गत संचालित जैविक कोरिडोर योजना और दुसरा-''रेन फिल्ड योजना'' जो घाघा पंचायत अन्तर्गत संचालित हो रही है। प्रिय पाठकगण जानकर आश्चर्य होगा कि घाघा पंचायत में सेवा दे रहे पदाधिकारी केद्वारा ऐसे भ्रष्टाचार का जन्म देते है कि आप सोच नही सकते। वैसे पहले कमरियॉव पंचायत अन्तर्गत चलाई जानेवाली जैविक कोरिडोर योजना में सरकार के द्वारा किसानो को प्रशिक्षण देने में की गई व्यय की राशि, जो कृषि समन्वयक की

जिम्मेवारी दी गई थी। जिसकी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मॉगी गई सूचना के आलोक में प्राप्त हुई। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पत्रांक-2882 दिनांक-08/10/2024 के आलोक में, एवं सूत्रो से प्राप्त जानकारी इस प्रकार है। पत्रांक में संलग्न कागजातो का अवलोकन करने से जानकारी हुई कि बिहिया बाजार का चर्चित

सारणी से समझिए, जिसमें सामग्री का विवरण जानकारी, जो आई सी एस मैनेजर/कृषि समन्वयक के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर को दी गई है :-

संस्था/दुकान का नाम	सामग्री का नाममात्रा	संख्या	भुगतान
अमित म्यूजिकल लाईट एण्ड साउण्ड राजा बाजार बिहिया 19/10/2023	टेन्ट, कुर्सी इत्यादि	02	नगद
लव-कुश स्वीट्स बिहिया 19/10/2023	नास्ता	45 गुणा 90	नगद
लव-कुश स्वीट्स बिहिया 19/10/2023	नास्ता	50 गुणा 90	नगद
लव-कुश स्वीट्स बिहिया 19/10/2023	नास्ता	45 गुणा 90	नगद
प्रीति नीर 19/10/2023	पानी	140 बोतल	नगद
केशरी पुस्तक भंडार 19/10/2023	फोल्डर	130	नगद
केशरी पुस्तक भंडार	कलम और पैड	130, 130	नगद
केशरी आर्ट प्रेस	बैनर	01	नगद

मिठाई की दुकान में चाय भी मिलता है जबकि हक्कीकत यह है कि चर्चित मिठाई दुकान में चाय का दूर-दूर तक कोई वास्ता नही है। प्राप्त कागजात के आलोक में:-कुशवाहा लाईट साउण्ड एवं टेन्ट हाउस, आर्केस्ट्रा को जिसका रसीद क्रमांक-150 दिनांक21/03/2023 है, से बीस हजार रू0 का भुगतान किया गया, जबकि नास्ता-का भुगतान-16500/-रू0 किया गया। यानि 19/10/2023 को कुल खर्च सैतीस हजार सात सौ पचास रूपया मात्र।

कैशमेमो से साफ स्पष्ट होता है कि कृषि समन्वयक के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर को दी गई कैशमेमो एक घोटाला है क्योकि किसी भी प्रशिक्षण में तीन बार नास्ता नही दिया जाता है बल्कि अलग-अलग मेनू होता है। जैविक कोरिडोर योजना कमरियॉव पंचायत के दो गॉव करखियॉ व जादोपुर कागज के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी भोजपुर को अवगत कराया गया है जबकि धरातल की खबर यह है कि तीनो प्रशिक्षण मंहत बडाई दास नथुनी सिंह राजकीयकृत उच्च विद्यालय जादोपुर में हुई है। जिसमें औसतन तीस किसान भी उपस्थिति नही हुये थे। कृषि समन्वयक श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय के द्वारा 99 किसानो की हस्ताक्षरयुक्त कागज जिला कृषि पदाधिकारी भोजपुर को दे चुके है, जबकि नास्ता का पैकेट लव-कुश स्वीट्स से 50 पीस ही मॉगवाये थे। एक दिन की प्रशिक्षण में तीन बार नास्ता की व्यवस्था की गई थी, पहली बार में 45, दुसरी बार में-50 जबकि तीसरी बार में-45 जरा सोचिये कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 99 किसान और नास्ता लाई गयी 45-50-45 वाह व्यवस्थापक महोदय। प्रखण्ड कृषि विभाग बिहिया में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में किसान सलाहकारो की कही भी भूमिका नही है जैसा कि विभित्र पंचायत की जनता ने जानकारी दी। रेन-फिल्ड योजना की विस्तृत जानकारी नही मिलने के कारण सूचीबद्व नही की जा सकती है। उपरोक्त खबर जैविक कोरिडोर योजना का पहला प्रशिक्षण की जानकारी उपलब्ध कराई गई है बाकि द्वितीय व तृतीय प्रशिक्षण की जानकारी अगले अंक में जारी।●

नगर भवन में हुआ सौर मेला का आयोजन

● बिन्ध्याचल सिंह

सौर ऊर्जा एवं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रोत्साहित करने, जन जागरूकता तथा जनभागीदारी हेतु आज दिनांक 31 जुलाई 2026 को सौर मेला का आयोजन नगर भवन बक्सर में किया गया। जिला पदाधिकारी बक्सर, श्रीमती साहिला, उप विकास आयुक्त बक्सर, श्रीमती निहारिका छवि एवं सहायक समाहर्ता बक्सर के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर मेले का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त बक्सर, सहायक समाहर्त्ता बक्सर, वरीय उप समाहर्त्ता बक्सर, विद्युत अधीक्षण अभियंता आरा, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बक्सर, जिला अग्रणी बैक के पदाधिकारी, अन्य बैको के पदाधिकारीगण, शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षद, नगर अध्यक्ष, विभिन्न पंचायतो से आये हुए मुखिया, ग्राम सरपंच एवं सोलर वैडरर्स उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी द्वारा अपने संबोधन में सोलर से होने वाले फायदे एवं योजना के लाभ से लोगो को अवगत

कराया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किस तरह लोग अपने छत पर पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से अपने छत पर सोलर पैनल लगवाकर स्वच्छ एवं प्रदुषणरहित बिजली उत्पादन कर अपने बिजली बिल को शून्य कर सकते है। जिला पदाधिकारी द्वारा मेले में शामिल सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे स्वयं अपने छतो पर सोलर पैनल लगवाये तथा समाज के सभी वर्गो को पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेते हुए अपने छत पर सोलर पैनल लगवाने हेतु प्रेरित करें।

जिला पदाधिकारी द्वारा बक्सर के ज्यादा से ज्यादा छतो पर सोलर पैनल लगाने हेतु मिशन प्रभाकिरण की शुरूआत की गयी। मिशन प्रभाकिरण के माध्यम से जिला पदाधिकारी द्वारा जिले के प्रत्येक नागरिक से अपील किया गया कि सभी अपने छतो पर सोलर पैनल लगाये तथा बक्सर को स्वच्छ उर्जा उत्पादन में अग्रणी बनाये। मेले में आये हुए लोगो द्वारा सौर उर्जा के बारे में जानकारी ली गयी तथा पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से अपने छतो पर सोलर पैनल लगाने हेतु 56 आवेदन भी किये।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

बियाडा बिहिया से क्यों गई महंगाई

● बिन्ध्याचल सिंह

'मंहगाई' से पुरे देश में हाहाकार है, नकारा नही जा सकता है। परन्तु 'मंहगाई' वर्ष-2019 से 'दिन दूनी रात चौगनी' बढती जा रही हैं, इस बात को भी नही नकारा जा सकता है। लेकिन यक्ष प्रश्न है कि जब पुरा देश मंहगाई से परेशान है तो बियाडा क्षेत्र बिहिया से मंहगाई क्यो चली जाती है। मंहगाई वर्ष-2017/2018 में भी रामको कम्पनी में कार्यरत श्रमिको के लिए चली गई थी, परन्तु केवल सच पत्रिका के अथक प्रयास के बाद पुनः चली आई और आजतक सरकार के नियमानुसार बढती रहती है। परन्तु मंहगाई इतना नटखट है कि पुनः बियाडा क्षेत्र बिहिया में दर्जनो श्रमिको के घर की चुल्हा जलाने की जिम्मेवारी लेने वाली अनुप जी फुड से चली गई, जिसकी जानकारी केवल सच प्रतिनिधि को अप्रैल-2026 में श्रमिको के द्वारा बियाडा क्षेत्र बिहिया से जानकारी प्राप्त हुई। सूत्रो से मिली जानकारी व श्रमिको द्वारा दी गई जानकारी के आलोक में श्री अनुप जी फुड में लगभग 50-60 श्रमिक कार्य करते है जिसमें 20-25 महिला श्रमिक है, जो भूतल पर कार्य करती है, जबकि पुरूष श्रमिक प्रथम तल व भूतल पर कार्य करते हैं। अनुप जी फुड में कोई भी श्रमिक स्थायी श्रमिक नही है। क्योकि श्रमिको को प्रत्येक दिन मजदूरी दी जाती है। जबकि बियाडा क्षेत्र बिहिया में ऐसा अन्य कम्पनी में नहीं है। जानकारी के अनुसार अनुप जी फुड में महिला श्रमिक को प्रत्येक दिन की मजदूरी प्रत्येक दिन नगद 200 रू० दी जाती है, वही पुरूष श्रमिक को 300/350 रू० दी जाती है। कार्य अवधि की बात की जाय तो महिला श्रमिक से सुबह नौ बजे से शाम छः बजे तक यानि 9 घंटे कार्य लिया जाता है जिसकी मजदूरी 200 रू० है, जबकि पुरूष श्रमिक से सुबह आठ बजे से शाम छः बजे तक यानि 10 घंटे कार्य के 300/350 रू० मजदूरी दी जाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है बियाडा क्षेत्र बिहिया में श्रमिक की मजदूरी बियाडा क्षेत्र बिहिया में स्थापित सभी कम्पनी की तुलनात्मक बात की जाय तो किसान दालमोट, गुप्ता ट्रेडिग कम्पनी, कोल्ड स्टोर, सम्पूर्णा एग्रो, रामको इत्यादि की तुलना में अनुप जी फुड में श्रमिको की मजदूरी कम दी जाती है। सूत्रो की माने तो अनुप जी फुड को प्रत्येक महिना लगभग 200000/दो लाख रू० बचत केवल श्रमिको की मजदुरी कम देने से होती है। जो जॉच का विषय है। उपरोक्त सूचीबद्ध खबर अनुप जी फुड में कार्यरत श्रमिक, समाजसेवी, श्रमिको की संस्था से ताल्लुकात रखने वाले शुभचिन्तक से प्राप्त जानकारी के आलोक में की गई है। केवल सच श्रमिको के मजदुरी को सत्यापित नही करता है।●

काश! सभी प्राइवेट विद्यालय यूनिवर्सल एवं महथीन विद्यापीठ की तरह ही होते?

● बिन्ध्याचल सिंह

गरीब, मजदुर, किसानो के बच्चे की देवालय है-''यूनिवर्सल''बिहिया व आदर्श महथीन विद्यापीठ ''सिकरियाँ'' ये दोनो प्राइवेट विद्यालय यूनिवर्सल बिहिया व आदर्श महथीन विद्यापीठ''सिकरियाँ'' अपनी अभी तक के जीवन काल में पुस्तक नही बदले है। जबकि आदर्श महथीन विद्यापीठ की स्थापना-जनवरी-1988 में हुई थी। जिसके सचिव परम आदरणीय कमल कुमार चौबे है, जो विकलांगता को बौना साबित करते आ रहे है। सिकरियाँ भोजपुर जिला के बिहियाँ प्रखण्ड के तियर पंचायत व भोजपुर जिला के पश्चिम छोर का अन्तिम गॉव है जो बक्सर जिला के बाबा ब्रम्मेश्वर नाथ की नगरी ब्रहम्मपुर के चौहदी से सटटा है। आदर्श महथीन विद्यापीठ ''सिकरियाँ'' एक सुदूर देहाती इलाका है जहाँ विद्या का दीपक जलना मुश्किल ही नही अपितु नामुमकिन है वहॉ आज 38 वर्षो से शिक्षा का अलख जगाना ''पत्थर पर दुब जमाना जैसा'' है। परन्तु आदरणीय कमल कुमार चौबे के अथक प्रयास से आज सिकरियाँ सहित अन्य गॉव के बच्चे आदर्श महथीन विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्तकर भारत व बिहार सरकार के कई प्रतिष्ठित पद पर सेवा दे रहे है। जबकि यूनिवर्सल की स्थापना-1995 ई0 में हुई थी, जिसके निर्देशक सह प्रचार्य श्री नीरज कुमार सिंह है जो यूनिवर्सल के सर्वेसर्वा है। यूनिवर्सल एक संयूक्त परिवार का उदाहरण है जहाँ छात्रो की संख्या-1350 शिक्षको की कुल संख्या-40 है। यूनिवर्सल विद्यालय की दो-तीन गुण ऐसा है जिससे अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, पदाधिकारी प्रभावित रहते है। जैसे- योग्य शिक्षक व गुणवतापूर्ण शिक्षा, विद्यालय प्रशासन द्वारा स्टेशनरी की विक्री न करना, सप्ताह में एक दिन प्राचार्य सह निर्देशक के द्वारा सभी वर्गो का मुल्याकंन करना इत्यादि शामिल है। सूत्रो की माने तो यूनिवर्सल प्लस टू विद्यालय के शिक्षक लगभग सभी प्रशिक्षित है। यही वजह है कि यूनिवर्सल विद्यालय के छात्र-छात्राएँ विगत पॉच-सात वर्षो से लगातार राज्य स्तर पर मैट्रिक की परीक्षा में टॉपर आ रहे है। यूनिवर्सल विद्यालय की गुणतापूर्ण शिक्षा की गुणगान अपर समाहर्ता भोजपुर भी विद्यालय के 31वॉ स्थापना दिवस पर कर चुके है। वही बिहिया चौरास्ता पर स्थित परमज्ञान्नद यूनिक पब्लिक स्कूल में विगत दस वर्षो से विज्ञान के योग्य शिक्षक के लिये चर्चा में रहता है क्योकि स्कूल के निर्देशक श्री अतुल कुमार गुणवतापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देते रहते है। जबकि विश्व भारती शिक्षा सदन में लगभग प्रत्येक वर्ष किताब बदलने की जानकारी केवल सच प्रतिनिधि को हुई। जिसकी सच्चाई के लिये विद्यालय के निर्देशक से वाट्सएप से मिलने की इच्छा जाहिर की गई तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि मेरी उपस्थिति दिल्ली में है। ●

● **गुड्डी साव**

मुख्यमंत्री ने इस भावुक क्षण में कहा कि आज का दिन विशेष रूप से मेरे एवं मेरे पूरे परिवार के लिए, अत्यंत भावुक और भारी दिन है, लेकिन यह पीड़ा केवल हमारे परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश के साथ-साथ देश के समस्त आदिवासी, दलित, शोषित और पिछड़े समाज के लिए यह अत्यंत दुःखद और भावुक कर देने वाला क्षण है। घपिछले वर्ष आज ही के दिन आदरणीय बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने अंतिम सांस ली थी और पंचतत्व में विलीन हुए थे। इस सृष्टि का यही शाश्वत सत्य है कि जिसने इस धरा पर जन्म लिया है, उसे कालचक्र के विधान अनुसार एक दिन प्रकृति में लीन होना ही पड़ता है।

आदरणीय गुरुजी ने भी उसी कालचक्र को पूरा किया। कभी-कभी कुछ घटनाओं और समय के चक्र के कारण हमारे प्रिय लोग हमारे बीच से बिछड़ जाते हैं। घआज हम सबने लुकैयाटांड़ (बरलंगा) स्थित सोना-सोबरन विद्यालय परिसर में आदरणीय गुरुजी की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा की स्थापना का उद्देश्य यही है कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपने इतिहास और जड़ों को कभी न भूलें। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के पहले और आजादी के बाद भी जिस प्रकार का शोषण हमारे समाज ने झेला और उस शोषण के विरुद्ध जिस निडरता से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, उस संघर्ष से सीख लेना हमारा कर्तव्य है। हमारे दादा जी अमर शहीद स्व० सोबरन मांझी जी ने भी समाज के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उस समय रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिले का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जहाँ एक छोटे से विद्यालय में उन्होंने शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएँ दीं और बच्चों को शिक्षित करने का काम किया, लेकिन असामाजिक तत्वों ने रात के अँधेरे में बड़ी ही निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। वह घटना मेरे जन्म से पहले की है, लेकिन आज भी जब उस काले अध्याय को याद करते हैं, तो मन व्यथित हो उठता है।

बड़ी चिंता का विषय यह है कि आज भी वे असामाजिक तत्व एक नए रूप और नए चेहरे के साथ हमारे समाज में विद्यमान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक तरफ जहाँ हम चाँद पर पहुँचने के सपने को पूरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शहरों से लेकर दूर-दराज के गाँवों और कस्बों तक ऐसी असामाजिक ताकतें लगातार पनप रही हैं। ये ताकतें हमारे सीधे-सादे आम नागरिकों-चाहे वे बुजुर्ग हों, महिलाएँ हों या नौजवान हों, उन्हें गुमराह करने और निशाना बनाने का काम करती है। मुझे लगता है कि इस समस्या का एक ही स्थायी समाधान है-हमारी अटूट एकजुटता और एक-दूसरे के प्रति आपसी सम्मान। जब तक हम आपस में सम्मान और भाईचारे का भाव नहीं रखेंगे, तब तक हम छोटी-छोटी बातों पर आपस में लड़ते रहेंगे। इसलिए आपसी भाईचारे का भाव और मानवीय भावना जागृत करनी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दौर नई युवा पीढ़ी का दौर है। हमारी युवा पीढ़ी बड़ी ऊर्जा और ताकत के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन इस ताकत के साथ जहाँ अच्छाइयाँ और अपार संभावनाएँ हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नई पीढ़ी को सही मार्ग पर बनाए रखें, ताकि वे भटकाव के रास्ते से कोसो दूर रहें।

दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर गांधी मैदान, जामताड़ा में फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ

जामताड़ा पद्म भूषण से सम्मानित स्मृति शेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर 4 अगस्त को गांधी मैदान जामताड़ा में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ झारखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं नाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवींद्रनाथ महतो ने किया। इस अवसर पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के उपरांत उपस्थित जनप्रतिनिधियों, खिलाड़ियों एवं नागरिकों ने गुरुजी के संघर्षमय जीवन और झारखंड आंदोलन में उनके ऐतिहासिक योगदान को स्मरण किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपना संपूर्ण जीवन जल, जंगल, जमीन, आदिवासी-मूलवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय तथा पृथक झारखंड राज्य के निर्माण के संघर्ष को समर्पित किया। उनका त्याग, अदम्य संघर्ष और जनसेवा का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। गुरुजी ने झारखंड की पहचान, स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वह इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में आयोजित यह फुटबॉल टूर्नामेंट केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि दिशोम गुरु के आदर्शों, संघर्ष और जनसेवा की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का एक सार्थक माध्यम है। खेल युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, भाईचारे और सकारात्मक सोच का विकास करते हैं तथा समाज को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्यक्ष ने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आहवान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। साथ ही कहा कि दिशोम गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए सामाजिक न्याय, जनसेवा और झारखंड के सर्वांगीण विकास के संकल्प को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, खेल प्रेमी, खिलाड़ी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके विचारों और आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया।

उन्होंने कहा कि आज आदरणीय 'गुरुजी' के विचार और आदर्श केवल उनकी जन्मस्थली, पंचायत या गाँव तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्यभर व देश में आज उन्हें बड़े आदर और श्रद्धा के साथ याद किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा बारिश का मौसम होने के बावजूद आज पूरे राज्यभर में आदरणीय गुरुजी की याद में लोग स्वत: स्फूर्त एकत्रित हो रहे हैं। राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर हर जिले में समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने अपने आंदोलन के माध्यम से न केवल झारखंड को एक विशिष्ट पहचान दी, बल्कि एक महान जननायक के रूप में अमूल्य योगदान दिया। वे राजनीति की पारंपरिक सीमाओं से बहुत आगे निकल चुके थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके समक्ष पद, नेता, विधायक और मंत्री सब फीके पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि 'गुरुजी' जैसे वीर सपूतों ने अपने खून-पसीने से सींचकर हमें यह अलग राज्य बनाकर दिया है, लेकिन आज इस राज्य को सजाने और संवारने की एक भारी-भरकम जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारा यह निरंतर प्रयास है कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की आवाज और सुविधाएँ पहुँचे और आपकी आवाज सीधी सरकार तक आए। हम सब मिलकर राज्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है, इसका मार्ग प्रशस्त करें। घ्पूर्व में हम सब इस लुकैयाटांड़ में अमर शहीद सोबरन मांझी जी की याद में एकत्रित होते रहे हैं। अब आदरणीय गुरुजी के सम्मान में भी हम सब यहाँ निरंतर जुटेंगे। हमारा पैतृक गाँव नेमरा यहाँ से बिल्कुल समीप ही है, जहाँ आदरणीय गुरुजी का जन्म हुआ था। चूँकि इतने सारे लोगों को उस छोटे से गाँव में समायोजित करना कठिन था, इसीलिए आप सबों के लिए इस स्थल को चिह्नित किया गया, ताकि आने वाले समय में हम बड़ी-से-बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित होकर अपने महान नायकों को याद कर सकें और उनकी प्रेरणा को आगे बढ़ाने का संकल्प ले सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन औपचारिक भाषण देने का नहीं है। आज प्रथम पुण्यतिथि पर मूर्ति के अनावरण के साथ-साथ ऐसे महान आत्माओं की याद को अपने दिल और आत्मा के अंदर बसाने का दिन है। भले ही वे शारीरिक रूप से आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका दिखाया संघर्ष और मार्ग आज भी हम सबों के सामने स्पष्ट दिखाई देता है। झारखंड की इस पावन धरा पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो और आदरणीय गुरुजी जैसे अनगिनत महापुरुषों का जन्म हुआ। इन महापुरुषों के त्याग के कारण ही झारखंड एक राज्य के साथ-साथ वीरों की पावन भूमि के रूप में स्थापित है। इसके हर कोने में कोई न कोई वीर सपूत दिखाई और उनका प्रेरणादायक संदेश सुनाई देगा। हम सब उन महान वीर पुरुषों के वंशज और सपूत हैं। वीरों की इस धरती पर हम सभी वीर हैं, और यह वीरता की लड़ाई हमें आपस में नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों से लड़नी है। उन्होंने कहा कि हमें अपने राज्य के इतिहास को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने विपरीत परिस्थिति में दिशोम गुरू के प्रथम पुण्यतिथि पर यहां पधारने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति आभार जताया।

प्रथम पुण्यतिथि पर राज्य के मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मंत्री संजय प्रसाद यादव, मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, सांसद राज्यसभा श्रीमती महुआ माजी, विधायक उमाकांत रजक, विधायक कुमार जयमंगल सिंह, विधायक अमित महतो, विधायक ममता देवी, पूर्व मंत्री बेबी देवी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित राज्य सरकार के वरीय अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।●

● गुड्डी साव

झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सभी राज्यवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए जोहार से अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस को हम सभी जानते हैं। पूरे आदिवासी समाज को आज के इस दिवस को यादगार बनाने का इंतजार रहता है। धरती पर आदिवासी समाज की अलग पहचान है। इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हुई है। उन्होंने महोत्सव के लिये सभी लोगों के सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त होने का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने राज्य के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की गरिमामयी उपस्थिति को समारोह की विशेष गरिमा और आदिवासी समाज के गौरव का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राज्यपाल महोदय केवल राज्य के राज्यपाल ही नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय के मार्गदर्शक और सर्वमान्य नेतृत्वकर्ता के रूप में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (टीएसी) राज्यपाल महोदय की छत्रछाया और मार्गदर्शन में कार्य करती है। टीएसी के माध्यम से आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा, उनके समग्र विकास और कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाती है। साथ ही, आदिवासी समाज के विकास के साथ-साथ पूरे समाज की प्रगति और भविष्य की दिशा तय करने में भी टीएसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के आदिवासी दिवस को पूरे देश और दुनिया में आदिवासी समाज अपने-अपने तरीके से यादगार बनाने में

जुटा हुआ है। झारखंड में भी पिछले कुछ वर्षों से इस अवसर पर छोटे-बड़े विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करके आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मोरहाबादी के पूरे मैदान में देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों की विविधता और सांस्कृतिक झलक देखने को मिल रही है। आयोजन स्थल पर पंडाल लगाए गए हैं, जहां हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग अपनी जीवनशैली, कला, संस्कृति, परंपरा और आजीविका के साध नों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यह आयोजन हमें यह भी दिखाता है कि किस तरह आदिवासी समाज अपनी पारंपरिक पहचान को संजोते हुए विकास और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन में केवल झारखंड ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से भी आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए हैं। कलाकारों, कारीगरों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की सहभागिता ने इस आयोजन को और भी अधिक व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। उनके हुनर, परंपरा और अनुभवों के माध्यम से एक मजबूत और बेहतर रास्ते की तलाश में आगे बढ़ते आदिवासी समाज की तस्वीर यहां देखने को मिल रही है। इस अवसर पर राज्य में विभिन्न

गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी समाज की समृद्ध विरासत को सम्मान और सशक्तिकरण का प्रदर्शन हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मना रही है, वहीं हमारे कुछ युवा, नौजवान और छात्र-छात्राएं अपनी कुछ मांगों और अधिकारों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार खुले मन से उनकी बातें सुन रही है और उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझने का प्रयास कर रही है। हर समस्या का समाधान संवाद से संभव है। उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि इतनी बड़ी व्यवस्था का संचालन करते हुए भी सरकार की मंशा राज्य के सवा तीन करोड़ लोगों के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करने की है। गांव में रहने वाला व्यक्ति हो या शहर में रहने वाला, किसान हो या मजदूर, महिला हो या पुरुष, पढ़ा-लिखा नौजवान हो या कम पढ़ा-लिखा अथवा अशिक्षित व्यक्तिख्रसरकार सभी की चिंता करती है और सबके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिस विषय को लेकर राज्य के नौजवान अपने अधिकार की आवाज उठा रहे हैं, वह उनकी जागरूकता और अपने हक के लिए खड़े होने के साहस को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि नौजवानों ने हिम्मत इसलिए जुटाई है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उनके साथ न्याय होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि मेरे संज्ञान में गड़बड़ी सामने आई है, उसकी जांच होगी, नौजवानों को न्याय मिलेगा और जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए धरती पुत्र की भांति कहा कि आप विश्वास रखिए, हम इसी मिट्टी में जन्मे हैं और इसी मिट्टी में दफन भी होंगे। इसलिए हम आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि इस पूरे विषय को राजनीतिक रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है, और न ही युवाओं को किसी राजनीतिक छत्रछाया की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पालते हैं और राजनीतिक दलों का इस्तेमाल कर युवा पीढ़ी को अपने हित में इस्तेमाल करने का रास्ता अख्तियार करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से नौजवानों से कहा कि वे विद्यार्थी हैं, उनका अपना अधिकार है और उन्हें उनका अधिकार एवं न्याय मिलना चाहिए। यह जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इसे पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरे देश में अलग-अलग तरीके से राजनीतिक दलों की नजर युवा पीढ़ी पर है। किस तरह युवाओं को सही और गलत तथ्यों के बीच दिग्भ्रमित किया जाए, इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें केवल सामान्य लोग ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े विद्वान, पढ़े-लिखे और ज्ञानी लोग भी शामिल हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी बात सरकार के समक्ष पूरी स्पष्टता और निर्भीकता के साथ रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब केवल आंदोलन और धरना-प्रदर्शन के माध्यम से ही युवाओं की बातें सुनने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन युवाओं तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही है, जो घर बैठे अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं को लेकर चिंतित हैं। इसके लिए सरकार ने संवाद का माध्यम भी बनाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश को जो संविधान दिया है, वह देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान करता है। व्यक्ति अमीर हो या गरीब, संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद समाज में असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है। आने वाले वर्षों में देश आजादी की शताब्दी की ओर बढ़ेगा, लेकिन आज भी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बड़ी असमानताएं मौजूद हैं। समाज, राज्य और देश में आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं जितनी बढ़ेंगी, तनाव भी उतना ही बढ़ेगा। इसलिए इन असमानताओं को दूर करना और सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराना समय की बड़ी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लोकतंत्र की मूल भावना को चुनौती देने के लिए भी एक बड़ा समूह पूरी ताकत और शिद्दत के साथ प्रयासरत है। हालांकि, झारखंड केवल एक राज्य नहीं, बल्कि वीरों की भूमि है। यह वह धरती है, जहां देश के बड़े हिस्से में आजादी का सपना देखने की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उस समय से झारखंड के वीर पूर्वज अपने अधिकार, अस्मिता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे हैं। संघर्ष की यह परंपरा आज भी जारी है। उन्होंने कहा कि झारखंड को अलग राज्य बने 25 वर्ष हो चुके हैं और इन वर्षों में राज्य ने अपने पैरों पर खड़े होने तथा अपनी अलग पहचान स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था, जब झारखंड को केवल संसाधनों के दोहन के लिए

एक चारागाह की तरह देखा गया, लेकिन आज जब यह राज्य अपनी ताकत और क्षमता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो यह बात कई लोगों को स्वीकार नहीं हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य की प्रगति और उसकी बढ़ती ताकत को रोकने के लिए कभी चेहरा छिपाकर, कभी चेहरा बदलकर और कभी पर्दे के पीछे से गलत संदेश देने तथा लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे प्रयासों के प्रति समाज और विशेषकर युवाओं को सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान बातचीत और लोकतांत्रिक तरीके से निकाला जा सकता है। सीमाओं पर देश के दुश्मनों से मुकाबला अलग विषय है, लेकिन देश के भीतर रहने वाले अपने ही लोगों के साथ लाठी-डंडे के बल पर किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से युवाओं, विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि वे स्वयं को युवाओं से अलग नहीं मानते। आपकी भावनाएं और सभी की चिंताएं उनकी चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि आज संवैधानिक जिम्मेदारी के स्थान पर रहते हुए वे युवाओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके साथ पूरी पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय केवल होगा ही नहीं, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का यह महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि अपनी गौरवशाली विरासत, संघर्ष और पहचान को याद करने का अवसर है। उन्होंने कामना की कि यह महोत्सव यादगार और प्रेरणादायक बने तथा आदिवासी समाज अपने गौरव और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े।●

भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को समर्पित भव्य जतरा को मंत्री चमरा लिंडा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

● गुड्डी साव

झारखण्ड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति और वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की अमर विरासत को जीवंत रखने वाले भव्य आयोजन का शुभारंभ हुआ। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखण्ड सरकार के मंत्री चमरा लिंडा ने 9 अगस्त को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क बिरसा मुंडा कारागृह जेल मोड़ से भगवान बिरसा मुंडा जतरा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रधान सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कृपानन्द झा, आदिवासी कल्याण आयुक्त, कुलदीप चौधरी, विशेष सचिव सह निदेशक सूचना जन संपर्क विभाग, राजीव लोचन पदाधिकारी, परियोजना निदेशक प्ज्व। रांची, मनीषा तिर्की, जिला जन संपर्क पदाधिकारी रांची, उर्वशी पांडेय एवं सम्बंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। यह ऐतिहासिक जतरा भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क बिरसा मुंडा कारागृह जेल मोड़ से प्रारंभ होकर करम टोली चौक होते हुए एसएसपी आवास से होते हुए मोरहाबादी पहुंची । पूरे मार्ग में जनजातीय संस्कृति की अनुपम झलक देखने को मिली। जतरा में झारखण्ड के सभी जिलों से लगभग 10 हजार कलाकार शामिल हुए । ये कलाकार राज्य की विभिन्न जनजातियों-संथाल, मुंडा, हो, उरांव, खड़िया, खरवार और अन्यख्रसे संबंधित हैं। उन्होंने अपने-अपने पारंपरिक स्थानीय वेश-भूषा, आभूषण और वाद्ययंत्रों (ढोल, नगाड़ा, मांदर, बाँसुरी

आदि) से सुसज्जित होकर इस भव्य आयोजन में भाग लिया जतरा में कुल 6 आकर्षक झाँकियों का भी प्रदर्शन किया गया, जिनमें भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और आदिवासी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। यह जतरा केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भगवान बिरसा मुंडा के त्याग, बलिदान और आदिवासी अस्मिता के संरक्षण का प्रतीक है। इसमें शामिल कलाकारों की विशाल संख्या और विविध जनजातीय प्रतिनिधित्व झारखण्ड की सांस्कृतिक एकता और गौरव को प्रदर्शित करता है। मंत्री चमरा लिंडा ने इस अवसर पर सभी कलाकारों, आयोजकों और प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन आदिवासी युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और झारखण्ड की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। मंत्री ने जतरा की सफलता की कामना करते हुए सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में आम नागरिक, संस्कृति प्रेमी और अधिकारीगण भी उपस्थित रहे, जिन्होंने कलाकारों के उत्साहपूर्ण प्रदर्शन की भरपूर सराहना की।●

सीएमपीडीआई और सिपेट के बीच एमओए पर हस्ताक्षर

● गुड्डी साव

युवाओं को सशक्त बनाने और सतत आजीविका के अवसर उत्पन्न करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए 5 अगस्त को सीएमपीडीआई ने सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी सिपेट, रांची के साथ एक समझौते ज्ञापन एमओए पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपनी निगमित सामाजिक दायित्व सीएसआर पहल के अंतर्गत वंचित, बेरोजगार एवं अर्द्धरोजगार युवाओं को आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया गया है। इस एमओए पर सीएमपीडीआई, रांची की ओर से महाप्रबंधक मानव संसाधन/सीएसआर संजय कडम्बार और सिपेट, रांची के निदेशक और प्रमुख अवनीत कुमार जोशी ने औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। इस मौके पर सीएमपीडीआई मुख्यालय के सीएसआर टीम और सिपेट, रांची के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस एमओए के तहत झारखंड राज्य के रांची, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद और लातेहार जिलों के 80 वंचित, बेरोजगार एवं अर्द्धरोजगार युवाओं को सिपेट, रांची में मशीन आपरेटर-प्लास्टिक प्रोसेसिंग एमओ-पीपी एवं मशीन आपरेटर-टूल रूम एमओ-टीआर जैसे उद्योग-उन्मुखी ट्रेडो में आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक कोर्स में 40 उम्मीदवार होंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्रित शिक्षा, व्यावहारिक अनुभव और व्यापक कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को चार महीने के दौरान कुल 600 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह पूर्ण रूप से आवासीय आधारित होगा। इस परियोजना को लागू करने के लिए सीएमपीडीआई ने कुल 47 लाख 52 हजार का बजट आवंटित किया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रतिभागियों को उद्योग के लिए प्रासंगिक तकनीकी कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे प्लास्टिक प्रोसेसिंग और विनिर्माण क्षेत्रों में उनके रोजगार के अवसर को बढ़ावा देगा। कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् इन प्रशिक्षुओं को प्लास्टिक प्रोसेसिंग, टूल रूम संचालन और संबंधित विनिर्माण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगों में बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे।●

अरगड़ा क्षेत्र में एक दिवसीय समाधान शिविर का आयोजन

● गुड्डी साव

अरगड़ा क्षेत्र में सामाधान शिविर का आयोजन 5 अगस्त को किया गया साथ ही कर्मचारियों की शिकायतों का हुआ त्वरित निस्तारण जिसमें कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न सेवा संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों को प्रबंधन के समक्ष रखा। शिविर की अध्यक्षता समाधान प्रकोष्ठ के मुख्य प्रबंधक गौतम चौधरी ने की। इस अवसर पर अरगड़ा क्षेत्र के स्टाफ अधिकारी मानव संसाधन एवं प्रशासन राजीव कुमार, मुख्य प्रबंधक कार्मिक तेजविंदर सिंह सहित श्रीमती ऋचा टाइटस वरि प्रबंधक मानव संसाधन/नोडल अधिकारी समाधान सेल, स्टाफ अधिकारी सिविल, सभी इकाईओं के मानव संसाधन अधिकारी एवं अन्य उपस्थित रहे। शिविर के दौरान कर्मचारियों द्वारा आवास अनुरक्षण, पदोन्नति तथा अन्य सेवा संबंधी मामलों की समीक्षा की गई। संवेदनशीलता एवं तत्परता का परिचय देते हुए अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर कर्मचारियों को तत्काल राहत प्रदान की। वहीं, जिन मामलों के समाधान हेतु विस्तृत प्रक्रिया आवश्यक थी, उन्हें नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई के लिए दर्ज किया गया। यह पहल कर्मचारियों की शिकायतों के शीघ्र निस्तारण तथा पारदर्शी एवं उत्तरदायी कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में सीसीएल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।●

किताब से कंटीले तार तक झारखण्ड का युवा आखिर सड़क पर क्यों?

● **भारती मिश्रा**

सुबह से किताब खोलकर बैठा एक लड़का शायद यह सोच रहा था कि आज संविधान पढ़ना है, गणित के सवाल लगाने हैं और शाम तक सामान्य ज्ञान दोहराना है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही लड़का विधानसभा के रास्ते पर खड़ा दिखाई देता है। हाथ में किताब नहीं। सामने कंटीले तार। बीच में पुलिस और सवाल वही नौकरी कब मिलेगी और परीक्षा पर भरोसा कब होगा? यही झारखंड के मौजूदा छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी तस्वीर है। यह कहानी 10 अगस्त से शुरू नहीं हुई। विधानसभा घेराव को अगर सिर्फ एक दिन की घटना मान लिया जाए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। 10 अगस्त को छात्र विधानसभा की ओर बढ़े। प्रशासन ने रास्ते में बैरिकेड लगाए, कंटीले तार लगाए और सुरक्षा बढ़ाई। टकराव हुआ। पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन सवाल यह है कि हजारों छात्र वहां पहुंचे क्यों? क्या उन्हें अचानक विधानसभा की याद आ गई थी? नहीं। इसके पीछे वर्षों की प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया को लेकर जमा हुआ असंतोष है। एक परीक्षा खत्म होती है, दूसरा विवाद शुरू।

झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं की कहानी कुछ ऐसी हो गई है-परीक्षा की तैयारी करो। परीक्षा दो। रिजल्ट का इंतजार करो। फिर विवाद की खबर सुनो। फिर जांच की मांग करो। फिर परीक्षा रद्द होने की आशंका। फिर अगली परीक्षा का इंतजार और इसी बीच उम्र आगे बढ़ती रहती है। छात्र मजाक में कह सकता है- "यहां सरकारी नौकरी

की तैयारी से ज्यादा तैयारी इंतजार की करनी पड़ती है।" लेकिन इस मजाक के पीछे एक गंभीर दर्द है। जब मेहनत पर शक होने लगे- JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं को लेकर पिछले वर्षों में कई बार सवाल उठे हैं। हाल के विवाद में अभय तिवारी का नाम जांच के सिलसिले में सामने आया है। परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच की जा रही है। राजनीतिक बयानबाजी में "नौकरी बेचने" जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन यहां तथ्य और आरोप के बीच फर्क रखना जरूरी है। आरोप लगना अपराध साबित होना नहीं है। फिर भी छात्र के लिए ऐसी खबरें बेचैनी पैदा करती हैं। क्योंकि उसने नौकरी खरीदने के लिए नहीं, नौकरी पाने के लिए पढ़ाई की है। उसने साल लगाए हैं। पैसा लगाया है। घरवालों की उम्मीद लगाई है। और जब उसे लगता है कि परीक्षा की व्यवस्था ही भरोसे के लायक नहीं रही, तो उसका गुस्सा सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रहता। फिर सरकार ने बात की सरकार ने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया। चार मंत्रियों ने छात्रों से मुलाकात की। कई दौर की बातचीत हुई। कुछ मांगों पर सरकार ने सहमति भी जताई। सरकार की तरफ से कहा गया कि छात्रों की लगभग 98 प्रतिशत मांगें मान ली गई हैं। 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा समेत कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और 14वीं JPSC से जुड़े वित्तीय आरोपों की जांच ED से कराने पर भी सहमति बनी। यह सरकार की तरफ से बड़ा कदम था। फिर आंदोलन क्यों नहीं रुका? यहीं कहानी पलटती है।

छात्र कहता है-अभी असली बात बाकी है, छात्रों की नजर में दो बड़े सवाल अभी भी खड़े हैं। पहला-CBI जांच, दूसरा-JSSC-CGL परीक्षा। छात्र कथित गड़बड़ियों की जांच CBI से कराने और JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार इन मांगों पर सहमत नहीं हुई। इसलिए सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के बाद भी दूरी बनी रही। सरकार के लिए यह 98 प्रतिशत है। छात्र के लिए वह बाकी हिस्सा है जिसमें उसके आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण मांगें शामिल हैं। यही वजह है कि बातचीत खत्म होने के बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कहां हैं? इसके साथ एक राजनीतिक सवाल भी जुड़ गया। छात्र चाहते हैं कि मुख्यमंत्री खुद उनसे मिलें। सरकार की ओर से मंत्री बातचीत कर रहे हैं। लेकिन छात्रों को लगता है कि अंतिम जवाब मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। यानी अब आंदोलन सिर्फ परीक्षा का नहीं रहा। यह संवाद और भरोसे का भी सवाल बन गया है और फिर आया कंटीला तार। विधानसभा लोकतंत्र का वह स्थान है जहां जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं। उसी विधानसभा की ओर जाने वाले रास्ते पर जब छात्रों के सामने कंटीले तार लगाए जाते हैं, तो तस्वीर अपने आप एक सवाल बन जाती है। सरकार कहेगी-कानून-व्यवस्था जरूरी है। छात्र कहेगा-हम अपनी बात कहने आए हैं। दोनों की अपनी जगह हो सकती है, लेकिन तस्वीर फिर भी चुभती है। क्योंकि जिस युवा को लोकतंत्र में अपनी बात कहनी चाहिए, वह लोकतंत्र के दरवाजे तक पहुंचने से पहले कंटीले तार के सामने खड़ा है। असली गुस्सा किस बात का है? शायद नौकरी न मिलने का नहीं। शायद सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने का भी नहीं। असल गुस्सा है-बार-बार

अनिश्चितता का। छात्र जानना चाहता है कि परीक्षा कब होगी। पेपर सुरक्षित रहेगा या नहीं। रिजल्ट कब आएगा। अगर गड़बड़ी हुई तो कौन जिम्मेदार होगा और सबसे जरूरी- क्या ईमानदारी से पढ़ने वाला छात्र अंत में जीत पाएगा? यह सवाल जितना सीधा है, उसका जवाब उतना ही मुश्किल होता जा रहा है।

झारखंड के युवा की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी से आगे है। बेरोजगारी बड़ी समस्या है लेकिन बेरोजगार युवा के लिए उससे भी बड़ी समस्या है अनिश्चितता। अगर उसे पता हो कि परीक्षा होगी, निष्पक्ष होगी और समय पर नौकरी मिलेगी, तो वह शायद वर्षों तक मेहनत कर सकता है। लेकिन जब हर परीक्षा के साथ विवाद की आशंका जुड़ जाए, तो मेहनत के साथ डर भी जुड़ जाता है। और डर धीरे-धीरे गुस्से में बदलता है। कंटीले तार किसे रोक रहे हैं? छात्रों को? शायद। लेकिन क्या सिर्फ छात्रों को रोकने से समस्या रुक जाएगी? परीक्षा का विवाद रुक जाएगा? पेपर लीक की चिंता रुक जाएगी? नौकरी को लेकर उठ रहे सवाल रुक जाएंगे? नहीं। क्योंकि असली समस्या सड़क पर खड़ा छात्र नहीं है। असली समस्या वह भरोसा है जो धीरे-धीरे सड़क पर गिर रहा है। आखिर रास्ता क्या है? रास्ता बहुत मुश्किल भी नहीं है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो। परीक्षा समय पर हो। पेपर लीक और गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई हो। जांच निष्पक्ष हो। दोषियों की जिम्मेदारी तय हो और सरकार छात्रों से सिर्फ बातचीत न करे, बल्कि स्पष्ट समयसीमा के साथ समाधान दे। छात्रों की भी जिम्मेदारी है कि आंदोलन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण रहे। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का काम सिर्फ कानून-व्यवस्था संभालना नहीं है। उसे विश्वास भी संभालना होता है। आखिरी सवाल, विधानसभा के बाहर कंटीले तार आज हैं। कल शायद नहीं होंगे। बैरिकेड हट जाएंगे। पुलिस हट जाएगी। आंदोलन भी किसी दिन खत्म हो जाएगा लेकिन झारखंड के युवा के मन में एक सवाल तब भी रहेगा-"क्या अगली परीक्षा सचमुच सिर्फ परीक्षा होगी, या उसके साथ फिर कोई नया विवाद भी आएगा?" क्योंकि छात्र विधानसभा घेरने नहीं पैदा हुआ है। वह नौकरी पाने के लिए पढ़ रहा है। वह चाहता है कि उसकी किताब फिर उसके हाथ में हो। सड़क का झंडा नहीं। और शायद इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश भी यही है-झारखंड के युवाओं को कंटीले तार नहीं चाहिए। उन्हें ऐसी भर्ती व्यवस्था चाहिए, जिस पर उन्हें भरोसा हो।●

छात्र आंदोलन और विपक्ष के हंगामे में भेंट चढ़ गया झारखण्ड का मानसून सत्र

● भारती मिश्रा

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो गया। लेकिन इस बार सत्र की पहचान उसके कामकाज से ज्यादा हंगामे से बनी। सड़क पर छात्रों का आंदोलन था, विधानसभा के भीतर विपक्ष सरकार को घेर रहा था और केंद्र में JPSC, JSSC तथा JSSC-CGL से जुड़ी परीक्षाओं के विवाद थे। इन मुद्दों का असर इतना रहा कि जनता से जुड़े कई दूसरे सवाल पीछे छूट गए। आखिरकार विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा का सत्र तय समय से एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर जवाब देने से बच रही है और इसी वजह से सत्र को समय से पहले खत्म किया गया। सरकार का पक्ष इससे अलग रहा। लेकिन राजनीतिक आरोपों से अलग इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। इस टकराव में विधानसभा का वह समय कम हो गया, जो राज्य की जनता के दूसरे जरूरी सवालों पर चर्चा के लिए था।

☞ **JPSC–JSSC–CGL के बीच सिमट गया रोजगार का सवाल :-** JPSC की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा, JSSC की भर्ती परीक्षाएं और JSSC-CGL को लेकर उठे सवाल निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण थे। परीक्षा की पारदर्शिता, पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों पर चर्चा होना जरूरी था। युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला होने के कारण विधानसभा में इसे उठाना भी स्वाभाविक था। लेकिन रोजगार का सवाल केवल सरकारी भर्ती परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। झारखंड के युवाओं के सामने निजी क्षेत्र में रोजगार, कौशल विकास, पलायन और स्थानीय स्तर पर अवसरों की भी चुनौती है। इन व्यापक सवालों पर जितनी चर्चा होनी चाहिए थी, वह भर्ती परीक्षा विवाद के शोर में पीछे जाती दिखाई दी। यही स्थिति शिक्षा के मामले में भी रही। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, कॉलेजों की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, पानी, किसानों की समस्याएं और आदिवासी इलाकों से जुड़े सवाल भी विधानसभा के सामने थे। लेकिन सत्र का राजनीतिक केंद्र बार-बार JPSC-JSSC-CGL की तरफ लौटता रहा।

☞ **सड़क का आंदोलन सदन के हंगामे में बदला :-** छात्र सड़क पर थे और विपक्ष ने उनके मुद्दे को सदन में उठाया। सरकार से जवाब मांगा गया। इसके बाद हंगामा बढ़ता गया और कई मौकों पर विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित हुई। विपक्ष का सरकार को घेरना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर छात्रों की परीक्षा से जुड़ी शिकायतें हैं तो उन्हें विधानसभा में उठाना भी जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी एक मुद्दे का लगातार हावी रहना पूरे सदन के कामकाज को प्रभावित कर सकता है? विधानसभा का हर दिन महत्वपूर्ण होता है। एक दिन में विधायकों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठानी होती हैं, सरकार से जवाब लेना होता है और नीतियों पर चर्चा करनी होती है। जब कार्यवाही हंगामे में जाती है तो उसका नुकसान सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष को नहीं, बल्कि उन लोगों को भी होता है जिनकी आवाज सदन तक पहुंचाने के लिए उनके विधायक बैठे हैं।

☞ **एक दिन पहले स्थगित हुआ सत्र, पीछे रह गए कई सवाल :-** मानसून सत्र का तय समय पूरा होने से एक दिन पहले ही कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने इसे सरकार की रणनीति बताते हुए आरोप लगाया कि वह छात्रों के मुद्दे पर जवाब देने से बचना चाहती थी। यह आरोप राजनीतिक बहस का हिस्सा है। लेकिन एक दिन कम होने का मतलब विधानसभा में चर्चा का एक अवसर कम होना भी है। उस एक दिन में कौन-से सवाल पूछे जाते, किन मुद्दों पर मंत्री जवाब देते और कितने विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याएं सदन में रखते, अब यह सब अनुमान का विषय है। यही वजह है कि इस सत्र का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि JPSC-JSSC-CGL पर कितनी बहस हुई। यह भी देखना होगा कि इन मुद्दों के बीच कौन-से सवाल पीछे छूट गए।

☞ **जनता की विधानसभा में जनता के बाकी सवाल :-** जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनकी आवाज विधानसभा तक पहुंच गई। विपक्ष ने उसे जोर से उठाया और सरकार को जवाब देना पड़ा। लेकिन हर मुद्दा आंदोलन के जरिए विधानसभा तक नहीं पहुंचता। वह किसान भी जनता है जो सिंचाई की समस्या से परेशान है। वह गांव भी जनता है जहां सड़क या पेयजल की समस्या है। वह परिवार भी जनता है जो अस्पताल में इलाज के लिए परेशान है। वह बेरोजगार युवा भी जनता है जो किसी भर्ती परीक्षा के आंदोलन का हिस्सा नहीं है। विधानसभा की जिम्मेदारी सिर्फ सबसे ज्यादा शोर वाले मुद्दे को सुनना नहीं है। उसे उन आवाजों को भी जगह देनी होती है जो खुद सदन तक नहीं पहुंच सकतीं।

☞ **असली नुकसान किसका हुआ? :-** इस पूरे घटनाक्रम में सरकार, विपक्ष और छात्रख़तीनों के अपने-अपने तर्क हैं। छात्रों का आंदोलन अपनी जगह जरूरी था। विपक्ष का सरकार से जवाब मांगना भी जरूरी था। सरकार का अपना पक्ष रखना भी स्वाभाविक था। लेकिन लोकतंत्र में सवाल सिर्फ यह नहीं होता कि किसने किसे घेरा। सवाल यह भी होता है कि इस टकराव के बीच जनता के कितने सवालों पर चर्चा हो पाई। इस मानसून सत्र में JPSC-JSSC-CGL का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि विधानसभा की पूरी राजनीतिक तस्वीर उसी के आसपास घूमती रही। सड़क पर आंदोलन था, सदन में हंगामा था और आखिर में सत्र एक दिन पहले ही समाप्त हो गया।

☞ **मानसून सत्र की सबसे बड़ी तस्वीर :-** मानसून सत्र अब खत्म हो चुका है। JPSC, JSSC और CGL के विवाद अपनी जगह हैं और इन पर आगे भी बहस होती रहेगी। लेकिन इस सत्र की सबसे बड़ी सीख शायद यह है कि विधानसभा किसी एक आंदोलन, किसी एक दल या किसी एक मुद्दे की नहीं होती। सरकार से सवाल पूछना जरूरी है। विपक्ष का विरोध भी लोकतंत्र का हिस्सा है। छात्रों की आवाज भी सुनी जानी चाहिए। लेकिन इन सबके बीच विधानसभा को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके सामने पूरे झारखंड की जनता के सवाल होते हैं। इस बार सड़क के आंदोलन और सदन के हंगामे के बीच मानसून सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन जनता के कई सवाल अपनी बारी का इंतजार करते रह गए। यही इस मानसून सत्र की सबसे बड़ी विडंबना है।●

ऑपरेशन नवजीवन

पुलिस मुख्यालय में 16 खूंखार नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

● **ओम प्रकाश**

झारखंड पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। 28 जुलाई मंगलवार को एक बड़ी और ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई। झारखण्ड पुलिस मुख्यालय, राँची में आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाकपा (माओवादी) संगठन से जुड़े 16 खूंखार नक्सलियोंने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष विधिवत आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 39 लाख रुपये के कुल इनामी छह नक्सली शामिल हैं। इस समूह में 11 पुरुष और 5 महिला नक्सली हैं। इनके पास से 11 हथियार और 1562 कारतूस बरामद किए गए हैं। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति और झारखण्ड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा तथा झारखण्ड जगुआर द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन 'नवजीवन-II' से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने हिंसा और गोलियों का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का संकल्प लिया। झारखंड के डीजीपी तदाशा मिश्र ने बताया कि झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियानों से माओवादी संगठन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। साथ ही राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के कारण भी कई नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं।

❖ **सारंडा और कोल्हान के चप्पे-चप्पे से वाकिफ थे ये नक्सली :-** आत्मसमर्पण करने वाले ये नक्सली भाकपा (माओवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा उर्फ सागर जी और केंद्रीय कमेटी सदस्य असीम मंडल की टीम के प्रमुख कमांडर और मारक दस्ते के सक्रिय सदस्य थे। ये पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) के सुदूर सारंडा और कोल्हान के जंगलों के चप्पे-चप्पे से वाकिफ थे और इलाके में कई बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। इस

दस्ते के 15 सदस्य झारखण्ड के चाईबासा, लातेहार,लोहरदगा, हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, राँची, सरायकेला और गिरिडीह जिलों के रहने वाले हैं, जबकि 1 सदस्य ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले का निवासी है।

❖ **आत्मसमर्पण करने वाले 16 नक्सलियों की लिस्ट और इनामों का ब्योरा :-**

☞ संतोष उर्फ बासुदेव दा (RCM) : रीजनल कमेटी सदस्य, जिस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित था (कुल 128 मामले दर्ज)।

☞ संतोष मांझी उर्फ जगबंधु (ZCM): जोनल कमेटी सदस्य, 10 लाख रुपये का इनामी (32 मामले दर्ज)।

☞ चंदन लोहरा (ZCM): जोनल कमेटी सदस्य (78 मामले दर्ज)।

☞ जयकांत मुंडा उर्फ बंगाली (ZCM): जोनल कमेटी सदस्य (38 मामले दर्ज)।

☞ राजनाथ हांसदा उर्फ गुना (SZCM): सब जोनल कमेटी सदस्य (06 मामले दर्ज)।

☞ अनिल तुरी उर्फ उज्ज्वल (SZCM): सब जोनल कमेटी सदस्य, 5 लाख रुपये का इनामी (22 मामले दर्ज)।

☞ सुखलाल बिरंजिया उर्फ अकेला (SZCM): सब जोनल कमेटी सदस्य, 5 लाख रुपये का इनामी (12 मामले दर्ज)।

☞ सुदेश होनहागा (ACM): एरिया कमेटी सदस्य, 2 लाख रुपये का इनामी (33 मामले दर्ज)।

☞ एतवारी मांझी उर्फ सोनोत उर्फ संत उर्फ शनिचरवा, एरिया कमेटी सदस्य (ACM)।

☞ देवान मुर्मू उर्फ शनिचर, एरिया कमेटी सदस्य (ACM)।

☞ सुमित्रा सुरिन, एरिया कमेटी सदस्य (ACM)।

☞ चंपा मांझियाइन उर्फ गुड़िया, (संथाल) कैडर सदस्य।

☞ रिसिव, एरिया कमेटी सदस्य (ACM)।

☞ सालेमी मुंडा उर्फ पारुल, एरिया कमेटी

सदस्य (ACM)।

☞ मुन्नी सुरिन उर्फ मुरीन सुरिन, कैडर सदस्य।

☞ सीता मुंडा, कैडर सदस्य।

❖ **सरेंडर के दौरान सौंपे गए आधुनिक हथियार और कारतूस :-**

❖ **नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के दौरान हथियारों और गोलियों का बड़ा जखीरा पुलिस के सुपुर्द किया :-**

☞ **अत्याधुनिक राइफलें (11) :-** 6 इंसास राइफल, 2 एके-47, 1 एचके-33, 1 यूएस कार्बाइन और 1 एम-16 (ड-16) राइफल ।

☞ **मैगजीन (38) :-** 28 इंसास, 4 एके-47, 3 एलएमजी, 2 यूएस कार्बाइन और 1 एम-16 मैगजीन

☞ **कारतूस (1,562 राउंड) :-** 786 इंसास, 244 एम-16, 229 एके-47, 208 एचके-33 और 95 यूएस कार्बाइन कारतूस शामिल हैं।

❖ **आईईडी ब्लास्ट और जवानों की शहादत में रहे थे शामिल : आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कई जघन्य वारदातों में शामिल रहे हैं, इनमें शामिल प्रमुख घटनाएं :-**

☞ **गोईलकेरा में पूर्व विधायक पर हमला (2022) :** पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के दो अंगरक्षकों की हत्या कर हथियार लूटने में चंदन लोहरा व सुदेश होनहागा शामिल थे।

☞ **आईईडी ब्लास्ट व मुठभेड़ :** टोंटो, छोटानागरा और जराईकेला के जंगलों में हुए आईईडी विस्फोटों में सुरक्षाबलों के कई जवान शहीद व घायल हुए थे, जिनमें संतोष मांझी, जयकांत मुंडा, चंदन लोहरा और मुन्नी सुरीन जैसे नाम शामिल थे।

☞ **लातेहार में माइन ब्लास्ट (2018) :** खपरी महुआ में लैंडमाइंस ब्लास्ट में झारखंड जगुआर के 6 जवान शहीद हुए थे, जिसमें अनिल तुरी शामिल था।

☞ **जंगल के कठिन जीवन से तंग आकर छोड़ा हिंसा का रास्ता :-** सालों तक बंदूक के दम पर अपनी समानांतर सरकार चलाने का दावा करने वाले इन नक्सलियों का अचानक हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे जंगलों की कड़वी सच्चाई है। सुरक्षाबलों के नए कैंपों के बनने से नक्सलियों के छिपने और राशन-पानी जुटाने के ठिकाने खत्म हो गए। इसके साथ ही संगठन के भीतर शीर्ष नेताओं की मनमानी, निचले कैडरों का शोषण और लगातार बढ़ता अविश्वास उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। एक तरफ जंगलों में हर पल मंडराता मौत का खतरा था, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का खुला दरवाजा। बेहतर जीवन, अपने परिवार के पास लौटने की चाह और बच्चों के भविष्य की चिंता ने इन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया।

☞ **मेज पर सजे एके-47 और गोलियों के ढेर से बयां हुई सरेंडर की कहानी :-** मंगलवार को जब यह 16 नक्सली पुलिस अधिकारियों के सामने आए, तो उन्होंने सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई, बल्कि अपने साथ उन घातक हथियारों को भी जमा करा दिया जो सालों से बेगुनाहों और सुरक्षाबलों का खून बहा रहे थे। पुलिस के सामने 2 एके-47, 6 इंसास, 1 एम-16, 1 एचके-33 और 1 यूएस कार्बाइन समेत कुल 11 अत्याधुनिक राइफलें रखी गईं। इसके साथ ही 38 मैगजीन और 1562 जिंदा गोलियां भी सौंपी गई। इन हथियारों का पुलिस के कब्जे में आना माओवादियों की मारक क्षमता पर बहुत बड़ा प्रहार है। हथियार सौंपने वालों में 11 पुरुषों के साथ 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं, जो जंगलों की अमानवीय जिंदगी से तंग आकर मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला कर चुकी थीं।

☞ **साल 2026 में बिखरता माओवादी नेटवर्क, अब खातमे की ओर कदम :-** यह सरेंडर केवल एक दिन की सफलता नहीं है, बल्कि साल 2026 में सुरक्षाबलों द्वारा लगातार चलाए गए आक्रामक अभियानों का सीधा परिणाम है। इस साल अब तक 93 नक्सलियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, 45 नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके हैं और मुठभेड़ों में 22 खूंखार नक्सली मारे गए हैं। मई के महीने में 27 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर होना और फिर शीर्ष कमांडरों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाइयों ने माओवादी ढांचे की कमर पूरी तरह तोड़ दी है। पुलिस प्रशासन ने बचे हुए नक्सलियों से भी अपील की है कि वे हिंसा और भय का रास्ता छोड़कर झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति योजना का लाभ उठाएं और समाज में सम्मानजनक जीवन की शुरुआत करें।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े।

खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

सद्दाम अंसारी के साथ रमेश स्वर्णकार गिरफ्तार

● ओम प्रकाश

राजधानी रांची में पुलिस ने चेन स्नेचिंग करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर चेन स्नेचर और चोरी के गहने खरीदने वाले ज्वेलर्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 19 ग्राम गलाया हुआ सोना, एक चोरी की टीवीएस स्कूटी (JH03AN4087) और एक पैशन प्रो बाइक (JH01CE9582) बरामद की है। डीएसपी मुख्यालय प्रथम अमर कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि चोरी के दो पहिया वाहन पर सवार होकर कुछ अपराध कर्मी नामकुम की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद नामकुम थाना प्रभारी एवं नामकुम गश्ती दल के द्वारा रेलवे फ्लाई ओवर के पास नामकुम की तरफ चेकिंग प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में समय करीब पांच बजे देखा गया कि एक युवक काले रंग के हीरो पैशन प्रो मोटरसाईकिल पर सवार होकर आ रहा है। उसके नजदीक आने पर उसे चेकिंग के लिए रूकने का इशारा किया गया, परन्तु वह मोटरसाईकिल को आडा-तिरछा कर भागने का प्रयास किया, जिसे सशस्त्र बल की सहायता से पकड़ लिया गया।

☞ **दो माह पहले पतरातु पार्क से मोटरसाईकिल चोरी की थी और मिटा दिया था चेचिस नंबर :-** पकड़ाये युवक से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम सद्दाम अंसारी, उम्र 30 वर्ष, पिता इजहार अंसारी, पता बी०आई०टी० सिरतनगर, थाना मेसरा ओ०पी०, जिला राँची बताया। पूछताछ में सद्दाम मोटरसाईकिल के कागजात नहीं दिखा सका। जब मोटरसाईकिल की बारिकी से जाँच की गई तो पाया गया कि मोटरसाईकिल का चेचिस नंबर घिस कर मिटाया गया है। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि दो माह पहले पतरातु पार्क से मोटरसाईकिल चोरी की थी और उसी के जरिए शहर के अलग-अलग इलाकों में महिलाओं से चेन छिनतई की वारदातों को अंजाम देता था।

☞ **चोरी का वाहन पाये जाने पर पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन को जप्त किया गया :-** गिरफ्तार आरोपी ने आगे बताया कि उसके द्वारा पतरातु क्षेत्र से एक स्कूटी जिसका रजि०नं0-JH03AN-4087 है की चोरी कर उसे अपने घर में छिपाकर रखा गया है, जिसे बाद स्कूटी को भी जब्त किया गया। साथ ही इसके द्वारा मार्च 2026 में नामकुम स्टेशन के पास महिला से सोने की चेन छिनतई, अप्रैल 2026 में कॉके थानान्तर्गत अरसण्डे महावीर स्थल गली में वृद्ध महिला से व लालपुर थाना अन्तर्गत महेन्द्र प्रसाद महिला इंटर कॉलेज के पास महिला के गले से सोने की चेन छिनतई एवं इसके अलावा इसने स्वीकार किया कि जून 2026 में बरियातु थाना अन्तर्गत हरीहर सिंह रोड स्थित मंदिर के पास महिला के गले से सोने की चेन छिनतई की घटना इसने अपने एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर अंजाम दिया था।

☞ **B.I.T. मेसरा चौक स्थित वर्मा ज्वेलर्स में खपाया जाता था चोरी का माल :-** गिरफ्तार आरोपी द्वारा अपने स्वीकरोक्ति बयान में बताया गया कि उक्त सभी घटनाओं में छिनतई किये गए आभुषण को B.I.T. मेसरा चौक स्थित वर्मा ज्वेलर्स के मालिक रमेश प्रसाद स्वर्णकार को औने-पौने दाम में बेची गई है, जिससे उसे लगभग 4,00,000/- रूपया रमेश प्रसाद सवर्णकार के द्वारा दिये गए हैं। गिरफ्तार सद्दाम की निशानदेही पर रमेश प्रसाद सवर्णकार की दुकान से गलाया हुआ सोना वजन करीब 19 ग्राम बरामद कर विधिवत जप्त किया गया।इसके बाद रमेश प्रसाद स्वर्णकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अबतक के अनुसंधान में यह ज्ञात हुआ है कि चोरी के वाहन का प्रयोग कर गिरफ्तार अपराध कर्मी के द्वारा चेन छिनतई का एक संगठित गिरोह बनाकर छिनतई की घटना को अंजाम दिया जाता है तथा कीमती आभुषण को ज्वेलरी के दुकान में खपाया जाता है। घटना में गिरफ्तार अभियुक्त के अन्य अपराधिक सहायोगि को चिन्हित कर लिया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है।

☞ **चार थानों में दर्ज हैं मामले :-** पुलिस के अनुसार सद्दाम अंसारी के खिलाफ नामकुम, कांके, बरियातू और लालपुर थानों में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह नामकुम स्टेशन के पास, कांके के अरसंडे, लालपुर के महिला कॉलेज क्षेत्र और बरियातू के हरीहर सिंह रोड स्थित मंदिर के समीप महिलाओं से चेन छिनतई की घटनाओं को अंजाम दे चुका है।●

❖ **छापामारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी/कर्मी :-**

☞ पु०नि० रामनारायण सिंह, पु०नि०-सह-थाना प्रभारी, नामकुम, राँची।

☞ पु०नि० रूपेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी, लालपुर थाना, राँची।

☞ पु०नि० प्रकाश रजक, पु०नि०-सह-थाना प्रभारी, बरियातु, राँची।

☞ पु०अ०नि० नकुल साह, बरियातु थाना, राँची।

☞ पु०अ०नि० गौतम कुमार नामकुम थाना, राँची।

☞ पु०अ०नि० शशिरंजन, नामकुम थाना।

☞ पु०अ०नि० जयदेव सराक, नामकुम थाना, राँची।

☞ स०अ०नि० मंटू सिंह, नामकुम थाना, राँची।

अप्राकृतिक यौनाचार, परी का झांसा, धन वर्षा और गई जान

● **ओम प्रकाश**

राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित कोकर के खोरहा टोली में हुये सनसनीखेज जमीन कारोबारी रमेश ठाकुर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अमित चौधरी, निरंजन स्वासी उर्फ नीरज और सचिन कुमार गुप्ता शामिल है। पुलिस ने इनके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार, खून से सना पिलाश, देसी पिस्टल, कारतूस, लूटा गया आभूषण, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे की कहानी बेहद चौंकाने वाली है, जिसमें तंत्र-मंत्र, धनवर्षा का लालच, अप्राकृतिक यौनाचार और आखिर में बेरहमी से हत्या जैसी कई परतें सामने आई हैं। रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि, बीते 22 जुलाई की रात अज्ञात अपराधियों ने रमेश ठाकुर की हत्या कर उनके पहने हुए आभूषण लूट लिये थे। मृतक के बेटे आकाश ठाकुर की शिकायत पर सदर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुये रांची एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई और 24 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, मृतक रमेश ठाकुर खुद को ओझा-गुनी और तांत्रिक बताकर युवकों को अपने जाल में फंसाता था।

पुलिस के मुताबिक, 22 जुलाई की रात तीनों आरोपियों ने पहले ही फैसला कर लिया था कि अगर इस बार भी कथित चमत्कार नहीं हुआ, तो रमेश की हत्या कर देंगे। योजना के तहत वे बाइक से उसके घर पहुंचे। वहां कथित तांत्रिक अनुष्ठान और अप्राकृतिक यौनाचार के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तो आरोपियों ने पहले देसी पिस्टल से गोली चलाने की कोशिश की। गोली निशाने पर नहीं लगी, जिसके बाद पास में रखे पिलाश से रमेश के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी उसके शरीर पर मौजूद आभूषण लेकर फरार हो गए।

☞ **परी से मुलाकात और धनवर्षा का लालच :-** जांच में पुलिस को पता चला कि मृतक रमेश ठाकुर खुद को ओझा-गुनी बताते थे। वे कुछ युवकों से दोस्ती कर उन्हें अपने कोकर स्थित घर बुलाते थे। वह उन्हें कथित तांत्रिक अनुष्ठानों और परी से मुलाकातष तथा ''धनवर्षा" का लालच देता था। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता था कि ऐसा करने पर "परी" आयेगी और उन पर धनवर्षा होगी। जांच में यह भी सामने आया कि मृतक कथित तांत्रिक प्रक्रिया के नाम पर युवकों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करता था। इसी दौरान रमेश ठाकुर की दोस्ती अमित चौधरी से हुई। बाद में अमित ने अपने दो साथियों सचिन कुमार गुप्ता और निरंजन स्वासी उर्फ नीरज को भी उससे मिलवाया। तीनों आरोपी लंबे समय तक रमेश की बातों में आकर कथित तांत्रिक प्रक्रिया में शामिल रहे, लेकिन जब न तो धन मिला और न ही कथित परी से मुलाकात हुई, तो उनके मन में गुस्सा भर गया।

☞ **पहले गोली चलाई फिर पिलास से कुचल डाला :-** पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन तीनों आरोपियों ने तय किया कि अगर इस बार भी कथित चमत्कार नहीं हुआ और परी नहीं आई तो रमेश ठाकुर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तीनों बाइक से पिस्टल और कारतूस लेकर उसके घर पहुंचे। वहां कथित तांत्रिक प्रक्रिया के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आरोपियों ने पहले पिस्टल से फायर किया, लेकिन गोली नहीं लगी। इसके बाद पास में रखे पिलास से रमेश ठाकुर के सिर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मृतक के पहने हुए आभूषण लेकर फरार हो गये।

☞ **तीन आरोपी गिरफ्तार, हथियार और लूट का सामन बरामद :-** पुलिस ने इस मामले में अमित चौधरी, निरंजन स्वासी उर्फ नीरज और सचिन कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस, खोखा, हत्या में इस्तेमाल खून लगा पिलास, लूटे गये रोल गोल्ड के गहने, खून से सने कपड़े, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (JH01CD-9858) और तीन मोबाइल फोन बरामद किये गये हैं। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा सदर कैंच संजीव बेसरा के नेतृत्व में गठित टीम ने किया। टीम में सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान शामिल रहे। ●

आपका राशिफल

पंडित तरुण झा

ज्योतिषचार्य

(ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ)

ब्रज किशोर ज्योतिष संस्थान

प्रताप चौक,

सहरसा-852201, (बिहार)

मो० :- 9470480168

मेष राशि :- आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये महीना बहुत शुभ साबित होगा, आपके सभी रुके हुए काम बनेंगे, हो सकता है कि आप इस माह नया मकान खरीद लें, इस महीने सेहत भी आपका साथ देगी, मगर प्रेग्नेंट महिलाएं अपना ध्यान रखें, यह वक्त परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का है, खासतौर से भाई-बहन के साथ संबंध उत्तम रहेंगे!

वृषभ राशि :- किसी खास व्यक्ति की सलाह से आपको बड़ा लाभ होगा, धन की भी कोई कमी नहीं रहेगी, मगर पैसों को सही जगह निवेश करें, आपका घरेलू जीवन भी सुखमय रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और परिवार में भी मान सम्मान में वृद्धि होगी, जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें, पैसों के लेन-देन से जुड़े मामलों में लापरवाही न बरतें, यह महीना छात्रों के लिए नॉर्मल रहेगा

मिथुन राशि :- कोई बेहद करीबी व्यक्ति आपको धोखा देगा, इसलिए कोशिश करें कि किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, अपने कायक्षेत्र में आप व्यस्त रहेंगे और घरवालों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएंगे, जिनका प्रेम संबंध है, उन्हें इस माह अपने प्रेमी से विवाह करने की अनुमति परिवार से मिल सकती है!

कर्क राशि :- यदि आप शेयर इत्यादि में निवेश करते हैं तो इस माह थोड़ा सावधानी बरतें, हो सकता है कि आपको इससे बड़ा धन लाभ मिले, जितना परिश्रम करेंगे उतना धन कमा सकेंगे, नौकरीपेशा हैं तो हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाये, बेरोजगारों को अभी और भागदौड़ करनी पड़ सकती है।

सिंह राशि :- हो सकता है कि आपको किसी खास कार्य को पूरा करने में ऋण लेना पड़े, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं, सतर्क रहें परिवार में ही कोई सदस्य आपको धोखा दे सकता है, वैवाहिक जीवन के लिए समय उत्तम रहेगा। पेट से जुड़ी कोई परेशानी उभर सकती है, हो सके तो साफ-सफाई का ख्याल रखें और किसी भी प्रकार की गंदगी से दूर रहें।

कन्या राशि :- किसी भी तरह के उधार पैसों के लेन-देन से बचें, आपका घरेलू जीवन इस माह उत्तम रहेगा, नया वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है, दोस्तों और भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत बनेंगे, सेहत के लिहाज से भी यह माह आपके लिए बुहत अच्छा साबित होगा!

तुला राशि :- धन हानि के योग बन रहे हैं, शेयर बाजार में घाटा हो सकता है, पैसे सोच समझ कर ही निवेश करें, परिवार के ज्यादातर सदस्यों की सेहत खराब रहेगी, इससे आपका मन काफी अशांत रहेगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना ही आपके लिए सही रहेगा, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा!

वृश्चिक राशि :-आप इस माह नए आभूषण खरीद सकते हैं, इस माह आप मौज मस्ती और अपने शौक पूरे करने के लिए काफी धन खर्च करेंगे, घर परिवार के साथ अच्छा समय भी बीतेगा, हो सकता है कि आप इस माह कुछ धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहें, इस माह आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, अकेलापन खत्म हो सकता है और रिश्तों में मजबूती आएगी।

धनु राशि :- परिवारिक सदस्यों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा, कार्यक्षेत्र में किसी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव जाग सकता है, खुद को तनाव रहित रखने के लिए आप अपने परिवार के साथ कहीं सैर-सपाटे के लिए जा सकते हैं। नौकरी पेशा हैं तो उच्च अधिकारियों से उलझने से बचें।

मकर राशि :- रुका हुआ पैसा भी वापिस मिल सकता है,अपने खर्चों को कम करें, पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, आप परिवार पर ध्यान देंगे और उनको सुख सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करेंगे, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और सेहत के प्रति कोई लापरवाही न करें वरना आपको मौसमी रोग लग सकते हैं।

कुंभ राशि :- आपको धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे, प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे, जीवनसाथी से आपको कोई अच्छा उपहार मिल सकता है, जो आपके मन को खुश कर देगा।

मीन राशि :-नई खरीददारी की संभावनाएं प्रबल रहेंगी, सोच समझ कर धन खर्च करें, अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे, हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, अधिक काम के चलते परिवार वालों के साथ वक्त बिता पाना कठिन होगा।

✯ सामान्य आशा एवं सामान्य उद्देश्य किस प्रकार का अपराध है एवं दोनों में क्या प्रमुख अंतर होता है?

सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य भारतीय कानून (IPC/भारतीय न्याय संहिता) के दो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो किसी अपराध में एक से अधिक लोगों के शामिल होने पर लागू होते हैं। मुख्य अंतर यह है कि सामान्य आशय में अपराध करने से पहले दिमागों का मिलन (पूर्व-योजना) जरूरी है, जबकि सामान्य उद्देश्य के लिए केवल एक गैर-कानूनी मंडली का सदस्य होना ही काफी है।

इन दोनों के बीच के अंतर को आसानी से समझने के लिए नीचे दी गई तालिका (ज्ंइसम) को देखें :-

मुख्य अंतर तालिका :-

अंतर का आधार	**सामान्य आशय**	**सामान्य उद्देश्य**
कानूनी धारा	धारा 34 (IPC)/नई संहिता में संबंधित धारा	धारा 149 (IPC)/नई संहिता में संबंधित धारा
न्यूनतम सदस्य	कम से कम 2 लोग होने चाहिए।	कम से कम 5 लोग होने चाहिए।
पूर्व-योजना	इसमें दिमागों का मिलना और पहले से बनी योजना जरूरी है।	इसमें पहले से योजना बनाना जरूरी नहीं है।
सक्रिय भागीदारी	घटना के समय व्यक्ति की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए।	केवल उस गैर-कानूनी समूह का सदस्य होना ही काफी है।
अपराध का	यह केवल एक नियम है, अपने आप में कोई अलग अपराध नहीं है।	यह अपने आप में एक विशिष्ट (अलग) अपराध बनाता है।

❖ **सामान्य आशय को विस्तार से समझें :-**

☞ **दिमागों का मिलन :-** इसका मतलब है कि अपराध करने वाले सभी लोगों को पता था कि क्या होने वाला है और वे सब इसके लिए सहमत थे।

☞ **पूर्व-निर्धारित योजना :-** घटना से पहले या घटना के वक्त ही अचानक सबके मन में एक जैसा प्लान बनता है।

☞ **उदाहरण :-** यदि 'A' और 'B' मिलकर 'C' को पीटने की योजना बनाते हैं। 'A' रास्ता रोकता है और 'B' डंडे से मारता है। यहाँ दोनों का आशय (Intention) एक था, इसलिए दोनों बराबर के दोषी होंगे।

❖ **सामान्य उद्देश्य को विस्तार से समझें :-**

☞ **गैर-कानूनी मंडली :-** इसके लिए 5 या उससे ज्यादा लोगों का समूह होना जरूरी है, जिसका मकसद कोई गैर-कानूनी काम करना हो।

☞ **सक्रिय होना जरूरी नहीं :-** अगर आप उस भीड़ का हिस्सा हैं और भीड़ में से कोई अपराध कर देता है, तो आप भी दोषी माने जाएंगे, भले ही आपने खुद हाथ न उठाया हो।

☞ **उदाहरण :-** 10 लोगों की भीड़ किसी दुकान को तोड़ने जाती है। उनमें से 2 लोग दुकान में आग लगा देते हैं। बाकी 8 लोगों को भले ही नहीं पता था कि आग लगाई जाएगी, लेकिन वे उस भीड़ का हिस्सा थे, इसलिए वे भी दोषी होंगे।

शिवानंद गिरि

(अधिवक्ता)

Ph.- 9308454485

7004408851

E-mail :-shivanandgiri5@gmail.com

✯ रिट कितने प्रकार के होते हैं?

भारतीय संविधान के तहत मुख्य रूप से पाँच प्रकार की रिट (राइट्स) होती हैं, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं और अदालतों द्वारा जारी किए गए आदेश हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण (हबीज कॉरपस), परमादेश (मैंडेमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), उत्प्रेषण (सर्टियोरारी) और अधिकार पृच्छा (क्वो-वारंटो). ये रिट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करती हैं.

पाँच मुख्य प्रकार की रिटें :-

☞ **बंदी प्रत्यक्षीकरण (हबीज कॉरपस):-** किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेने से बचाने के लिए, यह आदेश देता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाए ताकि हिरासत की वैधता की जाँच हो सके.

☞ **परमादेश (मैंडेमस) :-** यह एक सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देता है, जब वह ऐसा करने में विफल रहता है.

☞ **प्रतिषेध (प्रोहिबिशन) :-** निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है.

☞ **उत्प्रेषण (सर्टियोरारी) :-** निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के अवैध या गलत आदेश को रद्द करने या मामले को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।

☞ **अधिकार पृच्छा (क्वो-वारंटो) :-** किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारण किए गए सार्वजनिक पद को चुनौती देने के लिए जारी किया जाता है, यह पूछता है कि 'किस अधिकार से?'

❖ **अतिरिक्त जानकारी :-**

☞ **अनुच्छेद 32 (संविधान) :-** सुप्रीम कोर्ट को इन रिटों को जारी करने का अधिकार देता है, जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है।

☞ **अनुच्छेद 226 (संविधान) :-** उच्च न्यायालयों को मौलिक और कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ये रिट जारी करने का अधिकार देता है।

बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित
बुद्ध मार्ग, पटना- 800001
राज्य के किसान भाईयों एवं बैंक के सभी सदस्यों को
80वाँ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।
भूमि विकास बैंक भवन
LAND DEVELOPMENT BANK, BUILDING
स्वतंत्रता दिवस
की
हार्दिक शुभकामनाए
श्रीमती ममता सिंह
अध्यक्ष

BASUDEB CHATTERJEE SMRITI FOUNDATION
80 वें वर्ष
स्वतंत्रता दिवस
के 80वें वर्ष पर
सभी देशवासियों को मेरी
हार्दिक शुभकामनाएँ।
-: निवेदक:-
राजीब चटर्जी
अध्यक्ष
बासुदेव चटर्जी स्मृति फाउंडेशन

जन-जन की आवाज है केवल सच
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका
Kewalsachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ
Kewalsach news
खबर वहीं, जो केवल सच हो
Mob.: 9431073769, 9308815605
केवल सच TIMES
आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं
को सपोर्ट करें
आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा
BHIM UPI
G Pay
Paytm
www.kewalsach.com
www.kewalsachlive.in
-: सम्पर्क करें :-
पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Dispersing Happiness

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008